सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2015 की संख्या 55

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2015 की संख्या 55

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.3	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा	1.4	1
बजट और व्यय नियंत्रण	1.5	8
अध्याय II : दूरसंचार विभाग		
गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क का समंजन	2.1	9
3.3–3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	2.2	15
ट्राई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को खोले जाने पर अनियमित व्यय	2.3	18
अध्याय III : डाक विभाग		
सेनवैट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण सेवा कर का अधिक भुगतान	3.1	25
बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय	3.2	26
किराये का गैर दावा	3.3	28
बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान	3.4	29
स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र का कम उपयोग	3.5	30
अध्याय IV : इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अनुबंध प्रबंधन, वेब होस्टिंग तथा एप्लिकेशन डेवलपमंट में कमियाँ	4.1	33
सी–डैक द्वारा पुणे में भवन निर्माण तथा जसोला, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण को प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब	4.2	51
सी–डैक प्रबंधन के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण नोएडा से भूखण्ड क्रय करने में ₹ 91.78 लाख का परिहार्य भुगतान	4.3	57
सी–डैक पुणे द्वारा रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने में विफलता के कारण ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.4	59
कार्मिक एवं स्थापना प्रकरणों के नियमन में कमियाँ	4.5	62
किराए की जगहों के लिए आंतरिक साज सज्जा का काम पूरा करने में असामान्य देरी के कारण परिहार्य एवं निष्फल किराया व्यय	4.6	67
दण्डात्मक ब्याज का गैर आरोपण	4.7	69

अध्याय V : मंत्रालय के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
भा सं नि लि में सी डी आर आधारित सम्मिलित बिलिंग एवं ग्राहक सेवा सिस्टम	5.1	73
गैर भुगतान के बावजूद भी लीज्ड सेवाओं का विच्छेदन न करना	5.2	80
शास्ति का परिहार्य भुगतान	5.3	81
आई टी सी की बिक्री पर अनावश्यक सेवा कर का दायित्व	5.4	83
टॉवर की शेयरिंग में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	5.5	86
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएँ इकं द्वारा अपने कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता व एल टी सी का अनियमित भुगतान	5.6	88
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	5.7	91
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–(वाणिज्यिक)	5.8	91
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही –(सिविल)	6.1	93
अनुलग्नक		
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	I	97
मैसर्स एयरसेल लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	II	98
मैसर्स रिलाइन्स से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	III	99
मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	IV	100
मैसर्स ट्रैक ऑनलाइन लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	V	101
मैसर्स तुलीप से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण	VI	102
नये खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों पर किए गए व्यय को दर्शाता विवरण	VII	103
बार कोडिड बैग लेबल की अधिप्राप्ति दर्शाने वाला विवरण	VIII	104
वर्ष 2005-06 के दौरान खरीदे गये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत को दर्शाने वाला विवरण	IX	105
पुरानी निविदाओं के विस्तार के कारण अतिरिक्त व्यय के विस्तृत को दर्शाने वाला विवरण	X	106
एस एम एस प्रभार पर किये गये परिहार्य व्यय के विस्तृत को दर्शाने वाला विवरण	XI	108
पाशान भवन परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि को दर्शाता विवरण	XII	109

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक के दौरान सी–डैक पुणे के द्वारा किराये के परिसर पर किये जाने वाले/किये गये के किराये का व्यय दर्शाता विस्तृत विवरण	XIII	110
सी–डैक नोएडा का प्लाट बी-30, सेक्टर 60, नोएडा के लिए किऐ जाने वाले किश्त/ब्याज और वास्तव में किये गये भुगतान की तुलना को दर्शाता विवरण	XIV	111
ब्याज की हानि की गणना दर्शाता विवरण	XV	112
रियाती शुल्क दरों पर विधुत का लाभ न लेने के कारण सी–डैक पुणे द्वारा किये गये परिहार्य अतिरिक्त व्यय को दर्शाता विस्तृत विवरण (पुणे विश्वविद्यालय भवन)	XVI	113
रियायती विधुत शुल्क दरों का लाभ न लेने के कारण सी–डैक पुणे द्वारा किये गये परिहार्य अतिरिक्त व्यय को दर्शाता विस्तृत विवरण (एनएसजी आई टी उद्यान/वेस्टइन्ड केन्द्र)	XVII	115
सी–डैक पुणे के सभी कर्मचारियों को लीज्ड आवास सुविधा का विस्तार देने के कारण हुये अधिक भुगतान को दर्शाता विवरण	XVIII	117
सी–डैक पुणे द्वारा ग्रेच्युटी के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण	XIX	118
सी–डैक पुणे द्वारा कर्मचारियों के ₹ 5000/- प्रतिवर्ष से अधिक किए गए मानदेय भुगतान को दर्शाता विवरण	XX	120
अप्रैल 2013 से अक्तूबर 2014 के दौरान पवन दुग्गल एसोसिएटस् को सी–डैक पुणे द्वारा दिये गये परामर्श प्रभार को दर्शाता विवरण	XXI	122
सरकारी राजस्व को भारत की समेकित निधि में गैर प्रेषण के कारण देय दण्डात्मक ब्याज को दर्शाता विवरण	XXII	127
लीज्ड सर्किट ग्राहकों से तीन साल से अधिक बकाया राशि को दर्शाता विवरण	XXIII	128
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली दर्शाता विवरण	XXIV	129
परिशिष्ट		
सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 के लिए दूरसंचार विभाग, सं मं व सू प्रौ के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति।	I	133
सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 के लिये संचार मंत्रालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सं मं व सू प्रौ) के अन्तर्गत विभागों से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	II	135
शब्दावली		136

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निष्पादन एवं लेन–देन संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो कि 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा वे भी हैं जो कि पूर्व के वर्षों में सज्ञान में आये, किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है। इसमें छः अध्याय हैं। अध्याय I संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्भूत वर्तमान निष्कर्षों/अवलोकनों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ नीचे दिये गये हैं:

अध्याय – II दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क का समंजन

नवम्बर 2012/मार्च 2013 में सम्पन्न 1800 मेगाहर्ट्ज/800 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम के लिये देय नीलामी राशि के विरूद्ध लाइसेंस धारकों, जिनके लाइसेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित एवं निरस्त कर दिये गये थे, द्वारा 2008 में भुगतान किये गये गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ₹ 5476.30 करोड़ के समंजन ने सरकार को उस सीमा तक राजस्व से वंचित किया।

पैराग्राफ 2.1

3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की गैर–नीलामी के कारण राजस्व की हानि

आपरेटरों को प्रशासनिक तौर पर निःशुल्क वर्ष प्रतिवर्ष 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम का लगातार आबंटन/विस्तार करने के परिणामस्वरूप एकमुश्त प्रभारों की गैर–वसूली की वजह से सार्वजनिक कोष में उल्लेखनीय हानि हुई जिसको कि सरकार वसूल सकती थी यदि इन्होंने इसकी नीलामी की होती। यह 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पैक्ट्रम की नीलामी करने के लिये ट्राई की सिफारिश के बावजूद था तथा इसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आशय एवं भावना का भी उल्लंघन किया।

पैराग्राफ 2.2

ट्राई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर अनियमित व्यय

भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार के निर्देशों, अपने ही लीगल डिवीजन तथा विधि, न्याय व कम्पनी मामलों की राय की अनदेखी करते हुये पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2004 तक ₹ 14.12 करोड़ का व्यय किया। भविष्य में व्यय तब तक किया जायेगा जब तक क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत रहेंगे।

पैराग्राफ 2.3

अध्याय–III डाक विभाग

सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के कारण सेवाकर का अधिक भुगतान

सितम्बर 2004 में प्रारम्भ हुये सेनवैट क्रेडिट नियमों ने विनिर्माता अथवा कर योग्य सेवा के सम्भरक को अनुमत किया था कि वे प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अथवा विशिष्ट अंतिम उत्पाद/आउटपुट सेवाओं के विनिर्माण के सम्बंध में भुगतान किये गये शुल्क/सेवा कर का क्रेडिट लें। इस प्रकार उपलब्ध सेनवैट

क्रेडिट का उपयोग किसी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क अथवा आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान के लिये किया जा सकता था।

निदेशक पी एल आई कोलकाता, सी पी एम जी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा दिल्ली 2010 11 से 2013–14 के दौरान पात्र उपयुक्त, सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर व शिक्षा उपकर ₹ 7.52 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 3.1

बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

बैग लेवल डेटा इलेक्ट्रानिकली प्राप्त करने के उद्देश्य से, डा वि ने जून 2012 में अपंजीकृत प्रथम श्रेणी की डाक बैग के लिये बारकोडेड बैग लेबल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। सभी डाक परिमंडलों को अनुदेश दिये गये थे कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन बैग लेबल के लिये आदेश दें। अपेक्षित सॉफ्टवेयर विकसित किये बिना इन बैग लेबल की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप आशयित उद्देश्य की गैर उपलब्धि के अतिरिक्त ₹ 1.71 करोड़ की व्यय अविवेकी हुआ।

पैराग्राफ 3.2

अध्याय–IV इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अनुबंध प्रबंधन, वेब होस्टिंग तथा एप्लिकेशन डेवलपमेंट में कमियां

अनुपयुक्त योजना के कारण डाटा के बेस मैपिंग पर कम्प्यूटर ऐडेड डिजिटल मैपिंग परियोजना में ₹ 14.25 करोड़ की लागत से किया गया व्यय निष्फल रहा। उचित निगरानी की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 12.10 करोड़ के मूल्य के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अप्रचलित हो गये। एन आई सी ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना में भी ₹ 35.20 करोड़ के अप्रयुक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की खरीद पर निष्क्रिय निवेश करने के अतिरिक्त किराया व मेंटिनेंस चार्जेज पर भी ₹ 3.74 करोड़ का अपव्यय किया।

इसके अतिरिक्त एन आई सी के संबंधित उपयोगकर्ता समूहों के बीच समन्वय की कमी के कारण वेंडर द्वारा ई–कोर्ट परियोजना में कार्य आदेश निष्पादित नहीं करने पर एन आई सी ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने में असफल रहा। एन आई सी एन ई टी को इंटरनेट बैंडविथ प्रदान करने के लिये समय पर निविदा जारी नहीं करने के कारण एन आई सी घटती दरों का लाभ लेने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एन आई सी ने बिना सुरक्षा लेखापरीक्षा के 3158 वेबसाइट होस्ट किये। विभिन्न परियोजनाओं के वेबसाइट विकास तथा वेब एप्लिकेशन में भी अनेक कमियां थी।

पैराग्राफ 4.1

सी–डैक द्वारा पुणे में भवन–निर्माण तथा जसोला, नई दिल्ली में कार्यालय–भवन के निर्माण प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब

सी–डैक पुणे द्वारा दोषपूर्ण आयोजन व अविवेकपूर्ण निर्णय भवन–निर्माण के पूर्ण होने में न केवल छः वर्षों से अधिक के विलम्ब में फलित हुआ अपितु लागत में ₹ 66.39 करोड़ की वृद्धि तथा ₹ 47.62 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

इसके अतिरिक्त, सी–डैक दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान करके सितम्बर 2001 में एक प्लॉट पर आधिपत्य लिया था। तथापि, आधिपत्य की तारीख से 14 वर्षों के बाद भी, प्लाट पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था तथा समय–समय पर विस्तार की मांग के लिये डी डी ए को ₹ 6.08 करोड़ का भुगतान भी किया गया था।

पैराग्राफ 4.2

सी–डैक पुणे द्वारा रियायती बिजली टैरिफ प्राप्त करने में विफलता के कारण ₹ 4.78 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस पालिसी 2009 के अनुसार, सी–डैक प्रबन्धन योग्य रियायती बिजली टैरिफ का लाभ प्राप्त करने के लिए कदम उठाने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2014 तक) बिजली प्रभारों में ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य व्यय के साथ ही भविष्य में आवर्ती प्रभाव हुआ।

पैराग्राफ 4.4

कार्मिक व स्थापना मामलों के विनियमन में कमियां

सी–डैक पुणे द्वारा उसकी गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित अपने स्टाफ नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा जी एफ आर तथा एफ आर एवं एस आर के उल्लंघन के परिणामस्वरूप स्वरूप पट्टे पर लिये गये आवास, उपदान, मानदेय आदि पर अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 4.5

भाड़े पर लिये गये आवास के लिये आन्तरिक साज सज्जा पूरा करने में असाधारण विलम्ब के कारण परिहार्य व निष्फल किराया व्यय

ई आर एन ई टी पट्टा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी भाड़े की जगह का उपयोग नहीं कर सका था। एरनेट की इस भूल से ₹ 7.17 करोड़ का निष्फल/परिहार्य व्यय हुआ।

पैराग्राफ 4.6

अध्याय –V मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

भा सं नि लि में सी डी आर पर आधारित संमिलित बिलिंग एवं ग्राहक सेवा प्रणाली

भा सं नि लि ने नई चुनौतियों का सामना करने व राजस्व रिसाव बिन्दुओं को रोकने के लिये सी डी आर आधारित बिलिंग व ग्राहक सेवा समाधान कार्यान्वित किया। भा सं नि लि द्वारा दोषपूर्ण योजना के कारण

₹ 8.80 करोड़ के मैग्नेटिक टेप एमुलेटर की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय, राजस्व आश्वासन व कपटपूर्ण प्रबन्धन प्रणाली का आंशिक कार्यान्वयन तथा आई पी डी आर की बिलिंग में बिल न बनाने/विलम्ब से बनाने पर में परणीत हुआ।

पैराग्राफ 5.1

गैर भुगतान के बावजूद भी पट्टे पर दी गई सेवाओं का गैर–विच्छेदन

पट्टे पर दिया गया परिपथ एक समर्पित लिंक है जो ग्राहक द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिये दो स्थिर स्थानों के बीच दिया जाना है। इंडियन टेलीग्राफ नियम के अनुसार, प्रारम्भ में मांग पत्र द्वारा एक वर्ष का अग्रिम किराया तथा स्थापना प्रभार की वसूली की जानी थी तथा आगे के वर्ष के लिये अग्रिम किराया लेना है। निजी/सरकारी संगठनों से तीन वर्षों से अधिक समय के लिये देयों के गैर भुगतान के बावजूद भी बी एस एन एल द्वारा पट्टे पर दी गई लाइनों व परिपथों को चालू रखने के परिणाम स्वरूप छः दूरसंचार परिमंडल व एक दूरसंचार क्षेत्र में ₹ 223.99 करोड़ के बकाया का संचयन हुआ।

पैराग्राफ 5.2

शास्ति का परिहार्य भुगतान

बी एस एन एल मध्य प्रदेश परिमंडल में अवसंरचना स्थलों के अनुचित रखरखाव के कारण निर्बाध मोबाइल सेवायें प्रदान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप दू वि को ₹ 22.27 करोड़ की शास्ति का भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 5.3

आई टी सी की बिक्री पर अनुचित सेवा कर का दायित्व

बी एस एन एल इंडियन टेलीफोन कार्ड, जिसे केवल जम्मू एवं कश्मीर में बिक्री के लिये बनाया गया था, का निगरानी करने में विफल रहा। यह सेवा कर व उस पर शास्ति के कारण ₹ 5.40 करोड़ की हानि के अतिरिक्त परिहार्य मुकदमेबाजी में फंसने में फलित हुआ।

पैराग्राफ 5.4

नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर सेवायें इंक द्वारा अपने स्टाफ को परियोजना प्रोत्साहन परिवहन भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा एल टी सी का अनियमित भुगतान

नेशनल इनफारमेटिक सेन्टर सर्विसेज इंक (निकसी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अन्तर्गत एक अलाभकारी खण्ड 25 कम्पनी ने ₹ 2.11 करोड़ का परियोजना प्रोत्साहन, ₹ 48.87 लाख का परिवहन भत्ता, ₹ 16.58 लाख का मकान किराया भत्ता व ₹ 1.90 करोड़ की एल टी सी प्रतिपूर्ति अपने अधिकारियों को, जो नेशनल इनफोरमेटिक्स सेन्टर से प्रतिनियुक्ति पर थे, को 2010–11 से 2013–14 के दौरान भुगतान किया जोकि वित्त मंत्रालय/कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के उल्लघंन में था।

पैराग्राफ 5.6

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी), भारत सरकार एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय विभागों और सम्बन्धित संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी) के अधीन विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। सी ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी के (डी पी सी) अधिनियम[1] की धारा 13[2] और 17[3] तथा पीएसयू के लिये धारा 19 के तहत करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरुप लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्याँकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा निर्धारित की जाती है।

1.4 लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा

1.4.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार[4] है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय से रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह देश के सभी

1 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

2 (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन–देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनापत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

3 संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

4 डीओटी का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

उपभोगकर्ताओं के बेतार नियामक उपायों को लागू करने और बेतार संचरण की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

➢ व्यय विश्लेषण

डी ओ टी के 2013-14 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका–1 में दी गई है:

तालिका-1
डी ओ टी के राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व	15879.49	120547.63	17400.92	18902.00	40113.76
व्यय	11127.30	10370.26	8692.16	9273.38	10835.57

(स्रोतः डी ओ टी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

तालिका -2
प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाइसेंस शुल्क	9778.52	10286.43	11790.93	11456.48	14628.47
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	3809.54	3432.47	5192.30	5679.19	6883.67
नीलामी राजस्व	–	106264.73	–	1722.24	18267.18

(स्रोतः 2014-15 के लिए डीओटी का वार्षिक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के एक विश्लेषण ने दर्शाया कि 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान, विभाग की आय में वृद्धि इन वर्षों में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई प्राप्ति के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग का व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ़ा है।

➢ दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रुपरेखा

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रुप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 621.28 मिलियन से बढ़कर 933 मिलियन हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए समग्र वृद्धि की स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है।

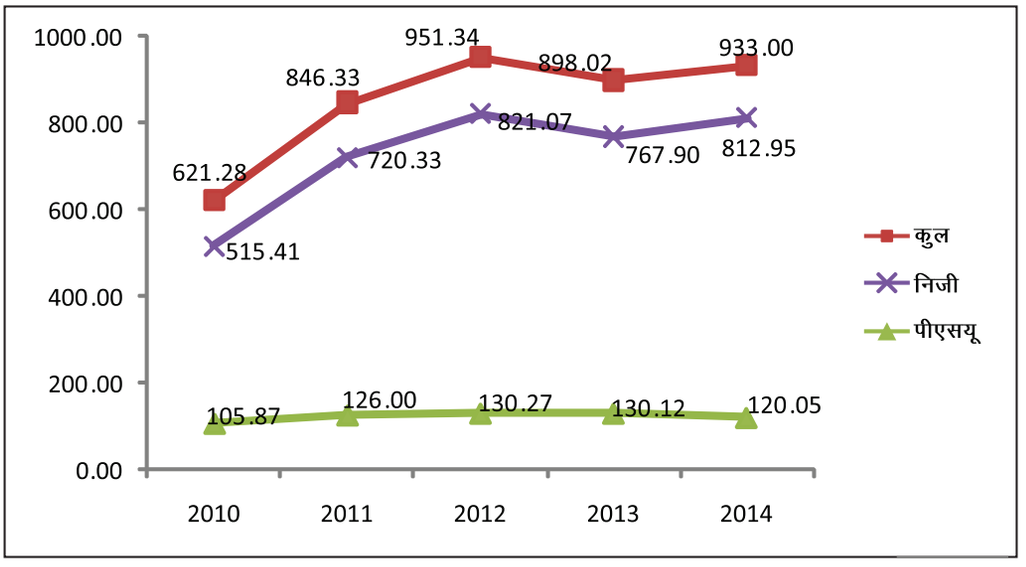
तालिका-3
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	उपभोक्ता (मिलियन में)					टेलीडेंसिटी (प्रतिशत में)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलेस	समग्र	ग्रामीण	शहरी
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96
2013-14	933.00	377.74	555.26	28.49	904.51	75.23	43.96	145.78

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन 2009-10 से 2013-14)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है:

उपभोक्ता आधार में वृद्धि–निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपभोक्ताओ' की सँख्या (मिलियन मे)



(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि निजी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में जो पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरावट का रूख दर्शा रही है, महत्वपूर्ण है।

➢ क्षेत्र का नियामक ढाँचा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

ट्राई की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फारवरी 1997 को दूरसंचार सेवाओं को दरों के निर्धारण/संशोधन सहित सेवाओं को विनियमित करने, जो पूर्व में केन्द्र सरकार में निहित थे, के लिये की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्धेश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान अवसर प्रोत्साहित करे, उपभोक्ताओं के

हितो का संरक्षण करे तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई को अधिकार दिया गया है

- लाईसेंस के नियमों व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- टैरिफ पॉलिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तो तथा सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस के लिये नियम व शर्तों की अनुशंसा करना;
- टैरिफ पॉलिसी की मॉनिटरिंग, वाणिज्यिक तथा अंतःसंयोजन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय;
- काल राउटिंग एवं कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;
- जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में स्वतन्त्र चुनाव एवं समान पहुँच;
- बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न टकरावों का समाधान;
- विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता; तथा
- सेवा प्रदाताओं में पारस्परिक विचार विमर्श तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के पारस्परिक विचार विमर्श के लिए फोरम विकसित करना;

सरकार के दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा मानते हुए इन क्षेत्रों को ट्राई की परिधि में लाया गया। ट्राई के लिए भी अपेक्षित है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण एवं केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर अनुशंसाये दे।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडी सैट)

टी डी सैट की स्थापना एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंस धारक के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए, ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए ट्राई अधिनियम में 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➢ महत्वपूर्ण डी ओ टी इकाईयाँ

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डीनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीतिगत अनुसंधान संस्थान (एजन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

➢ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 01 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड) का गठन किया। यू एस ओ की आवश्यकताओं हेतु संसाधन सार्वभौमिक अभिगम उद्‌गृहण (यू ए एल), जो कि विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी संचालकों द्वारा कमाये गये राजस्व का वर्तमान में एक निश्चित प्रतिशत है, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ फण्ड के पक्ष में प्राप्त धन राशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय–समय पर ऐसी आय को निधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रुप से पूरा करने के उपयोग हेतु जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2014 तक यू एस ओ उद्‌गृहण के रूप में ₹ 58,579.35 करोड़ की राशि दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा एकत्र की गई तथा जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया गया है। विनियोग द्वारा (डी ओ टी) इस राशि में से मात्र ₹ 24,896.49 करोड़, प्राप्त हुए तथा 31 मार्च 2014 तक यू एस ओ फण्ड में जमा किये गये। जिसमें वर्ष 2002-06 के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रुप में भारत संचार निगम लिमिटेड को यू एस ओ एफ के अंतर्गत ग्रामीण कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु 2008-09 में प्रतिपूर्ति हेतु समायोजित किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

1.4.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारतीय डाक नेटवर्क 1.54 लाख से अधिक डाकघरों के साथ विश्व में सबसे बड़ा है तथा यह देश के दूरस्थ स्थानों तक फैला है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, वहीं विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेषण, बैंकिग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेन्शन भोगियों को पेन्शन एवं पारिवारिक पेन्शन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचरियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेन्शन के संवितरण में भी संलिप्त है। अभी हाल ही में, डाक विभाग ने सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनाओं की जिम्मेदारी ली है।

वित्तीय प्रदर्शन

डाक विभाग के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका-4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4

डी ओ पी की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

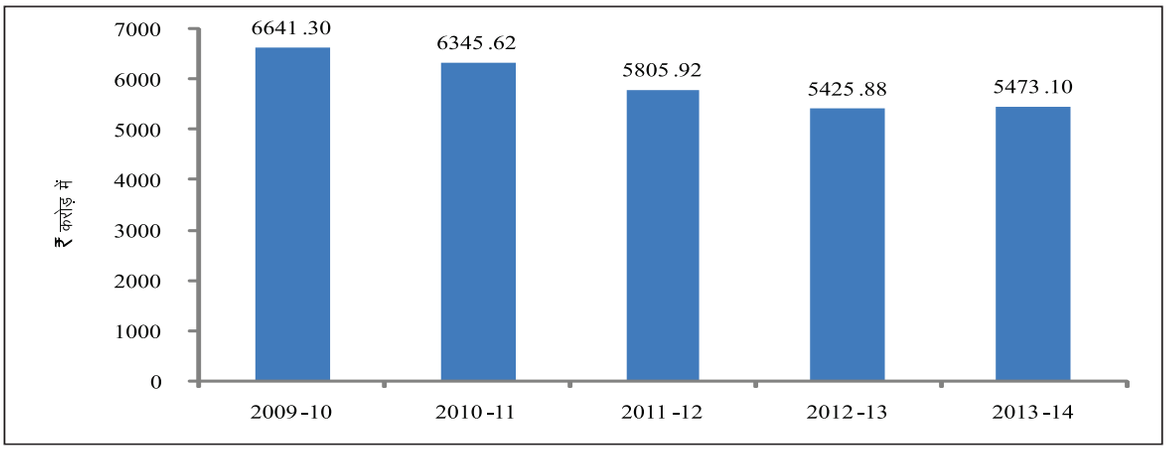
वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	वसूलियाँ	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62
2011-12	7899.35	458.64	14163.91	5805.92
2012-13	9366.50	688.77	15481.15	5425.88
2013-14	10730.42	593.19	16796.71	5473.10

(स्रोतः डी ओ पी के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के विनियोजन लेखे)

विभाग की कमाईयाँ "वसूलियों" एवं "राजस्व प्राप्तियों" के रुप में है।

2013-14 में डाक सेवाओं [5] पर ₹ 5,473.10 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा के घाटे का मुख्य कारण एल टी सी पर अवकाश नकदीकरण, एम ए सी पी, वेतन में सामान्य वृद्धि, महँगाई भत्ते में वृद्धि, आउटर्सोसिंग एवं पेन्शन प्रभार इत्यादि के कारण कार्य व्यय में वृद्धि को ठहराया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की डाक सेवाओं में घाटे को तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:

डाक सेवाओं पर घाटा



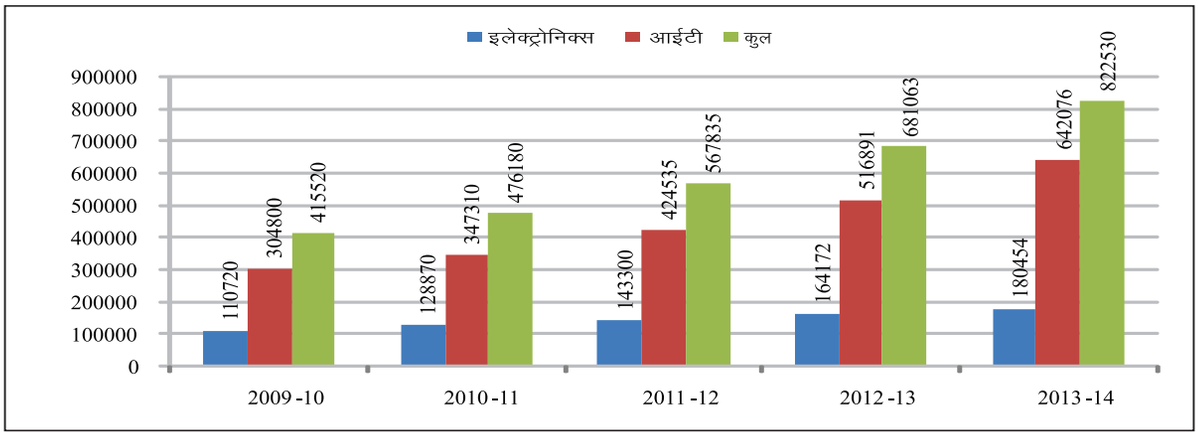
1.4.3 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

डी ई आई टी वाई, एम ओ सी एण्ड आई टी के अन्तर्गत एक विभाग है, जो कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में संक्रमण हेतु इंजन के रूप में भारत का ई–विकास करना है।

भारतीय आई टी उद्योग भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में उल्लेखनीय रूप से योगदान कर रहा है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी–आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि का खाका नीचे चार्ट में दिया गया है:

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी उत्पादन

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन)

5 घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {(₹ 10730.42 + ₹ 593.19) - ₹16796.71}

इलेक्ट्रानिक्स व आई टी–आई टी ई एस उद्योग की समग्र वृद्धि के लिये मुख्य कारण, जैसा विभाग द्वारा माना गया सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं में प्रासंगिक रूप से उच्चतर वृद्धि है जो व्यापक रूप से निर्यात संचालित व इलेक्ट्रॉनिक व आई टी सेक्टर पर भी प्रभुत्व रखती हैं। विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान इस उद्योग का कुल उत्पादन ₹ 9,33,550 करोड़ विचारित है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर व आई टी–आई टी ई एस का उत्पादन क्रमशः ₹ 1,90,366 करोड़ व ₹ 7,43,184 करोड़ था।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु डी ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रुप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान डी ई आई टी वाई को प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष किया गया व्यय, तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5

डी ई आई टी वाई से संबंधित अनुदान के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान राशि	कुल व्यय
2009-10	2582	1697
2010-11	3719	3129
2011-12	3048	2074
2012-13	3051	1903
2013-14	3052	2166
कुल	15452	10969

(स्रोतः डी ई आई टी वाई के वर्ष 2009-10 *से* 2013-14 *के विनियोजन लेखे)*

डी ई आई टी वाई के अधीन पाँच सगठन[6] और सात स्वायत्त सोसायटी[7] के अतिरिक्त दो सम्बन्द्ध कार्यालय–मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) हैं।

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

वर्ष 1980 में स्थापित एस टी क्यू सी, अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये डी ई आई टी वाई मैंडेट के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई–शासन की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (अ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय

6 प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सी सी ए), साइबर अपीलीय प्राधिकरण (सी ए टी), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट–डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सी ई आर टी) और रजिस्ट्री में

7 कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण एवं शोध (ई आर एन ई टी), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी–डैक), इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी–मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी आई) एवं इलेक्ट्रानिकी एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ईएससी)

क्षेत्र योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत् श्रंखला प्रदान करता है।

1.5 बजट और व्यय नियंत्रण

डी ओ टी, डी ओ पी तथा डी ई आई टी वाई के सम्बन्ध में 2013-14 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश आगामी तालिका-6 में दिया गया है:

तालिका-6

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन तीन विभागों को दिये गये अनुदान (वोटेड एवं चार्ज्ड) तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय / विभाग	अनुदान / विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत / (+) आधिक्य
1.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3052.00	2166.27	(-) 885.73
2.	डाक विभाग	17310.37	17065.68	(-) 244.69
3.	दूरसंचार विभाग	15139.44	10835.57	(-) 4303.87

(स्रोत: 2013-14 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

अध्याय-II
दूरसंचार विभाग

2.1 गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क का समंजन

यूनिटेक ग्रुप ऑफ कम्पनीज, मैसर्स वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल), मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड (आई सी एल) और मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड (एस एस टी एल) द्वारा जनवरी 2008 में यू ए एस लाइसेंस जिनको कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में असंवैधानिक घोषित एवं निरस्त कर दिया गया था, को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गये गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क ₹ 5476.30 करोड़ का नवम्बर 2012/मार्च 2013 में सम्पन्न निविदा में 1800 मेगा हर्टज़/800 मेगा हर्टज़ स्पेक्ट्रम के लिए देय नीलामी राशि के विरूद्व समंजन (सेट–ऑफ) ने सरकार को उस सीमा तक राजस्व से वंचित किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में कहा कि तत्कालीन 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में डी ओ टी के अधिकारियों द्वारा सितम्बर 2007 और मार्च 2008 के मध्य किये गये कार्य पूर्ण रूप से स्वच्छन्द, अनियमित एवं लोकहित के प्रतिकूल थे। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री दर्शाती है कि तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जनता के राजकोश की कीमत पर कुछ कम्पनियों का पक्षपात करना चाहते थे।' न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि '10 जनवरी 2008 को जारी की गई दो प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसरण में निजी प्रतिवादियों को 10 जनवरी 2008 को या उसके पश्चात आवंटित लाइसेंसों तथा तत्पश्चात् लाइसेंस धारकों को प्रदत्त स्पेक्ट्रम असंवैधानिक एवं निरस्त घोषित किये जाते हैं'।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप 2008 के दौरान नौ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं[1] (टी एस पी) को जारी किये गये 122 यू ए एस लाइसेंस, जिनमें यूनिटेक ग्रुप के 22 लाइसेंस, मैसर्स वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल) के 21 लाइसेंस, मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के नौ लाइसेंस और मैसर्स सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज (एस एस टी एल) के 21 लाइसेंस शामिल थे, सहित लाइसेंस धारियों को तत्पश्चात् आवंटित स्पेक्ट्रम अवैध एवं निरस्त घोषित कर दिये गये थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने छह प्रतिवादियों पर यह कहते हुये दण्ड़ भी आरोपित किया की 'प्रतिवादी संख्या [2] 2, 3 और 9 जो कि डी ओ टी के यू एएस लाइसेंस प्रदान करने एवं 2जी बैंड के स्पेक्ट्रम आवंटन करने के पूर्णतया मनमाने एवं असंवैधानिक कृत्य द्वारा जनता के राजकोष की कीमत पर लाभान्वित हुये थे तथा इक्विटी के नवीन निषेचन या इक्विटी के नये हस्तांतरण के नाम पर कई हजार करोड़ के अपने हिस्सों को बेच दिया था, प्रत्येक ₹ 5 करोड़ दंड का भुगतान करेगें। प्रतिवादी संख्या[3] 4, 6, 7 और 10 प्रत्येक ₹ 50 लाख का भुगतान करेगें क्योंकि वे भी डी ओ टी द्वारा अपनाए गए पूर्णतया मनमाने

1 मेंसर्स एलाइन्ज इन्फ्राटैक प्राइवेट लि०, मेसर्स इतिस्लाट डी. बी. टेलीकॉम प्राईवेट लि०, मेसर्स आईडिया सेल्युलर लि०, मेसर्स लूप टेलीकॉम लि०, मेसर्स एस टेल प्राईवेट लि०, मेसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि०, मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि०, मेसर्स यूनिटेक वायरलेस प्राईवेट लि०, मेसर्स वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लि०

2 मैसर्स इतिस्लात डीबी टेलीकॉम प्राईवेट लि०, मेसर्स यूनिटेक वायरलेस ग्रुप एवं मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि०

3 मेसर्स लूप टेलीकॉम प्राईवेट लि०, मेसर्स एस टेल लि०, मेसर्स एलाइन्ज इन्फ्राटैक (प्राइवेट) लि० एवं मेसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि०

और असंवैधानिक कृत्य द्वारा यू ए एस लाइसेंस प्रदान करने और 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन से लाभान्वित हो चुके थे।' माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी निर्देशित किया था कि ट्राई 22 सेवा क्षेत्रों में नीलामी द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु नई संस्तुतियाँ करेगा जैसा कि 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुआ था। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि 'केन्द्र सरकार ट्राई की संस्तुतियों पर विचार करेगी और अगले एक माह के भीतर उचित निर्णय लेगी तथा नये लाइसेंस नीलामी के द्वारा प्रदान किये जायेंगें'।

तद्नुसार डी ओ टी ने ट्राई की संस्तुतियाँ माँगी और उनकी संस्तुतियों के आधार पर (अप्रैल 2012) 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिये 28 सितम्बर 2012 को एक आवेदन आमंत्रण करने की सूचना (एन आई ए) जारी की गयी। एन आई ए का उपनियम 3.2 (i) निर्धारित करता था कि कम्पनी/लाइसेंस धारक जिनके लाइसेंस उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार खारिज किये जाने थे 'नये प्रवेशी' माने जायेंगे और उन्हें डीओटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया और यूनिफाइड लाइसेंस (एसेस सेवा) प्राप्त करने के लिये निर्धारित दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। 18 सितम्बर 2012 को जारी प्रश्नों एवं प्रत्युत्तरों में डी ओ टी ने, नीलामी द्वारा 1800 मेगाहर्ट्ज़ एवं 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में प्रस्तावित स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में, इंगित किया था कि लाईसेंस धारको के द्वारा, जिनके कि लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए थे, भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क का देय नीलामी भुगतान के विरूद्ध समायोजन नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि खारिज लाइसेंस धारक (मैसर्स वी टी एल) ने डी ओ टी को 2008 में नीलामी मूल्य के विरूद्व एकमुश्त भुगतान किये गये प्रवेश शुल्क के समायोजन के लिये अभ्यावेदन (05 अक्टूवर 2012) प्रस्तुत किया क्योंकि उन्होनें दावा किया कि उनका लाइसेंस उनकी किसी गलती के बगैर निरस्त किया गया था। लाइसेंस धारक के अनुरोध के आधार पर डीओटी द्वारा मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की बैठक के लिए 06 अक्टूबर 2012 को एक नोट तैयार किया और उसे ईजीओएम की बैठक के समक्ष 08 अक्टूबर 2012 को प्रस्तुत किया गया। बैठक के मिनट्स 10 अक्टूबर 2012 को परिचालित किए गए, जिसमें यह कहा गया कि यद्यपि 'ई जी ओ एम ने, समान राहत के सिद्धांत पर, अनुशंसा की है कि इस नीलामी में स्पेक्ट्रम विजित करने की स्थिति मे केवल बयाना जमा राशि (ईएमडी) तथा देय भुगतान के विरूद्ध समंजन (सेट–आफ) की अनुमति दी जा सकती है इस प्रकार के समंजन की कुल धनराशि इकाई द्वारा उसके उन सभी लाईसेंसों, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किए जा चुके है, के लिए भुगतान किए गए सकल प्रवेश शुल्क से सीमित होगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।'

इसके अतिरिक्त डी ओ टी ने एन आई ए पर प्रश्नों एवं प्रत्युत्तरों में स्पष्ट किया (12 अक्टूबर 2012) कि यदि लाइसेंस धारक के बिना किसी दोष के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा लाईसेंस निरस्त किया गया था तब प्रस्तावित नीलामी में स्पेक्ट्रम पाने की स्थिति में समान राहत के सिद्वान्त पर बयाना जमा राशि (ई एम डी) एवं देय भुगतान के विरूद्व समंजन स्वीकृत किया जायेगा। हालांकि यह पाया गया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री (ई जी ओ एम के सदस्यों में से एक) के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार, 08 अक्टूबर 2012 की बैठक में इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। उपरोक्त प्रकरण पुनः विचारित किया गया एवं अंततः 18 अक्टूबर 2012 को ई जी ओ एम की बैठक मे अनुमोदित हुआ।

नवम्बर 2012/मार्च 2013 में आयोजित 1800 मेगाहर्ट्ज़/800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच मार्च–अप्रैल 2013 में प्रकट हुआ कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ में स्पेक्ट्रम हेतु नवम्बर 2012 में आयोजित नीलामी में पाँच बोलीदाताओं (मैसर्स वीटीएल, मैसर्स आई सी एल, मैसर्स टी सी एस पी एल, मैसर्स भारती ऐयरटेल एवं मैसर्स वोडाफोन) ने भाग लिया तथा 800 मेगाहर्ट्ज़ में स्पेक्ट्रम हेतु मार्च 2013 में आयोजित नीलामी में एक बोलीदाता (मैसर्स एस एस टी एल) ने भाग लिया। इन छह बोली दाताओं में तीन बोली दाता– मैसर्स वी टी एल (21 लाइसेंस), मैसर्स आई सी एल (9 लाइसेंस) और मैसर्स एस एस टी एल (21 लाइसेंस) वह टी एस पी थे जिनका लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। जबकि मैसर्स भारती एयरटेल और मैसर्स वोडाफोन मौजूदा आपरेटर थे, मैसर्स टेलीविंग कम्यूनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (टी सी एस पी एल) एक नया प्रवेशी था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मैसर्स वी टी एल, मैसर्स आई सी एल, मैसर्स टी सी एस पी एल[4] और मैसर्स एस एस टी एल को नवम्बर 2012/मार्च 2013 में देय नीलामी फीस के विरूद्व ₹ 5476.30 करोड़[5] का समंजन दिया गया। लेखापरीक्षा के कथन निम्न हैं:

- यू ए एस लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के अनुसार लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क एक गैर वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क था। इसके अतिरिक्त, डी ओ टी की शंका 'क्या लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क की वापसी की आवश्यकता है जैसा कि लाइसेंस धारकों द्वारा मांग की जा रही है?' पर मांगी गई विधिक सलाह के अपने प्रत्युत्तर में भारत के एटॉर्नी जनरल ने कहा (अगस्त 2012) कि इस चरण में लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क की वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

- एन आई ए ने निर्धारित किया कि कम्पनियाँ/लाईसेंस धारक, जिनके लाईसेंस उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खारिज किए जाने थे, एक 'नया प्रवेशी' माने जाएँगे। इसका तात्पर्य था कि उनको पूरी निविदा फीस, उनके खारिज लाईसेंसों हेतु भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क से किसी भी प्रकार से न जोड़ते हुए, जमा करनी थी।

- इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा नौ आपरेटरों के 122 लाइसेंसों को निरस्त करते समय लाइसेंस धारकों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। परन्तु डी ओ टी ने ऑपरेटरों की दलील पर, कि बिना उनकी किसी गलती के उनके लाईसेंस निरस्त किए गए थे, खारिज लाईसेंस धारको की दो श्रेणियाँ बना दी – वह लाईसेंस धारक जिनके लाईसेंस उनकी गलती के कारण निरस्त किए गए थे और वह लाईसेंस धारक जिनके लाईसेंस उनकी बिना किसी गलती के खारिज किए गए थे, और समान राहत के सिद्धांत पर समंजन को स्वीकृति किया।

- डी ओ टी ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई यथोचित परिश्रम भी नहीं किया कि क्या इन कम्पनियों का आचरण वास्तव में निर्दोष था और उनके लाइसेंसों के निरस्तीकरण के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था जो उन पर लागू होता हो। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने पाया कि

4 मैसर्स टी सी एस पी एल माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त टेलीनॉर द्वारा फरवरी 2012 में भारत में निगमित एक कम्पनी थी, पूर्व में टेलीनॉर ने 2008 में यूनिटेक गुप ऑफ कम्पनीज़ में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त की थी जिसका लाइसेंस भी खारिज कर दिया गया था।

5 मैसर्स वीडियोकॉन– ₹ 1506.82 करोड़, मैसर्स आईडिया– ₹ 684.59 करोड़, मैसर्स टी सी एस पी एल– ₹1658.57 करोड़ और मैसर्स एस एस टी एल– ₹ 162.32 करोड़

खारिज लाइसेंस धारकों के समंजन हेतु अनुरोध को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये आधार के बिना किसी प्रमाणीकरण के स्वीकार कर लिया गया विशेषकर तब जब कि लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर निरस्त हो चुके थे।

✓ भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 में भी यह इंगित किया गया था कि वी टी एल और यूनीटेक प्रारम्भ से ही यू ए एस लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अयोग्य थे।

✓ जहाँ तक मैसर्स एस एस टी एल का संबध है, एटार्नी जनरल ने अपनी विधिक राय में कहा था[6] (अगस्त 2012) कि एस एस टी एल आवेदन की तिथि पर अयोग्य थी क्योंकि कम्पनी के पास आवश्यक परिलब्धियाँ नहीं थी।

ई जी ओ एम को प्रस्तुत 06 अक्टूबर 2012 को तैयार किए गए नोट में वी टी एल एवं एस एस टी एल के बारे में उपरोक्त तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था।

- मैसर्स टी सी एस पी एल ने डी ओ टी को मैसर्स यूनीटेक द्वारा 22 लाईसेंसों को 2008 में प्राप्त करने हेतु, जिनको कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, भुगतान किए गए एक मुश्त प्रवेश शुल्क ₹ 1658.57 करोड के समंजन हेतु निवेदन किया (अक्टूबर 2012)। 23 फरवरी 2013 को डी ओ टी द्वारा निर्णय लिया गया था कि टी सी एस पी एल को गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का समंजन इस आधार पर कि समंजन केवल निविदा में भाग लेने वाले खारिज लाईसेंस धारको को ही स्वीकृत किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा और चूंकि मैसर्स टी सी एस पी एल एक खारिज लाईसेंस धारक नहीं था, यूनीटेक (खारिज लाईसेंस धारक) द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क का टी सी एस पी एल (भाग लेने वाली इकाई) द्वारा देय भुगतान के विरूद्ध समंजन ई जी ओ एम के अनुमोदन के अनुरूप नहीं था। 05 मार्च 2013 को टी सी एस पी एल ने पुनः डी ओ टी से निवेदन किया कि यद्यपि वे अलग इकाई थे, उनके विरूद्ध देय भुगतान को यूनीटेक द्वारा भुगतान किये गये एक मुश्त प्रवेश फीस से डी ओ टी द्वारा समायोजित करना चाहिए। उसी तिथि पर (यानि 05 मार्च 2013) ई जी ओ एम के लिए एक नोट तैयार किया गया जिसको कि 06 मार्च 2013 को हुई ई जी ओ एम की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

➢ लेखापरीक्षा ने देखा कि ई जी ओ एम को प्रस्तुत 05 मार्च 2013 को तैयार अनुपूरक नोट यूनीटेक ग्रुप द्वारा अपने आवेदन को प्रस्तुत करते समय महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने ओर तथ्यों के मिथ्या निरूपण इत्यादि को सम्मिलित नहीं करता था हालांकि यह सी एण्ड ए जी द्वारा 2010-11 के प्रतिवेदन सख्या 19 में उल्लेखित किए जा चुके थे और डी ओ टी का निर्णय भी कि टी सी एस पी एल को गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का समंजन स्वीकृत नहीं था। इसके अतिरिक्त मा0 भारत के उच्चतम न्यायालय के यू ए एस लाइसेंस के निरस्तीकरण पर निर्णय (02 फरवरी 2012) के काफी समय पश्चात केवल 24 फरवरी 2012 को टी सी एस पी एल निगमित किया गया था।

6 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 2010 की 10660 में आई ए संख्या 2011 की 27 के फॉर्म में सेन्टर फॉर पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन तथा अन्य से प्राप्त शिकायत के संबध में।

यह इंगित किए जाने पर डी ओ टी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि,

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नीतिगत मामलों में टिप्पणी और आपत्ति नहीं कर सकते हैं।
- जहाँ तक मैसर्स यूनिटेक वायरलेस से सम्बन्धित आपराधिक उत्तरदायित्वों का मामला है, प्रकरण विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित है और इसको स्थापित किए बगैर सिविल एक्शन लेने का कोई विधिक आधार नहीं है। इसके अलावा, अपने आदेश के क्रियात्मक भाग में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपरेटरों को संचालन जारी रखने एवं स्पेक्ट्रम हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की स्वीकृति देते समय ऑपरेटरों के मध्य ऐसा कोई विभेद नहीं किया था।
- समंजन की अनुमति प्रवेश शुल्क वापसी की प्रकृति की नहीं थी तथा उन किसी भी निरस्त लाइसेंस धारकों को नहीं दी गई थी जिन्होनें नीलामी में भाग नहीं लिया और स्पेक्ट्रम नहीं पाया।
- समंजन प्रदान करने की अनुमति का निर्णय ई जी एम ओ एम द्वारा हिस्सेदारों के विभिन्न अभ्यावेदनों एवं प्रस्तुतियों के आलोक में समान राहत के सिद्वान्त के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया था।
- समंजन पूर्ण अप फ्रंट भुगतान के रूप में लिया गया था और किसी भी सेट ऑफ को भविष्य की किश्तों के विरूद्ध आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी।
- डी ओ टी द्वारा उस समय प्रकरण पर विद्यमान नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार टेलीनॉर समूह का अनुरोध माना नहीं गया था तथा इसलिए सक्षम प्रधिकारी द्वारा प्रकरण को ई जी ओ एम को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया एवं ई जी ओ एम द्वारा 06 मार्च 2013 को लिया गया समंजन की अनुमति का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय था।
- जहाँ तक सी ए जी के अपने 2010-11 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 में 'अपात्र आवेदकों को यू एस लाइसेंस निर्गमन' से सम्बन्धित प्रेक्षणों का विषय है, वीटीएल को उसके 21 यू ए एस लाइसेंस समाप्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रकरण की जाँच समय समय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं विधि व न्याय मंत्रालय से परामर्श कर की गयी थी तथा आवेदन की तिथि पर कम्पनी की पात्रता के प्रकरण पर निर्णय अभी भी लम्बित है।
- मार्च 2014 में, डी ओ टी ने पुनः अपने पूर्व दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि ड्राफ्ट आडिट अनुच्छेदों में सम्मिलित मुद्दों को जनवरी 2014 में ई जी ओ एम को सन्दर्भित किया गया था जिसने तब डी ओ टी को सरकार के निर्णय की युक्ति एवं तथ्यों से सी एण्ड ए जी को अवगत् करने हेतु निर्देशित किया था। आगे यह कहा गया कि ई जी ओ एम द्वारा समंजन पर विचार तथा स्वीकृति इस तथ्य के दृष्टिगत दी गयी थी कि टी एस पी द्वारा किया गया प्रवेश शुल्क भुगतान 20 वर्ष की अवधि हेतु था। जहाँ एक ओर, टी एस पी से लाइसेंस के संचालन की अवधि (2008-12) हेतु आनुपातिक भुगतान कर दिए जाने की अपेक्षा की जा

सकती थी, वहीं दूसरी ओर शेष अवधि की आनुपातिक कुल राशि पर ब्याज सहित वापसी का दावा भी किया जा सकता था। डी ओ टी ने एक बार फिर कहा कि इन सभी निर्णयों में नीतिगत एवं वैद्यानिक प्रकरण समाहित थे, जो कि लेखापरीक्षा के प्राधिकार से परे थे।

डीओटी के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

- दरअसल लेखापरीक्षा ने सरकार की नीति पर प्रश्न नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने ई जी ओ एम को प्रस्तुत की गई सूचनाओं की अपूर्णता तथा अपर्याप्तता पर टिप्पणी की है।

- डी ओ टी द्वारा वीटीएल एवं यूनीटेक ग्रुप को यू ए एस लाइसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर उनकी पात्रता के संबंध में निर्गत कारण–बताओ नोटिस पर निर्णय, ई जी ओ एम को समंजन के लिए नोट प्रस्तुत करने के समय डी ओ टी के पास लम्बित था। डी ओ टी द्वारा इस तथ्य को भी अपने नोट में ई जी ओ एम के संज्ञान में नहीं लाया गया था। इसके अतिरिक्त डी ओ टी को मैसर्स यूनिटेक वायरलैस के अपराधिक उत्तरदायित्वों के प्रकरणों के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने की जानकारी के बावजूद डी ओ टी न तो इसे अपने नोट में ई जी ओ एम के संज्ञान में लाया न ही इन प्रकारणो के निर्णीत होने तक की प्रतीक्षा की और मैसर्स टी सी एस पी एल द्वारा देय नीलामी मूल्य के विरूद्ध मेसर्स यूनीटेक द्वारा भुगतान किए गए एक–मुश्त प्रवेश शुल्क के समंजन की अनुमति दी।

- चूँकि टी सी एस पी एल एक पृथक विधिक इकाई थी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (02 फरवरी 2012) के पश्चात् निगमित (24 फरवरी 2012) एक नई कम्पनी थी यह किसी अन्य विधिक इकाई द्वारा किए गए भुगतान के विरूद्ध समंजन की पात्र नहीं थी। डी ओ टी ने समंजन के प्रस्ताव को इस आधार पर प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया था, परन्तु बाद में समंजन के अनुरोध को ई जी ओ एम को प्रेषित कर दिया था, जिसको ई जी ओ एम द्वारा 06 मार्च 2013 को अनुमोदित कर दिया गया था।

- चूँकि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ऑपरेटरों द्वारा एक बार देय प्रवेश शुल्क गैर–वापसी योग्य था, डी ओ टी द्वारा कथित शेष अवधि हेतु आनुपातिक धनराशि पर ब्याज सहित वापसी के दावे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

- ई जी ओ एम को गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क के समजंन हेतु नोट तैयार करते समय डी ओ टी द्वारा खारिज लाइसेन्सों से कम्पनियों द्वारा 2008 से कमाए गए ₹ 7741.65 करोड़[7] के राजस्व कमाने का संज्ञान तक नहीं लिया गया था। इस प्रकार से लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स गँवाने पर पारितोषिक पाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि लाइसेन्स के संचालन की अवधि (2008 व 12) हेतु समजंन की अनुमति दिए जाने के कारण कोई प्रवेश शुल्क लाइसेंस धारकों पर आरोपित नहीं किया गया था।

इस प्रकार उन लाईसेंस धारकों द्वारा भुगतान किए गए गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ₹ 5476.30 करोड़ का जिनके लाईसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित एवं खारिज कर दिए गए थे, नवम्बर

7 मैसर्स यूनिटेक– ₹ 3859.89 करोड़; मैसर्स एस एस टी एल– ₹ 1833.43 करोड़; मैसर्स आई सी एल– ₹ 1292.33 करोड़; मैसर्स वी टी एल–₹ 756 करोड; कुल–₹ 7741.65 करोड

2012/मार्च 2013 में 1800 मेगाहर्ट्ज़/800 मेगाहर्ट्ज़ में स्पेक्ट्रम हेतु देय नीलामी मूल्य के विरूद्ध समंजन अनुपयुक्त था और उस सीमा तक सरकार राजस्व से वंचित रही।

2.2 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सिफारिश की थी (2006) कि जिन ऑपरेटरों के पास 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पैक्ट्रम हैं उन्हें परिमंडल आधारित सेवा क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का एक विकल्प दिया जाये तथा आपरेटरों को 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम की नीलामी मूल्य के बराबर एक बार के स्पैक्ट्रम अधिग्रहण फीस का अग्रिम भुगतान करना चाहिये। सितम्बर 2006 व जुलाई 2008 में ट्राई द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद, दू वि ने 3.3 गीगा हर्टज बैंड में बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम का विस्तार/आबंटन जारी रखा तथा 2010 में बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम की नीलामी के पांच वर्षों के बाद तक भी 3.3 गीगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं की। 3.3 गीगा हर्ट्ज में बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम की नीलामी नहीं की जाने से सरकार को राजस्व की हानि हुई।

बी डब्ल्यू ए सेवाओं के लिये सभी आपरेटरों के मध्य लेवल प्लेइंग फील्ड कायम रखने के उद्देश्य से, ट्राई ने सिफारिश की थी (सितम्बर 2006) कि जिन ऑपरेटरों के पास 3.3.3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है उन्हें परिमंडल आधारित सेवा क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का विकल्प दिया जाना चाहिये। ऐसा करने में, इन आपरेटरों के लिए आवश्यक होगा कि वे रोल आउट तथा वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभारों से सम्बन्धित नई शर्तों को स्वीकार करेंगे, एक समय की स्पेक्ट्रम अधिग्रहण फीस का अग्रिम भुगतान करेंगे तथा परिमंडल स्तर पर प्रचालन शुरू करेंगे।

ट्राई ने 2.3-2.4 गीगा हर्ट्ज, 2.5-2.6 गीगा हर्ट्ज तथा 3.3-3.6 गीगा हर्ट्ज बैंड के लिये आबंटन व कीमत निर्धारण पर अपनी सिफारिशों (जुलाई 2008) में दोहराया था कि सभी सेवा सम्भरक, जिनके पास 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है, से तुरंत परिमंडल स्तर प्रचालन में स्थान्नतरण करने को कहा जाये। प्राधिकरण ने यह भी महसूस किया कि 3.3-3.6 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती हुई बेतार प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन, जो कि समय की मांग थी, के द्वारा स्थिर बॉडबैड़ की वृद्धि को बढ़ाने में हो सकता था और सिफारिश की कि

- '3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में, पहले से ही 6-7 सेवा सम्भरक हैं। ये सेवा सम्भरक एम सी डब्ल्यू[8] फारमूला पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान कर रहे हैं। दू वि की डब्ल्यू पी सी यूनिट के अनुसार, 3.3-3.4 गीगा हर्टज बैंड में 49-49 मेगार्हट्ज स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। तथापि, परिमंडल स्तर के लिये स्थानान्तरण के बाद, बड़ी संख्या में सेवा क्षेत्र होंगे जहां स्पेक्ट्रम नये प्रवेशकों को नीलामी के लिये उपलब्ध होंगे। इन सेवा क्षेत्रों के लिये स्पेक्ट्रम की नीलामी की जायेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड रखने के उद्देश्य से, विद्यमान सेवा सम्भरकों को भी इन सेवा क्षेत्रों में नीलामी के दौरान प्राप्त सर्वोच्च बोली कीमत का भुगतान करना पड़ेगा'।
- इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि 'अथॉरिटी ने इस विचार के साथ बी डब्ल्यू ए के लिये स्पेक्ट्रम आबंटन पर अपनी सिफारिश दी थी (सितम्बर 2006) कि 3.3-3.6 गीगा

8 एम सी डब्ल्यू–माइक्रोवेव फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द रेट्स फॉर माइक्रोवेव कैरियर्स अलॉटेड

हर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले ब्राडबैंड बेतार नेटवर्क का तत्काल परियोजन डिजिटल विभाजन कम करने के लक्ष्य में अपेक्षित प्रोत्साहन देगा। तथापि, सिफारिशें करने के 20 माह से अधिक समय बाद भी इन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस बीच, बी डब्ल्यू ए प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकीय प्रगति और अधिक फोकस के परिणामस्वरूप ट्रिपल प्ले[9] सहित विभिन्न एप्लीकेशन के लिये इस बैंड के सम्भाव्य उपयोग में वृद्धि हुई। इस बैंड को भविष्य में परीक्षण (बैंड श्रेणी 4 व 5)[10] के लिये मोबाइल वाइमैक्स सर्टिफिकेट प्रोफाइल में भी शामिल किया गया। अतः भविष्य में, स्थिर व मोबाइल ब्राडबैंड दोनों ही तथा अन्य सेवायें बैंड में उपलब्ध हो जायेंगी। पूर्ववर्ती के मद्देनजर अब अथॉरिटी, जहां तक नीलामी के रिजर्व मूल्य के निर्धारण का संबंध है, 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड को 2.3 व 2.5 गीगा हर्ट्ज से अलग मानने का कोई औचित्य नहीं समझती'।

दूरसंचार विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (नवम्बर 2014) किः–

- दू वि ने महानगरों व शहरों में सेवा सम्भरकों को बिना एक समय स्पैक्ट्रम प्रभार के भुगतान के 3.3 गीगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम आबंटित किया था जिनका वार्षिक नवीनीकरण किया गया था।

- दू वि ने 2.5 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम नीलाम करने के लिय दिशा निर्देश जारी किये थे (अगस्त 2008) तथा यह बताया भी था कि 2.3-2.4 गीगा हर्ट्ज तथा 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी तब की जायेगी जब वे उपलब्ध होंगे। दो पी एस यू (बी एस एन एल व एम टी एन एल) को 2008 में 2.5 गीगा हर्ट्ज बैंड में प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम आबंटित किये गये थे और उन्हें बताया गया था कि उन्हें 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड के लिये नीलामी अन्वेषित कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। ट्राई की सिफारिशों के अनुसार, बी डब्ल्यू ए सेवाओं के लिये 2010 में 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड की नीलामी की गई थीं। दोनों पी एस यू ने जून 2010 में 2.3 गीगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी की कीमत के आधार पर 2.5 गीगा हर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के लिये भुगतान किया था। तथापि, आज तक सेवा सम्भरकों जिनके पास 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है को न तो परिमंडल स्तर परिचालन में स्थानान्तरित करने के लिये कहा गया और न ही 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिये कोई कार्रवाई की गई थी और इस प्रकार सेवा सम्भरकों, जिनको यह स्पेक्ट्रम आबंटित था, को अनुचित लाभ दिया गया।

- 2006 व पुनः 2008 में ट्राई की सिफारिशों के बावजूद बिना नीलामी किये तथा बिना एक बार के स्पैक्ट्रम प्रभार के भुगतान के वर्ष–प्रतिवर्ष वाणिज्यिक आपरेटरों के 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड के स्पैक्ट्रम के निरंतर प्रशासनिक आंबटन से सेवा सम्भरकों को अनुचित लाभ हुआ तथा सार्वजनिक कोष को हानि हुई। चूंकि कोई नीलामी नहीं हुई थी, लेखापरीक्षा सार्वजनिक कोष में हुई हानि का सही निर्धारिण नहीं कर सका। तथापि 2010 में 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में बी. डब्ल्यू.ए. स्पैक्ट्रम के लिए रिजर्व मूल्य जिसकी सिफारिश ट्राई ने 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड के लिये भी की थी (2008), के आधार पर, नीलामी नहीं की जाने के कारण 1 सितम्बर 2010

9 दूरसंचार में ट्रिपल प्ले उसे कहते है जिसमें ध्वनि वीडियो तथा डाटा भी एक ही एक्सेस सब्सक्रिप्सन में होते हैं

10 स्रोतः वाईमैक्स फोरम टीएम मोबाइल सिस्टम प्रोफाइल 4 रिलीज 1.0 अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन (रिविजन 1.2.2 : 2006-11-17)

से 1 सितम्बर 2015 के बीच हुई हानि ₹ 1014 करोड़[11] थी जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आपरेटर का नाम	कब आंवटन हुआ	एसए की संख्या जहां टी एस पी के पास 3.3 गीगा हर्ट्ज़ स्पैक्ट्रम है	आवंटित स्पैक्ट्रम (3.3 गीगा हर्ट्ज़ बेंड में)	एल एस ए की संख्या जहां आपरेटर ने नीलामी द्वारा 2.3 गीगा हर्ट्ज़ में 20 मेगा हर्ट्ज़ बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया	5 वर्षों हेतु बी डब्ल्यू ए की अनुपातिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1	भारती एयरटेल (168 शहर)	अप्रैल 2005 से जुलाई 2009	22	2X6 मेगा हर्ट्ज़ (165 शहरों में) तथा 2 X 1.75 मेगा हर्टज़ (3 शहरों में)	8	228.50
2	एयरसेल (80 शहर)	अक्तूबर 2004 से अप्रैल 2010	16	2X6 मेगा हर्ट्ज़	8	228.75
3	आर सी आई एल (12 शहर)	अक्तूबर 2004 से फरवरी 2010	8	6 मेगा हर्ट्ज़	.	177.00
4	टी सी एल (396 शहर)	अक्तूबर 2004 से मार्च 2008	22	6 मेगा हर्ट्ज़	.	131.25
5	ट्रेक ऑनलाइन (4 शहर)	मार्च 2004 से सितम्बर 2005	4	2 X 1.75 मेगा हर्ट्ज़	.	28.00
6	टयूलिप (121 शहर)	मार्च 2008	19	2X6 मेगा हर्ट्ज़	.	220.50
कुल						1014.00

(विवरण अनुलग्नक I से VI में दर्शाये गये हैं)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर दू वि द्वारा उत्तर दिया गया (अप्रैल 2015) कि–

- ट्राई की सिफारिशों की जांच करने के लिये वायरलेस एडवाइजर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार (जून 2007), 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड अभी तक विश्व भर में बी डब्ल्यू ए अप्लीकेशन से मेल नहीं खाता, इसलिये यह सिफारिश की गई थी कि बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम का आबंटन 2.5 गीगा हर्ट्ज बैंड के साथ शुरू किया जाना चाहिये और उसके बाद अन्य सेवा सम्भरकों को 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड, 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड तथा 3.4-3.6 गीगा हर्ट्ज बैंड में (संगतता स्थापित हो जाने के बाद) वैकल्पिक स्पैक्ट्रम के आबंटन पर विचार किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, दूरसंचार आयोग के लिये प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे दूरसंचार आयोग ने 29 जून 2007 को अनुमोदित किया।

- 2.3/2.5 गीगा हर्ट्ज बेंड को शामिल कर स्पैक्ट्रम की नीलामी के लिये दिशानिर्देश जारी किये गये थे (अगस्त 2008) तथा नीलामी के लिये 3.3-3.5 गीगा हर्ट्ज स्पैक्ट्रम पर विचार नहीं किया गया था। उचित परिश्रम के बाद, एन आई ए फरवरी 2010 में प्रकाशित किया गया था तथा 2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम की नीलामी 2010 के दौरान की गई थी'।

11 (क) चूंकि ट्राई ने अपनी 2008 की सिफारिशों में नीलामी के लिये रिजर्व मूल्य निर्धारण हेतु 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज को 2.3 व 2.5 गीगा हर्ट्ज से अलग नहीं माना था, हानि की गणना बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम (2.3 गीगा हर्ट्ज) जिसकी नीलामी 2010 में की गई थी, के निर्धारित रिजर्व मूल्य के अधार पर की गई है।

(ख) नीलामी में स्पैक्ट्रम सामान्यतः 20 वर्षों के लिये दिया जाता है। यदि हानि की गणना 20 वर्षों के लिये रिजर्व प्राइज के आधार पर की जाये तो यह ₹ 4056 करोड़ आता है (1014 ÷ 4 = 4056)

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

- 3.3–3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड के वैश्विक सर्व स्वीकार्यता में कमी के सम्बंध में दू वि का उत्तर सुसंगत नहीं है। अक्तूबर 2007 में, अर्न्तराष्ट्रीय दूरसंचार संघ[12] (आई टी यू) ने अर्न्तराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आई एम टी) एप्लिकेश्न के लिये 3.4–3.6 गीगा हर्ट्ज बैंड को शामिल करने का निर्णय किया था। उसी निर्णय में, आई टी यू द्वारा 2.3-2.4 गीगा हर्ट्ज बैंड भी आई एम टी एप्लिकेश्न के लिये शामिल किया गया था, जिसकी बाद में 2010 में नीलामी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 2010 तक, यूरोपियन व एशियन पैसिफिक देशों[13] में बी डब्ल्यू ए सेवाओं के लिये 3.3 से 3.6 गीगा हर्ट्ज सबसे ज्यादा आबंटित स्पैक्ट्रम हो गया था।

- 2.5 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम नीलामी अनुमोदित करते समय (अगस्त 2008), दू वि द्वारा 2.3-2.4 गीगा हर्ट्ज तथा 3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम नीलाम न करने के लिये कारण दिया गया था कि उपरोक्त बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी तब की जायेगी जब यह उपलब्ध होगा। तथापि, स्पैक्ट्रम (3.3-3.4 गीगा हर्ट्ज बैंड) दू वि के पास 2008 से प्रभावपूर्ण तरीके से उपलब्ध था क्योंकि इस स्पैक्ट्रम का आबंटन केवल वार्षिक आधार पर था, जिसे दू वि द्वारा प्रति वर्ष बिना नीलामी किए नवीनीकरण किया जा रहा था।

इस प्रकार, आपरेटरों को बिना एक मुश्त प्रभारों के प्रशासनिक तौर पर प्रतिवर्ष 3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम का आबंटन/विस्तार जारी रखने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक कोष में उल्लेखनीय हानि हुई।

यह पैराग्राफ मंत्रालय को जून 2015 में जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.3 ट्राई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को खोले जाने पर अनियमित व्यय

भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केन्द्र सरकार के निर्देशों, अपने ही लीगल डिवीजन तथा विधि, न्याय तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय की राय की अनदेखी करते हुए देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा 2012-14 के दौरान ₹ 14.12 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

पहले से केन्द्र सरकार में निहित दूरसंचार सेवाओं के विनियमन जिसमें दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है, के लिए भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना ट्राई अधिनियम 1997 के द्वारा की गई थी (यहां से इसे 'अधिनियम' कहा जायेगा)। बाद में अधिनियम में ट्राई (संशोधन) अधिनियम 2000 के तहत संशोधन किया गया।

12 आई टी यू संयुक्त राष्ट्र की एक एजेन्सी है जिसका उद्देश्य विश्व भर में दूरसंचार ऑपरेशन तथा सेवाओं का समन्वय करना है।
13 स्रोतः बुक ऑन वाइमैक्स नेटवर्कस– टेक्नो इकोनॉमिक वर्जन एण्ड चैलेंजेज बाई रामजी प्रसाद एण्ड फर्नेडो वेलेज

अधिनियम के तहत, ट्राई अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के पालन हेतु अधिनियम व इसके तहत बने नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है (अनुच्छेद 36)[14] तथा ऐसे विनियम अनुच्छेद 37 में निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने आवश्यक है। ट्राई को यह अधिकार है कि अधिनियम के तहत (अनुच्छेद 10 (1)) अपने प्रकार्यों के कुशलता पूर्वक निष्पादन हेतु जैसा आवश्यक समझे अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के संचालन हेतु नियम बनाने का (अनुच्छेद 35 (1)), समय–समय पर नीतिगत मामलों पर प्राधिकरण को निर्देश, जिनका अनुपालन आवश्यक होगा, जारी करने का (अनुच्छेद 25 (1 व 2)) तथा प्राधिकरण के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की सैलरी, तथा भत्तों व सेवा के अन्य नियमों को निर्धारित करने का अधिकार है (अनुच्छेद 10(2))। प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों व पेंशन सहित, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान (अनुच्छेद 21 व 22) में से किये जाते हैं।

अगस्त 2011 में आयोजित इसकी 344 वीं बैठक में, ट्राई ने पूरे देश में दस विभिन्न स्थानों[15] में क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे का) खोलने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। अप्रैल 2012 में आयोजित इसकी 357वीं बैठक में दिल्ली में एक और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुमोदन किया गया। 360वीं बैठक (मई 2012) में, ट्राई ने पूर्ववर्ती अनुमोदन में संशोधन करते हुए निर्णय किया कि क्षे का ट्राई की कैपिसिटी बिल्डिंग के भाग के रूप में ट्राई की 'योजना निधि' के तहत 'पायलट परियोजना आधार' पर दो वर्षों अर्थात् 2012-13 व 2013 14 के लिये संचालित किये जायेंगे। यह भी निर्णय किया गया कि भविष्य में 'गैर योजना' निधि के तहत आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रकरण पर प्रयास किया जाएगा।

क्षे का की भूमिका व कार्य [16] के निर्धारण सहित सभी 11 कार्यालयों को खोलने के लिये कार्यकारी आदेश जून 2012 में जारी किये गये थे, जिसके तहत इन कार्यालयों को चलाने के लिये ट्राई द्वारा सलाहकार के 11 पद, संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार के 22 पद, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के 22 पद व सहायक के 11 पद भी सृजित किये गये थे। ट्राई ने इन क्षे.का. में 26 अधिकारी/कर्मचारी (9 सलाहकार, 11 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा 6 सहायक) तैनात किये तथा मार्च 2014 तक ₹ 14.12 करोड़ का व्यय किया जैसाकि **अनुलग्नक-VII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि ट्राई अधिनियम ट्राई को स्वंय क्षे का खोलने व पद–निर्माण के लिये अधिकृत नहीं करता है। यहां तक कि जब ट्राई ने अपने लीगल डिवीजन से क्षे का खोलने के सम्बंध में परामर्श किया तो उसने फरवरी 2011 में राय दी कि ट्राई अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान न होने से, पूरे देश में अपने आप क्षे का खोलना प्राधिकरण के लिये सम्भव नहीं होगा।

14 अनुच्छेद 36 के अंतर्गत ट्राई ने 15 फरवरी 2001 को ट्राई (ऑफिसर्स व स्टाफ नियुक्ति) विनियमन 2001 अधिसूचित किया है जिसे संसद में दिसम्बर 2002 में पेश किया गया था।

15 भोपाल, बंगलौर, चण्डीगढ़, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई और पटना।

16 टैरिफ से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना तथा रिटेल टैरिफ की प्रभावी मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी व मार्केटिंग पहलू के संबंध में सेवा सम्प्रकों से उचित समन्वय, सेवा की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग व उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान, ट्राई की ओ एच डी/सी ए जी बैठकें आयोजित करना, लेखापरीक्षा का समन्वय तथा मॉनिटरिंग व ट्राई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों से सर्वे कराना, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स (सी ए जी) का जिला ब्लॉक स्तर तक विकास तथा सी ए जी से निकट इंटरएक्शन उपभोक्ता शिक्षा वर्कशाप आयोजित करना, दू वि के टर्म सेल से निकट इंटरएक्शन एम एन पी तथा यू सी सी की मॉनिटरिंग इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, क्षे.का. खोलने के लिये अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु वर्ष 2012-13 के लिये ट्राई के बजट आकलन (गैर–योजना' के तहत) पर, दूरसंचार विभाग (दू वि) ने क्षे का में पदों के सृजन हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर जोर दिया (नवम्बर 2011) तथा ट्राई से कहा कि वह दू वि/वित्त मंत्रालय (वि मं) द्वारा दिये गये अनुमोदन की प्रतियों की आपूर्ति करें। दू वि ने पुनः दोहराया (मई 2012) कि प्रस्तावित क्षे का के लिये पदों का सृजन केवल वि मं तथा यूनियन कैबिनेट के अनुमोदन से किया जा सकता है। दू वि ने ट्राई से ट्राई के क्षे का के लिये प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु वित मंत्रालय (वि मं) के अनुमोदन हेतु स्वतः पूर्ण प्रस्ताव भी औचित्य के साथ भेजने को कहा था। बाद में, 2012-13 में गैर योजना के तहत निधि जारी करने हेतु सभी संस्वीकृति आदेशों में दू वि ने स्पष्ट रूप से कहा था कि निधि इस शर्त पर दी गई थी कि ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बंध में स्थापना व्यय हेतु निधि उसमें शामिल नहीं की गई थी। तथापि, जब दू वि ने 'गैर योजना' के तहत निधि आबंटन के लिये उनकी मांग स्वीकार नहीं की तो, ट्राई ने दू वि के सभी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए ग्यारह क्षेत्रीय कार्यालय खोलने व अस्थायी पदों के सृजन के लिये कार्यकारी आदेश जून 2012 में जारी जिसके लिए व्यय ट्राई की कैपेसिटी बिल्डिंग परियोजना के एक भाग के रूप में ट्राई की 'योजना निधि' से पूरा किया जाना था।

यह भी देखा गया कि निम्नलिखित पूर्ववर्ती अवसरों पर भी, भारत सरकार के मंत्रालयों ने स्पष्ट रूप से राय दी थी कि ट्राई को स्वयं पदों का सृजन का अधिकार नहीं था।

1. जनवरी 2000 में, वि मं ने दू वि को बताया था कि प्रत्यक्ष बजटीय व पालिसी निहितार्थों को ध्यान में रखकर, पदों का सृजन आदि वि मं के अनुमोदन से ही किया जाना चाहिये।

2. जुलाई 2001 में, विधि न्याय व कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दू वि को राय दी कि पदों का सृजन केन्द्र सरकार में निहित है तथा ट्राई अधिनियम के अनुच्छेद 10 के तहत 'नियुक्ति' शब्द ट्राई द्वारा पदों का सृजन शामिल नहीं करता। इसे दू वि ने जुलाई 2001 में ट्राई को इस अनुरोध के साथ सूचित किया था कि प्रस्तावित ट्राई (अधिकारी व स्टाफ नियुक्ति) विनियमन 2001 में अपेक्षित संशोधन करें।

3. अप्रैल 2004 में वि मं ने दू वि को स्पष्ट किया कि पदों के सृजन पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुये ऐसे मामलों में वि मं की सहमति आवश्यक होगी तथा यह पालिसी सभी विनियामक निकायों पर लागू थी।

इसके अतिरिक्त, कैपिसिटी बिल्डिंग के भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों को संचालित करने का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि कैपिसिटी बिल्डिंग परियोजना का अभिप्राय दक्षता विकास तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत करना व विकसित करना था और किसी भी तरह इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना को संचालित करना शामिल नहीं था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि प्रारंभ में, ट्राई ने गैर योजना के तहत निधि से क्षे का संचालित करने का निर्णय किया। यह वित्तीय शक्ति प्रत्यावर्तन नियम (नियम 10) का भी उल्लंघन था, जिसके तहत निधि का योजना शीर्ष से गैर योजना शीर्ष में वित मंत्रालय की सहमति के बिना पुर्नविनियोजन निषेध है।

तथापि, एक्ट के प्रावधानों, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों व स्पष्टीकरण तथा अपने ही लीगल डिवीजन की राय को न मानते हुये, प्राधिकरण ने पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने व उसमें काम करने के लिये पदों का सृजन केन्द्र सरकार से अनुमोदन लिये बिना किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, प्राधिकरण ने बताया कि (जून 2015) कि;

1) क्षेत्रीय कार्यालय पायलट परियोजना के तहत काम कर रहे थे तथा ट्राई की नियमित स्थापना का भाग नहीं थे। क्षे.का. नियमित कार्यालय नहीं बनाये जाने थे, इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि पायलट परियोजना के निष्पादन की समीक्षा में निर्णय किया गया कि 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में से पांच[17] बंद कर दिये जायें तथा इनमें सृजित 30 अस्थायी पद 31 मार्च 2014 से समाप्त कर दिये जायें। शेष छः[18] कार्यालयों की अवधि 31 मार्च 2016 तक बढ़ाई गई तथा उन्हें बनाये रखने की आवश्यकता या अन्यथा के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले उनकी स्थिति/निष्पादन का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यालय खोले जाने से पूर्व, श्री हरेन पी रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से विशेषज्ञ कानूनी राय ली गई थी (जुलाई 2011) जिन्होंने राय दी कि अधिनियम में किसी प्रकार के सांविधिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में, ट्राई के लिये सारे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना विधिक रूप से अनुमत्य था।

ट्राई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः

- मात्र विशिष्ट निषेध प्रावधान न होने से ट्राई को स्वयं क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अधिकार नहीं मिल जाता। यहां तक कि, उसके स्वयं के लीगल डिवीजन की राय थी (फरवरी 2011) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने का उद्देश्य ट्राई अधिनियम में उचित संशोधन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पॉलिसी मामलों (अनुच्छेद 25) पर ट्राई को निर्देश जारी करने के केन्द्र सरकार के अधिकारों के तहत भी यह जरूरी था कि क्षे का खोलने तथा उस पर भारत के समेकित निधि से प्राप्त अनुदान में से व्यय करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन लिया जाए।

- सामान्य स्थापना के भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय बनाने हेतु ट्राई का इरादा इस तथ्य से स्पष्ट था कि प्रारंभ में, इसकी स्थापना के लिये निधि का अनुरोध 'गैर योजना' के तहत किया गया था। जैसा कि ट्राई के प्रधान सलाहकार (एफ व ई ए) की राय (सितम्बर 2013) से स्पष्ट था कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द करने का मुख्य कारण दू वि से पर्याप्त निधि की उपलब्धता नहीं होनी थी। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षे का खोलने के पायलेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन्हें नियमित क्षे.का में परिवर्तित करने का था अन्यथा यह अनुपयोगी और अनावश्यक प्रयोग/व्यय होता।

17 चण्डीगढ़, गुहावटी, लखनऊ, मुम्बई तथा पटना।

18 बंगलौर, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता

2) (i) वर्ष 2000 में ट्राई अधिनियम में संशोधन से पूर्व, प्राधिकरण आवश्यकतानुसार पदों का सृजन कर रहा था। इसके अतिरिक्त संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा, केवल अनुच्छेद 10 (2) में संशोधन किया गया है तथा अनुच्छेद 10(1) अपरिवर्तित रहा और इस प्रकार पद–सृजन करने का ट्राई का अधिकार प्राधिकरण से नहीं लिया गया है।

(ii) अधिनियम के खंड 36 के तहत, ट्राई ने ट्राई (अधिकारी व स्टाफ नियुक्ति) विनियमन 2001 अधिसूचित किया है जिसमें यह अनुबंध किया गया है कि प्राधिकरण ग्रेड व पदों की संख्या के संबंध में समय–समय पर जैसा आवश्यक समझे निर्णय ले सकता है। यह विनियमन दिसम्बर 2002 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया गया था। विनियमन में संशोधन के लिये दू वि से सूचना मिलने पर (जुलाई 2001), ट्राई ने दिसम्बर 2001 में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए एस आनंद की राय प्राप्त की थी, जिन्होंने राय दी थी कि पदों के सृजन के अधिकार को अधिनियम के अनुच्छेद 10(1) के तहत नियुक्ति के लिये ट्राई के अधिकार में सम्मिलित माना जाना चाहिये। बाद में, प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन माननीय मंत्री सं व सू प्रौ को मामले की समीक्षा हेतु तथा संशोधन में आग्रह किये बिना संसद में विनियमन प्रस्तुत करने हेतु 13 फरवरी 2002 को एक पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद संसद के सामने विनियमन प्रस्तुत किया गया जैसाकि दूरसंचार विभाग में फरवरी 2013 में बताया। तब से चूंकि इस सम्बंध में दू वि से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे एक आम धारणा बनी कि दिनांक 13 फरवरी 2002 के पत्र के अनुसार ट्राई द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति दू वि को स्वीकार्य थी।

ट्राई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- 'नियुक्ति' व 'पदों का सृजन' के अर्थ अलग–अलग हैं। कानूनी मामलों के विभाग के अनुच्छेद 10(1) की व्याख्या के अनुसार 'नियुक्ति' शब्द में पदों का सृजन शामिल नहीं है।

- संसद में ट्राई (अधिकारी व स्टाफ नियुक्ति) विनियमन 2001 मूल रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि ट्राई पदों के सृजन के संबंध में ट्राई (अधिकारी व स्टाफ नियुक्ति) विनियमन 2001 में संशोधन करने पर सहमत नहीं था, दू वि ने संशोधन किये बिना संसद में विनियमन मूल रूप में प्रस्तुत किया। इसलिये ट्राई को पदों का सृजन करने का अधिकार नहीं था। दू वि के बाद में ट्राई से नवम्बर 2011 व मई 2012 में ट्राई के बजट प्रस्तावों पर पत्राचार से भी यह स्थापित होता है कि दू वि इस बात से सहमत नहीं था कि ट्राई को पदों का सृजन करने का अधिकार है।

3) मई 2012 में दू वि से संदर्भ प्राप्त होने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों को भरे जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी तथा कुछ अधिकारियों ने पदभार ग्रहण भी कर लिया था। पुनः चूंकि दू वि के अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये स्वयं दू वि द्वारा ही कार्यमुक्त किया गया था, इससे पता लगता है कि पदों के सृजन में सरकार का

अपेक्षित अनुमोदन था। तथापि, मई 2012 से दू वि से सूचना प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये पदों के सृजन हेतु एक विस्तृत औचित्य दू वि को जून 2012 में भेजा गया था और उसके बाद मामले में कोई उत्तर दू वि से प्राप्त नहीं हुआ।

ट्राई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्राई ने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये आदेश जून 2012 में जारी किया था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2012 के अंत में कार्य करना शुरू कर दिया था, जबकि दू वि ने नवम्बर 2011 में ही क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये बजट प्रस्तावों पर आपत्तियां उठाई थी। दू वि ने मई 2012 में अपने सूचना में विशेष रूप से बताया भी था कि क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों का भरा जाना पदों के सृजन हेतु वि मं के अनुमोदन के बाद ही हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, ट्राई ने सरकार के सभी निर्देशों के उल्लंघन में क्षे का में स्वयं द्वारा सृजित अस्थायी पदों को भरना जारी रखा।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से सहमत होकर मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि ट्राई का दावा ट्राई अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा मामले पर जारी सम्बन्धित नियमों/अनुदेशों के अनुसार उचित नहीं था।

इस प्रकार, ट्राई ने केन्द्र सरकार के निर्देशों, अपने लीगल डिवीजन व विधि न्याय व कम्पनी के मंत्रालय की राय नहीं मानते हुए पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2014 तक ₹ 14.12 करोड़ का अनाधिकृत व्यय किया। भविष्य में भी व्यय तब तक किया जायेगा जब तक क्षे.का कार्यरत रहेंगे।

अध्याय -III
डाक विभाग

3.1 सेनवैट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण सेवा कर का अधिक भुगतान

निदेशक पी एल आई कोलकाता, व सी पी एम जी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान व दिल्ली डाक परिमंडल 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपयुक्त सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर तथा शैक्षिक कर के रुप में ₹ 7.52 करोड का परिहार्य भुगतान हुआ।

सितम्बर 2004 में शुरू किये गये सेनवैट नियमों ने विनिर्माता अथवा कर योग्य सेवा के प्रदाता को अनुमति दी थी कि वह विर्निदिष्ट अंतिम उत्पाद/आउटपुट सेवाओं के विनिर्माण में प्रयुक्त या उससे संबंधित इनपुट सेवाओं के लिए प्रदत्त शुल्क/सेवा कर का क्रेडिट ले। उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का उपयोग आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर में अथवा किसी उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिये किया जा सकता था। डाक विभाग (डा वि) द्वारा दी गई सेवाओं को भारत सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2006 से सेवा कर के दायरे में लाया गया। डा वि, आउटपुट सेवा प्रदाता होने के नाते, अपनी उत्पाद सेवाओं अर्थात, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा, व्यवसायिक सहायक सेवाओं पर सेवा कर व शैक्षिक कर संग्रहित करता है तथा प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं जैसे डा वि के दूरभाष बिल, कम्प्यूटर के लिये वार्षिक अनुरक्षण प्रभार, पूंजीगत वस्तुओं के क्रय, आदि पर सेवा कर/उत्पाद शुल्क व शैक्षिक कर का भुगतान करता है।

2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 के पैराग्राफ संख्या 2.6 में सेवा कर के अधिक भुगतान पर टिप्पणी की गई थी। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पणी (दिसम्बर 2010) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया था व बताया था कि सेनवैट क्रेडिट का दावा करने की कार्यपद्धति पर विस्तृत अनुदेश नवम्बर 2010 में सभी परिमंडलों को जारी किये गये थे।

तथापि, मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2010 में अनुदेश जारी करने के बावजूद भी, कमियाँ निरन्तर बनी रहीं। निदेशक, डाक जीवन बीमा (नि डा जी बी) कोलकाता व सी पी एम जी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व दिल्ली परिमंडलों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा जांच के रिकार्ड (जनवरी 2014, जनवरी 2015 से मार्च 2015 और मई 2015 में अद्यतन) से पता चला कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान सेवाकर के रूप में ₹ 7.52 करोड़ का भुगतान इनपुट सेवाओं के कारण किया गया था। तथापि, यह संज्ञान में आया कि आउटपुट सेवाओं के लिये सेवाकर का भुगतान करते समय, इन परिमंडलों ने सहायक सेवाओं पर सेवाकर के विरूद्व ₹ 7.52 करोड़ का पात्र सेनैवट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	यूनिट का नाम	इनपुट सेवाओं के प्रकार जिस पर सेवा कर का भुगतान किया गया	सेनवैट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण अधिक भुगतान
1	डी पी एल आई कोलकाता	एजेन्ट को कमीशन का भुगतान	2.79
2	महाराष्ट्र	निजी एयरलाइन्स द्वारा स्पीड पोस्ट डाक पर कैरियेज	1.70
3	पश्चिम बंगाल	दूरभाष बिल, ए एम सी आदि	1.08
4	दिल्ली	स्वचालित डाक प्रक्रिया प्रणाली	1.61
5	राजस्थान	दूरभाष बिल, ए. एम. सी आदि	0.34
कुल			**7.52**

लेखापरीक्षा के एक पूर्व के संदर्भ[1] में मंत्रालय ने कहा (मई 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 2.79 करोड़ के प्राप्त नहीं किए गए सेनवैट क्रेडिट का लाभ निदेशक, डा जी बी कोलकाता ने सितम्बर 2014 के दौरान उठा लिया गया है।

मुख्य महाडाकपाल मुम्बई ने बताया (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 1.70 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट सितम्बर 2015 में प्राप्त किया गया था, सी पी एम जी पश्चिम बंगाल ने स्वीकार किया कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। सी पी एम जी राजस्थान परिमंडल ने बताया कि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। दिल्ली परिमंडल के सम्बन्ध में, निदेशक (डाक व्यवसाय) डा वि ने अगस्त 2015 में बताया कि डाक निदेशालय के डी डी ओ ने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया। आगे यह भी बताया गया था कि विक्रेता को भुगतान करने के सम्बन्ध में संस्वीकृत आदेश की प्रतियां डी डी ओ को पृष्ठांकित करते समय डी डी ओ द्वारा सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक टिप्पणी जोड़ी जायेगी। तीन सर्किलों द्वारा ₹ 3.03 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट उपयोग किया जाना शेष है (अक्तूबर 2015)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पुष्टि होती है कि डा वि को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सेनवैट क्रेडिट के लाभ का दावा करने के लिए डा. वि. द्वारा जारी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

3.2 बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

डाक विभाग ने अपेक्षित साफ्टवेयर सुसंगत तरीके से विकसित किये बिना बारकोडेड बैग लेबलों की अधिप्राप्ति की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा आशयित उद्देश्य की गैर–उपलब्धि हुई।

डाक विभाग (डा वि) का प्राथमिक कार्य डाक का संग्रहण, सम्भरण, सम्प्रेषण व वितरण है। सभी डाक वस्तुयें जिसकी विषय वस्तु संदेश प्रकृति की है, को डाक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें पत्र, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, पैकेट, साधारण/पंजीकृत पत्र, बीमाकृत वस्तुऐं, मूल्य भुगतान योग्य वस्तुऐं, स्पीड पोस्ट शामिल हैं। इनको प्रथम श्रेणी व द्वितीय क्षेणी की डाक के रूप वर्गीकृत किया गया

1 जनवरी 2014 में, निदेशक डी पी एल आई कोलकाता को एक संदर्भ दिया गया था

है। प्रथम श्रेणी की डाक का भारत के भीतर मुफ्त एयर मेल सम्प्रेषण होता है; जबकि द्वितीय श्रेणी की डाक का एयर लिफ्ट डाक तभी होता है जब हवाई प्रभार के साथ पूर्व भुगतान किया गया है। स्पीड पोस्ट व पंजीकृत डाक के लिये खोज़ व पता सुविधा उपलब्ध कराकर सम्प्रेषण की दृष्यता बढ़ा दी गई है। ग्राहक विशिष्ट बारकोड संख्या का उपयोग करके इंडिया पोस्ट वेवसाइट के माध्यम से डाक का पता लगा सकता है।

बैग लेवल डेटा इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से, डा वि ने जून 2012 में अपंजीकृत प्रथम श्रेणी के डाक बैग के लिये बारकोडेड बैग लेबल प्रारम्भ करने का निर्णय किया। सभी डाक परिमंडलों को अनुदेश दिये गये थे कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आबंटित विनिर्देशनों के अनुसार इन बैग लेबल के लिये आदेश दें। यह प्रक्रिया 31 जुलाई 2012 तक पूरी की जानी थी। इसके अतिरिक्त, मई 2012 में डा वि ने परिकल्पना की कि जब तक आवेदन साफ्टवेयर विकसित नहीं हो जाता है, तब तक साधारण डाक के लिये बैग लेबल डेटा प्रचलित आर–नेट साफ्टवेयर का उपयोग, जो कि पंजीकृत डाक की प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त किया जाता है, करते हुये प्राप्त किया जा सकता है। मेल नेटवर्क आप्टीमाइजेशन परियोजना (एम एन ओ पी) के भाग के रूप में, सेण्टर फार अनुपयोग एक्सेंस इन पोस्टल टेक्नोलोजी (सी ई पी टी) मैसूर को जुलाई 2012 में निर्देश दिया गया था कि वह आर नेट को अनुशास्ति करवायें तथा डाक कार्यालयों में बैग लेबल डेटा की प्राप्ति के लिये कार्यात्मकता विकसित करें। बाद में, सी ई पी टी से कहा गया था कि वह प्रधान डाकघरों में भी अपंजीकृत डाक बैग लेबल की जांच (स्कैनिंग) के लिये कार्यात्मकता शामिल करें।

17 परिमंडलों में 30 डाक भंडार डिपो में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014 व अद्यतन जुलाई 2015 तक) से पता चला कि डा वि के अनुदेश पर अगस्त 2012 से मार्च 2015 के दौरान 476.21 लाख बारकोडेड लेबल ₹ 1.71 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त किये गये थे, जैसा कि **अनुलग्नक VIII** में वर्णित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन बारकोडेड बैग लेबल का उपयोग बैग लेबल डेटा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं किया गया था क्योंकि न तो विद्यमान साफ्टवेयर अनूकुलित था और न ही एक नये साफ्टवेयर विकसित किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि चूंकि इन लेबल का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा था अतः डा वि ने अक्तूबर 2014 में सभी परिमंडलाध्यक्षों को अनुदेश जारी किये थे कि वे दिसम्बर 2014 से अपंजीकृत डाक वाले बैग बंद करते समय इन लेबल का उपयोग करें।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, परिमंडलों ने (जून/जुलाई 2015) में कहा कि अपेक्षित साफ्टवेयर उन्हें मुहैया नहीं कराया गया था। तथापि, इन बारकोडेड बैग लेबल का उपयोग अपंजीकृत डाक बैग के लिये किया जा रहा था।

इस प्रकार, अपेक्षित साफ्टवेयर विकसित किये बिना डा वि द्वारा बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति तथा साधारण लेबल के रूप में इन लेबल के क्रमागतः उपयोग से बैग लेबल डेटा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयोजन विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय रहा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.3 किराये का गैर दावा

मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से अस्थायी आधार पर दी गई भूमि के किराये का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के किराये की गैर–वसूली हुई।

डाक विभाग (डा. वि.) की वित्तीय शक्तियों की अनूसूची के पैराग्राफ 22(ख) के अनुसार, परिमंडलों के अध्यक्ष, डाक विभाग सम्बन्धित/पट्टे पर ली गई खाली भूमि से सरकारी कर्मचारियों अथवा निजी व्यक्तियों अथवा वार्षिक संविदा के तहत निकायों को किराये पर दे सकते हैं अथवा अति अनूकूल दरों पर पट्टे पर दे सकते हैं।

बैंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (बी एम आर सी एल) द्वारा महाडाकपाल, (पी एम जी) प्रधान डाकघर (जी पी ओ) बंगलोर से जुलाई 2009 में जी पी ओ परिसर में 1015 वर्ग मीटर भूमि की अस्थायी आवश्यकता के सम्बन्ध में एक अनुरोध किया गया था ताकि जीपीओ के पूर्वी छोर तथा पश्चिमी छोर (चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम) के बीच मेट्रो स्टेशन के निर्माण को सुगम बनाया जा सके।

मुख्य डाकपाल, प्रधान डाकघर बैंगलौर कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2015) से पता चला कि मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल ने बी एम आर सी एल का प्रस्ताव स्वीकार किया। तथापि, अस्थायी आधार पर बी. एम आर सी एल द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए किसी किराये का दावा नहीं किया गया था, जोकि वित्तीय शक्तियों की अनूसची में निहित प्रावधानों का उल्लंधन था। इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में आया कि बी एस एन एल से सम्बन्धित 810.12 वर्ग मी की माप वाली निकटवर्ती भूमि भी बी एम आर सी एल को अस्थायी आधार पर दी गई थी (सितम्बर 2009), जिसके लिये बी एम आर सी एल ने सरकार द्वारा प्रकाशित भूमि के निर्देशित मूल्य का 7 प्रतिशत वार्षिक मानक दर पर किराये का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार, सी पी एम जी कर्नाटक परिमंडल द्वारा बी एम आर सी एल से भूमि की अस्थायी आवश्यकता के लिए किराये का दावा करने में चूक कर के परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़[2] के किराये की वसूली नहीं हुई, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अवधि	महीनों की संख्या	कुल भूमि	प्रति वर्ग मीटर/ प्रति माह दर	राशि
01.08.2009 से 31.12.2009	5	1015 वर्ग मीटर	238.07	0.12
01.01.2010 से 31.12.2014	60			1.45
01.01.2015 से 31.03.2015	3			0.07
कुल				1.64

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमत होते हुये उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि किराये के भुगतान से सम्बन्धित मामले को बी. एम आर सी. एल के साथ उठाया गया है तथा यह विचाराधीन है। बी एम आर सी एल ने सूचित किया कि वे शीघ्र ही किराये से भुगतान योग्य राशि निर्दिष्ट करेंगे।

2 बी एस एन द्वारा दावित किराये के आधार पर हिसाब किया गया। भूमि का निर्देशित मूल्य जैसा कि सरकार द्वारा प्रकाशित = ₹ 40,812/ प्रति वर्गमीटर। अस्थायी आधार पर भूमि के प्रति वर्गमीटर का किराया = वार्षिक मूल्य का 7 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,856.84 प्रतिवर्ष। प्रतिमाह अस्थायी क्षेत्रफल के लिये किराया = ₹ 2,856.84/12 = ₹ 238.07)

इस प्रकार बी एम आर सी एल को पट्टे पर भूमि देते समय, किराये का दावा करने में सी पी एम जी कर्नाटक परिमण्डल की चूक ₹ 1.64 करोड़ के किराये पर वसूली में फलित हुई।

3.4 बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान

तमिलनाडु डाक परिमंडल के अन्तर्गत दो इकाईयों व पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल के अन्तर्गत एक इकाई द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विलम्ब के परिणामस्वरूप बिजली प्रभारों में ₹ 0.84 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

तमिलनाडु डाक परिमंडल के अन्तर्गत एयरमेल सोर्टिंग डिवीजन (ए एस डी) चेन्नई व महाप्रबंधक (डाक लेखा व वित्त) (जी एम (पी ए एंड एफ) चेन्नई तथा पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल के अन्तर्गत ए एस डी कोलकाता ने क्रमशः जुलाई 2002, मार्च 2006 व फरवरी 2012 में तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टी एन ई बी) तथा कलकत्ता बिजली आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (सी ई एस सी) के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाने हेतु एक करार किया। 325 के वी ए के लिए क्रमशः (अगस्त 2004 में न्यूनीकृत 275 के वी ए) तथा 250 के वी ए तथा ए एस डी कोलकाता के लिये 428 के वी ए की संविदात्मक अधिकतम मांग[3] ए एस डी चेन्नई व जी एम (पी ए एफ) चेन्नई की गई थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2014 व मार्च 2015) से पता चला कि ए एस डी चेन्नई व कोलकाता तथा जी एम पी ए एंड चेन्नई ने अपनी सम्बन्धित इकाईयों के लिये मांग की नियमित समीक्षा नहीं की थी तथा विद्यमान सी एम डी को जारी रखा जो कि अपेक्षित मांग से काफी अधिक थी। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में डाक प्राधिकारियों की इस भूल के परिणामस्वरूप मांग प्रभारों में ₹ 83.80 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹लाख में)

इकाई का नाम	अवधि	सी एम डी (के वी ए/ के डब्ल्यू में)	मांग की सीमा	न्यूनतम मांग जिसका बिल बनाया जाना था	औसतन अधिकतम मांग[4]	अन्तर (स्तम्भ 5–स्तम्भ 6)[5]	अधिक राशि का भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
ए एस डीए चैन्नई	जनवरी 2003 से अगस्त 2004	325	145 से 231	293	185	108	6.48
	सितम्बर 2004 से नवम्बर 2014	275	40 से 237	248	133	115	42.43
	दिसम्बर 2014	275		248	135	113	0.37
	जनवरी 2015 से मार्च 2015	275		248	131	117	1.23
जी एमए पी ए एवं एफ चैन्नई	सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2014	250	102 से 185	225	146	79	23.70
ए एस डीए कोलकाता	फरवरी 2013 से जनवरी 2015	428	145 से 320	364	238	126	9.59
कुल							83.80

3 बिजली खपत पैटर्न पर आधारित संविदात्मक मांग

4 चैन्नई में 90 प्रतिशत सी एम डी तथा कोलकाता में 85 प्रतिशत सी एम डी

5 अधिक राशि की गणना महीने व प्रति दर के वी ए से कॉलम 7 की गुणा करके की गई थी। तमिलनाडु के लिये प्रति के वी ए दर (₹300/– दिसम्बर 2014 से यह ₹ 325/– और जनवरी 2015 से ₹.350/– तथा कोलकाता के लिये प्रति के वी ए दर (₹ 317/–)

आगे यह भी देखा गया था कि जनवरी 2012 में स्वचालित प्रक्रिया केन्द्र के बंद होने के बावजूद भी, ए एस डी चेन्नई ने 275 के वी ए के मौजूदा सी एम डी को जारी रखा, जबकि जनवरी 2012 से मार्च 2015 की अविध के दौरान अधिकतम मांग 40 से 74 के वी ए रिकार्ड की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि ए एस डी चेन्नई के सम्बंध में, मई 2004 से लोड़ 325 के वी ए से कम कराकर 275 के वी ए हो गया था। अधिकतम मांग 110 के वी ए तक कम हो गई थी क्योंकि ए एम पी सी मशीनों ने 2012 से कार्य करना बंद कर दिया था तथा टी एन ई बी से अनुरोध किया गया था कि वह लोड 275 के वी ए से कम करके 125 के वी ए करें। मार्च 2015 में एच टी आपूर्ति को एल टी आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिये एक नया संयोजन स्वीकृत किया गया था तथा अगस्त 2015 में एल टी आपूर्ति हेतु एक ट्रांसफारमर नियत किया गया था। जी एम, पी ए व एफ चेन्नई के सम्बंध में यह कहा गया कि टी एन ई बी ने स्वीकार किया था कि मीटर दोषपूर्ण था तथा इसे नये मीटर से बदल दिया जायेगा। ए एस डी कोलकाता के सम्बंध में यह बताया गया था कि सी एई एस सी मई 2015 से 290 के वी ए के लिये बिल की मांग उठा रहा था।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने तमिलनाडु बिजली बोर्ड के साथ 325 के वी ए की आपूर्ति के लिये करार किया था जो कि अगस्त 2004 से 275 के वी ए तक कम कर दिया गया था और मार्च 2015 तक बनी रही, यह भी अपेक्षित सी एम डी से अभी भी उच्चतर थी जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

- अगस्त 2004 से सी एम डी 275 के वी ए रही जबकि सितम्बर 2004 से दिसम्बर 2011 के दौरान औसतन खपत मात्र 167 के वी ए थी।
- जनवरी 2012 से ए एम पी सी के बंद हो जाने के बाद औसतन खपत केवल 51 के वी ए थी।

उपरोक्त के बावजूद भी, नौ वर्षों के बीत जाने बाद ही लोड की कमी के लिए कदम उठाये गये थे तथा ए एस डी चेन्नई ने खपत में कमीं के बावजूद भी उच्चतर सी एम डी के लिये भुगतान जारी रखा।

इस प्रकार तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं के नियमित मूल्यांकन में विलम्ब के कारण विभाग को जनवरी 2003 से मार्च 2015 की अवधि के लिये मांग प्रभारों के रूप में ₹ 0.84 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान करना पड़ा।

3.5 स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र का कम उपयोग

डाक विभाग (डा वि) ने दिल्ली व कोलकाता के लिये स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र (ए एम पी सी) ₹ 82.53 करोड़ पर अधिप्राप्त किये थे। भारतीय डाक मानक की आवश्यकताओं के साथ ए एम पी सी की असंगतता के परिणामस्वरूप इन ए एम पी सी का असंतोषजनक कार्य निष्पादन व कम उपयोग हुआ।

डाक का संग्रहण, वितरण व सुपुर्दगी के अतिरिक्त डाक प्रसंस्करण डाक विभाग की मुख्य गतिविधियों में से एक है। डा वि इन कार्यों को 1.55 लाख डाकघरों व 400 डाक प्रक्रिया केन्द्रों से अधिक नेटवर्क के

माध्यम से करता है। इस गतिविधि का मशीनीकरण आवश्यक समझा गया था क्योंकि डाक का संचालन पूरी तरह हस्तचालित था जिसने इसकी प्रक्रिया को त्रुटियुक्त व धीमा बना दिया। डा वि ने मुम्बई व चेन्नई में 7वीं व 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक प्रसंस्करण गतिविधियों के लिये स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र (ए एम पी सी)[6] प्रारम्भ किये जो कि क्रमशः 1993 व 1996 में प्रचलन में आये। इन ए एम पी सी के उपयोग पैटर्न ने यह संकेत दिया कि इन प्रणालियों का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि डाक का मानकीकरण नहीं किया गया था जिससे इन मशीनों पर इसे प्रसंस्करण के लिये अनुपयुक्त कर दिया।

सी ए जी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संख्या 2007 का पी ए 1 के पैराग्राफ 1.14.1 व 1.14.2 में मुम्बई व चेन्नई में ए एम पी सी के कम उपयोग पर टिप्पणी की गई थी। मंत्रालय ने ए एम पी सी के कम उपयोग के कारण बताते समय अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (जुलाई 2008) में भी बताया था कि विभाग डाक वस्तुओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक था तथा 11वीं योजना के दौरान इसके लिये संरचनात्मक अभ्यास सुनियोजित किया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि 11वीं योजना के दौरान भी दिल्ली व कोलकाता में प्रतिष्ठापित ए एम पी सी का सकल रूप से कम उपयोग हुआ था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैं:

ए एम पी सी के अधिप्राप्ति व उपयोग से सम्बन्धित अभिलेखों (मई 2014 व फरवरी 2015 में अद्यतन) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विक्रेता की तकनीकी बोली के अनुसार, सभी प्रकार की वस्तुयें उदाहरणार्थ, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड आदि ए एम पी सी के माध्यम से संसाधित किये जा सकते थे। तथापि, यह देखा गया था कि केवल प्रथम श्रेणी की अपंजीकृत मानकीकृत डाक अर्थात् व्यवयायिक डाक व स्पीड पोस्ट ही ए एम पी सी के माध्यम से छांटी गई थी। इसके अतिरिक्त, ए एम पी सी के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रसंस्करण नहीं होने के कारण दिल्ली व कोलकाता में क्रमशः 42 व 30 प्रतिशत डाक (जनवरी 2013 से जुलाई/अक्तूबर 2045)एम पी सी के माध्यम से संसाधित की जा सकती थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

(संख्या लाख में)

केन्द्र	औसतन दैनिक डाक प्राप्ति	ए एम पी सी द्वारा छाँटी गई औसतन डाक	छाँटी गई डाक की दैनिक प्रतिशतता
दिल्ली (अक्तूबर 2014 तक)	7.76	3.26	42
कोलकाता (जुलाई 2014 तक)	5.41	1.64	30

उपरोक्त तर्क की पुष्टि इस तथ्य से भी हुई थी कि मुख्य महाडाकपाल ने डा वि को सूचित किया (सितम्बर 2013) कि डाक का केवल 40 प्रतिशत ही ए एम पी सी के माध्यम से छांटा जा सका था और शेष हाथ द्वारा छांटी जा रही थी। यह भी बताया गया था कि ए एम पी सी के प्रतिस्थापन के बाद दिल्ली में मानव श्रम पर व्यय वास्तव में बढ़ गया था। इस प्रकार भारतीय डाक मानक की आवश्यकताओं के साथ ए एम पी सी की असंगतता के परिणामस्वरूप इन ए एम पी सी का असंतोषजनक कार्य निष्पादन व कम उपयोग हुआ।

6 प्रत्येक ए एम पी सी में आप्टीकल करेक्टर रीडर (ओ सी आर), पत्र छंटाई मशीन (एल एस एम), मिक्स छंटाई मशीन (एम एस एम) आदि होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर (अगस्त 2015) मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र आदि इस प्रकार की वस्तुओं की छंटाई न करने का कारण था कि ऐसी वस्तुओं की मात्रा बहुत कम थी तथा इसलिये उन्हें पत्र छंटाई मशीनों के माध्यम से छांटा गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि डाक के मानकीकरण के लिये निधि परिमंडलों को आबंटित की गई थी, तथापि डाक के मानकीकरण के सम्बंध में प्रत्याशित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त डाक का मानकीकरण स्वचालित छंटाई के लिये अहम आधार था तथा डा वि इस पहलू को आगे बढ़ा रहा था परन्तु हमारे देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र तथा ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी प्रतिशतता के कारण वांछित सफलता प्राप्त नहीं की गई है। अंत में यह आम जनता ही है जिसे मानकीकृत लेखन सामग्री का उपयोग करना तथा डाक में सही पता लिखना पड़ता है।

इसलिये, डा वि की स्वीकृति कि 100 प्रतिशत स्पीड पोस्ट व व्यवसायिक डाक वस्तुयें ए एम पी सी के माध्यम से नहीं छांटी गई हैं, लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करती है कि डाक का गैर मानकीकरण ही न केवल कमियों वाला है बल्कि भारतीय डाक मानक के साथ ए एम पी सी की असंगता भी इन ए एम पी सी के असंतोषजनक निष्पादन व कम उपयोग का कारण हैं। यद्यपि डा वि ने बताया था (जुलाई 2008) कि डाक मानकीकृत करने के लिये कदम उठाये जा रहे थे, परन्तु इसे आज तक प्राप्त नहीं किया गया था। डा वि को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ए एम पी सी का अभीष्टतम उपयोग करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्याय -IV
इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग

4.1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अनुबंध प्रबंधन वेब होस्टिंग तथा एप्लिकेशन डेवलपमंट में कमियाँ

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) की स्थापना 1976 में इलैक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौधोगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) के अन्तर्गत एक सलंग्न कार्यालय के रूप में की गई थी और तब से यह निरन्तर विकास के लिये डिजीटल अवसरों को बढावा देने वाले और जमीनी स्तर तक ई शासन/ई–गवरनेंस एप्लीकेशन को पहुंचाने वाले मुख्य निर्माता के रूप में उभरा है। एन आई सी अपने सूचना संचार तकनीक (आई सी टी) नेटवर्क के माध्यम से, जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी एन इ टी) नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, का सस्थांगत सम्पर्क भारत के केन्द्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और अधिकांश जिला प्रशासन से है। एन आई सी सरकार मे ई–शासन/ई–गवरनेंस एप्लीकेशन चलाने में सहायक रहा है।

नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के साथ एन आई सी की सभी 29 राज्यों एवं 7 केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियों और भारत में 640 जिला केन्द्रों में क्षेत्रीय इकाईयॉ और 19 प्रशासनिक इकाईयॉ है। राज्य स्तर पर एन आई सी की राज्य/केन्द्र शासित इकाईयॉ सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूचना तन्त्र प्रदान करती हैं और जिला स्तर पर एन आई सी की जिला इकाईयॉ अपने जिला कार्यालयों को सूचना तन्त्र प्रदान करती है। एन आई सी का 2009-10 से 2013-14 का वित्तीय प्रारूप निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2009-10	439.67	86.88	526.55
2010-11	564.56	132.68	697.24
2011-12	576.62	153.96	730.58
2012-13	523.39	133.87	657.26
2013-14	523.01	129.38	652.39

स्रोतः बजट दस्वावेज

केन्द्र/राज्य सरकारों की 7000 से अधिक वेबसाईटों के प्रबंधन तथा आपदा रिकवरी केन्द्र नेटवर्क आपरेशन के सूचना तन्त्र के संचालन के लिये एन आई सी ने राष्ट्रीय और राजकीय डाटा केन्द्रों को मिलाकर अत्याधुनिक आई सी टी आधारभूत संरचना की स्थापना की है, जो कि मन्त्रालयों, राज्यों और जिलों को विभिन्न नेटवर्क के सचालन और सेवायें जैसे कि एस एम एस, इन्टरनेट, वीडियों कान्फरसिगं इत्यादि प्रदान करती है साथ ही देश में इन सेवाओं की क्षमता वृद्धि करती है।

एन आई सी केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित सरकारों की तरफ से परियोजनाओं का सचांलन और रखरखाव करती है। ऐसी परियोजनाओं को एन आई सी में भुगतान परियोजना के नाम से जानी जाती है जिसमें

8 मिशन मोड परियोजनायें (एम एम पी)[1] भी शामिल है। इन परियोजनाओं की गतिविधियों में सम्पूर्ण समाधान के लिये विशेष आवश्यकताओं जैसे कि हार्डवेयर और साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति शामिल है।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के बीच किये गये चुनिंदा सविदाओं की जांच की। लेखापरीक्षा कार्य एन आई सी के मुख्यालय, चयनित राज्यों[2] और जिला डाटा केन्द्रों में किया गया। सामान्य वित्तीय नियमों के साथ–साथ लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के प्रावधान, ई–प्रशासन, साईबर सुरक्षा आदि के लिये बनाये गये नियमों व कानूनों सेवायें प्रदान करने, वैबसाईटों का संचालन और परियोजनाओं को लेने के लिये और एन आई सी द्वारा अपनाये गये आन्तरिक दिशानिर्देश, लक्ष्यों और नीतियों का प्रयोग किया गया। लेखापरीक्षा नमूना स्तर पर किया गया इसलिये लेखापरीक्षा केवल उदाहरणार्थ है परिपूर्ण नहीं है।

4.1.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.1.1 संविदा प्रबन्धन

(क) अनुचित योजना के कारण कंप्यूटर एडेड डिजिटल मैंपिंग परियोजना में ₹ 12.10 करोड के हार्डवेयर और साफ्टवेयर का अनुपयोगी हो जाना और डिजीटल मैंपिगं पर ₹ 14.25 करोड का निष्फल व्यय।

कम्प्यूटर एडेड डिजिटल मैंपिंग (सी ए डी एम) परियोजना छः[3] शहरों के पांच[4] आधारभूत विभागों के नेटवर्क/सेवाओं को बनाने और रखरखाव के लिये उपयोगिता मैंपिगं प्रदान करता है। योजना आयोग ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ₹ 47.67 करोड की राशि संस्वीकृत की (फरवरी 2005) और इस परियोजना को 15 से 18 महीनों में पूरा किया जाना था। मार्च 2013 तक इस परियोजना पर कुल ₹ 35.39 करोड व्यय किया गया।

इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एन आर एस ए) व सर्वे आफ इडिया (एस ओ आई) द्वारा विकसित वेस मेप डाटा के साथ–साथ कम्प्यूटर हार्डवेयार व एप्लीकेशन साफ्टवेयर की जरूरत थी। हार्डवेयर व साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिये अप्रेल 2006 से जूलाई 2006 के दौरान ₹ 12.10 करोड़ के क्रय आदेश दिये थे जिसका विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-IX** में है। वेस मेप डाटा का कार्य (एरियल फोटोग्राफी व जियो कोडेड डिजिटल मेपिंग डाटा) एन आर एस ए व एस ओ आई को दिया था। इस उद्धेश्य के लिय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) एन आई सी व एन आर एस ए के बीच जून 2005 में निष्पादित हुआ था, एस ओ आई से कोई समझौता ज्ञापन नहीं हुआ। समझौता ज्ञापन के अनुसार वेस मेप डाटा 12 महीनों मे पूरा होना था। वेस मेप डाटा के लिये क्रय आदेश मई 2005 में एस ओ आई को दिया गया और मई 2005 से दिसमंबर 2007 तक एन आर एस ए को दिया गया था जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1 ई–कार्यालय, अप्रवास वीज़ा विदेशी पंजीकरण व ट्रेकिंग (आई वी एफ आर टी IVFRT), ई-अधिप्राप्ति ई–न्यायालय, सड़क परिवहन, इंडिया पोर्टल, कृषि व सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2 दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम।

3 चैन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई और बंगलौर

4 जल, सीवेज, दूरभाष नेटवर्क, विद्युत आपूर्ति, पुलिस विभाग

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	कार्य आदेश का क्रमांक व दिनांक	कार्य का क्षेत्र	कार्य की कीमत	निष्पादन की स्थिति
1	एस ओ आई	80 दिनांक 18 मई 2005	जियो–कोडेड डिजिटल डाटा फॉर अहमदाबाद, चैन्नई व मुम्बई	5.55	अहमदाबाद : अप्रैल 2010 चैन्नई : अप्रैल 2009 मुम्बई : जनवरी 2009
2	एन आर एस ए	912 दिनांक 03 अगस्त 2006	जियो–कोडेड डिजिटल मेपिंग डाटा फॉर बंगलौर	1.78	कार्य आदेश निरस्त 07 जुलाई 2011
3	एन आर एस ए	81 दिनांक 18 मई 2005	जियो–कोडेड फॉर हैदराबाद व बंगलौर	3.80	हैदराबाद : जून 2008 बंगलौर : अगस्त 2009
4	एन आर एस ए	875 दिनांक 14 जुलाई 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर अहमदाबाद व चैन्नई	0.53	उपलब्ध नहीं कराया
5	एन आर एस ए	913 दिनांक 03 अगस्त 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर कोलकाता, हैदराबाद व बंगलौर	1.53	अक्तूबर 2008
6	एन आर एस ए	922 दिनांक 10 अगस्त 2006	डिजिटल मेप कोडिंग फॉर कोलकाता	1.08	जून 2011
7	एन आर एस ए	921 दिनांक 10 अगस्त 2006	एरियल फोटोग्राफी फॉर मुम्बई	2.09	कार्य आदेश निरस्त (जुलाई 2011)
8 (क)	एन आर एस ए	2173 दिनांक 14 अगस्त 2007	एरियल फोटोग्राफी फॉर बंगलौर	0.43	अक्तूबर 2009
(ख)	एन आर एस ए	2173 दिनांक 14 अगस्त 2007	मैपिंग फॉर बैगलोर	2.70	कार्य आदेश निरस्त (जुलाई 2011)

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- कार्य आदेश में काम के पूर्ण होने की समय सूची की कोई क्लाज नही रखी गई थी। सभी प्रकरणों मे (निरस्त कार्य आदेशों को छोडकर) एरियल फोटोग्राफी व डिजिटल मेपिंग का कार्य वर्ष 2009 से 2011 के दौरान पूर्ण हुए तथा एस ओ आई व एन आर एस ए को ₹ 14.25 करोड़[5] राशि का भुगतान हुआ था।

- तीन निरस्त किये गये कार्य आदेशों मे (जो क्रम संख्या 2, 7 व 8 (ब) में दिखाये गये है) दो एन आर एस ए को अगस्त 2006 में व एक अगस्त 2007 मे जारी किये गये थे। तथापि एन आई सी इन कार्य आदेशों के क्रियान्वयन को मानीटर करने मे असफल रहा। एन आर एस ए ने फरवरी 2010 मे आवेदन किया कि 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान नही होने के कारण वह इस स्थिति में नही है कि इन तीन क्रय आदेशों को निष्पादित कर सके। एन आर एस ऐ ने आगे बताया कि पुरानी दरों पर वह इन कार्य आदेशों के निष्पादन की स्थिति में नहीं होंगे। इस कारण एन आई सी के द्वारा जुलाई 2011 में इन कार्य आदेशों को निरस्त कर दिया गया। पुनः एन आई सी ने इन कार्य आदेशों को निरस्त करने में एक वर्ष से ज्यादा का समय लिया। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से यह पता नही चलता कि क्या एन आई सी ने किसी अन्य एजेन्सी से इस कार्य को करवाया।

5 ₹ 12.92 करोड़ जमा सेवा कर

- बेस मेंप डाटा के कार्य की सम्पूर्णता सुनिशिचित किये बिना, एन आई सी ने जून 2006 से नवम्बर 2006 के दौरान ₹ 12.10 करोड़ के हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरणों की अधिप्राप्ति जारी रखी।
- जब तक (2009 से 2011 तक जैसा कि उपर तालिका में दिखाया गया है) एस ओ आई और एन आर एस ए बैस मैं. डाटा प्राप्त किया गया तब तक ₹ 12.10 करोड़ की लागत से खरीदे गये हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरण पुराने हो गये जैसा कि एन आई सी जून 2012 और जुन 2014 के परिपत्र से स्पष्ट है।
- वर्तमान में छः शहरों के पांच विभागों में से बैंगलोर और अहमदाबाद में प्रत्येक में पांच, कोलकाता में चार, मुम्बई में तीन और हैदराबाद और चेन्नई में दो सी ए डी एम का प्रयोग नही कर रहे है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित करने पर यह बताया गया कि विलम्ब का कारण रक्षा मंत्रालय से आवश्यक औपचारिकताओं को मिलने में देरी, और अन्य कारण जैसे कि हवाई जहाजों को उड़ाने के लिये पायलटों और आकाशीय फोटोग्राफी टीम के लिये मौके पर गार्डडो का अभाव था।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि हार्डवेयर की खरीद एक समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है और इसलिए इसकी खरीद से पहले ही डाटा मैपिंग का कार्य सम्पूर्ण कर लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिये था। एन आई सी ने एन आर एस ए द्वारा कार्य आदेशों के क्रियान्वय की जॉच नही की जिससे यह सुनिशिचित किया जा सकता कि बैस मैपिंग डाटा समय पर प्राप्त हुआ या नही जब कि कार्य आदेश मई 2005 से दिसम्बर 2007 तक जारी किये गये थे और एन आर एस ए ने अपना अभिवेदन फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया कि वह कार्य आदेशों के क्रियान्वयन की स्थिति में नही है। आगे उत्तर में विभिन्न स्थानो पर उपकरणो के उपयोगिता न होने के कारणों के बारे में कुछ नही बताया गया है।

इस प्रकार अनुचित योजना, जॉच का अभाव और विभिन्न चरणो में विलम्ब के कारण जून से नवम्बर 2006 तक ₹ 12.10 करोड़ की लागत से खरीदे गये हार्डवेयर और साफ्टवेयर उपकरण अप्रचलित हो गये। साथ में पुराने उपकरणो को न बदलने के कारण ₹ 14.25 करोड़ की लागत से बेस मैंपिग डाटा पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

(ख) एन पी आर परियोजना पर ₹ 3.74 करोड़ का फालतू खर्च।

दिल्ली में नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एन पी आर) डाटा के स्टोर व एन पी आर बायोमेट्रिक डाटा संग्रहण की वेबसाईट विकास/निगरानी की सुविधा सृजन व रखरखाव के लिये गृहमंत्रालय ने एन पी आर की योजना फेस-I के अन्तर्गत ₹ 90.45 करोड़ राशि की स्वीकृति (सितम्बर 2013) दी थी। परियोजना का अनुमोदन करते समय स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि (सितम्बर 2013) कि एन आई सी को परियोजना की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिये। इस के लिये लगभग 770 वर्गमीटर, भण्डारण के लिये वास्तविक जगह की आवश्यकता थी और एन पी आर डाटा के कार्यस्थल की तैयारी के समय तक वर्तमान एन आई सी नेशनल डाटा सेन्टर (एन डी सी) शास्त्री पार्क दिल्ली में अस्थायी रूप से रहना था।

उपयोगकर्ता मंत्रालय ने निर्णय लिया (सितम्बर 2013) कि संपूर्ण डाटा बेस को 2014 मध्य तक रखने के लिये प्रतिबद्ध जगह की आवश्यकता होगी और अलग एन पी आर सुविधा के प्रावधान का पता लगाने का निर्देश दिया। तदनुसार एन आई सी ने निर्णय लिया (जनवरी 2014) कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी एम आर सी) जो आंठवी मंजिल शास्त्री पार्क जहां एन डी सी में स्थित था में ₹ 675 प्रति वर्गमीटर की दर से 3522.20 वर्गमीटर सुपर बिल्डअप एरिया किराये पर लिया जाये।

डी एम आर सी ने जनवरी 2014 में आंवटन पत्र जारी किया जिसमें 31 जनवरी 2014 तक ₹ 6.59 करोड़ के भुगतान के लिये भी निवेदन किया था जिसमें लाइसेंस शुल्क का अग्रिम (₹ 3.21 करोड़), रखरखाव प्रभार (₹ 0.51 करोड़), जल प्रभार (₹ 0.02 करोड़) और वापसी योग्य सुरक्षा जमा (₹ 2.85 करोड़) था। एन आई सी ने 24 मार्च 2014 से 29 मार्च 2014 की अवधि मे तीन किश्तों मे जमा का भुगतान किया था । आंवटन पत्र निर्धारित करता है कि एन आई सी को भुगतान के 29 वे दिन या उससे पहले (27 अप्रेल 2014)[6] फ्लोर का आधिपत्य लेना था और यदि उस दिनांक तक आधिपत्य नहीं लेते है तो यह समझा जायेगा कि परिसर का 27 अप्रेल 2014 को कब्जा ले लिया है। रखरखाव प्रभार वास्तविक कब्जे की दिनांक से या 27 अप्रेल 2014 जो भी पहले हो से शुरू होना था। किराया (लाइसेंस शुल्क) सुसज्जित करने की अवधि 45 दिनों को मानने के बाद प्रभारित होगी। एन आई सी ने नियत की गई तारीख 27 अप्रेल 2014 तक परिसर का कब्जा नहीं लिया था। इसलिए रखरखाव प्रभार का दायित्व 27 अप्रेल 2014 से और उसका किराया 12 जून 2014 (27 अप्रेल 2014 से 45 दिन) से शुरू हुआ।

इसी दौरान एन आई सी (दिसंबर 2013 से मार्च 2014) ने छः 500 टी बी (टेरा बाईट) स्टोरेज हार्डवेयर और सम्बंधित साफ्टवेयर ₹ 35.20 करोड़ कीमत की अधिप्राप्ति की जो कि एन आई सी डाटा केन्द्र में चिन्हिन स्थान पर अस्थायी रूप से स्थापित किये। जो अभी तक बेकार रखे थे (नवम्बर 2015) इस परियोजना में फरवरी 2014 से मई 2014 तक जनशक्ति को लगाने मे व्यय ₹ 0.52 करोड़ हुआ था जिसे जून 2014 से बंद किया गया था।

लेखापरीक्षा संविक्षा बताती है कि मार्च 2014 में प्रथम वर्ष का अग्रिम ₹ 3.74 करोड़ जिसमें लाइसेंस शुल्क का अग्रिम (₹ 3.21 करोड), रखरखाव प्रभार (₹ 0.51 करोड़) और जल प्रभार ₹ 0.02 करोड़) शामिल था का भुगतान मार्च 2014 में करने के और मई 2014 में परिसर का कब्जा लेने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया (अक्तूबर 2015) परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ फालतू खर्च हुआ। इस कारण परियोजना के लिये प्राप्त हार्डवेयर एन आई सी परिसर में बेकार पड़े हुए थे और उसके उपयोग करने के अवसर भविष्य मे बहुत कम थे। आई टी हार्डवेयर के सीमित जीवन काल को देखते हुये (पांच वर्ष), यहां यह भी अवसर थे कि उपकरण बगैर उपयोग किये अप्रचालित हो जायेंगे।

इसे इंगित करने पर यह बताया गया (अप्रेल 2015) कि परियोजना डी ई आई टी वाई द्वारा समीक्षा की जा रही थी। एन आई सी ने आगे बताया (जूलाई 2015) कि कार्य के स्थान को तैयार करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कनस्ट्रकशन कारपोरेशन (एन बी सी सी)से अनुबंध प्रक्रिया अप्रेल 2015 में प्रांरभ हुई। एन बी सी सी के साथ 20 मई 2015 को एम ओ यू हस्ताक्षरित हुआ था। एन बी सी सी ने डाटा केन्द्र के

6 दिनॉक 10 जनवरी 2014 के आंबटन पत्र के अनुसार अग्रिम जमा की प्राप्ति के बाद, कब्जा जल्दी से जल्दी दे दिया जाना था किन्तू इसे एल ओ ए (अर्थात 10 जनवरी 2014) के जारी होने की तारीख से 29वें दिन से ज्यादा देरी नही होना थी एल ओ ए के जारी होने की तिथि से भुगतान के 29वें दिन बाद एन आई सी का प्रतिनिधि परिसर लेने नही आता तो उस दिन से एन आई सी को परिसर सौपा हुआ माना जावेगा। इस प्रकरण में 29 मार्च 2014 को अन्तिम भुगतान जमा हो गया था इसलिये कब्जा सौपने की तिथि जमा के भुगतान कि तिथि से 29वें दिन उदाहरणर्थ 27 अप्रैल 2014 ली जा रही है।

लिये एक परियोजना कनसलटेन्ट अनुरोध सृजन और निष्पादन एजेंसी के चयन प्रस्ताव के लिये अनुबंधित किया और जैसे ही एजेंसी का चयन होता निर्माण का कार्य आंठवी मंजिल पर प्रारंभ होना था। कार्य पूर्ण होने पर हार्डवेयर 3री मंजिल से 8वीं मंजिल पर स्थान्तरित होना था।

तथ्य यह था कि डी एम आर सी से किराये पर ली गई परिसर का उपयोग एन आई सी करने की स्थिति में नही था एवं इसके निकट भविष्य में उपयोग होने के अवसर भी कम थे जैसा कि एन आई सी का जवाब बता रहा था। इस प्रकार एन आई सी की ओर से निक्रिष्यता के कारण न केवल ₹ 3.74 करोड़ का किराया व रखरखाव पर फालतू व्यय हुआ बल्कि हार्डवेयर व साफ्टवेयर जो कि अनुपयोगी रहे की प्राप्ति पर किया गया खर्च ₹ 35.20 करोड़ व्यर्थ रहा।

(ग) एन आई सी ई–कोर्ट परियोजना के अधीन वेंडर कार्य निश्पादित करने की विफलता से ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त नहीं कर सका।

ई–कोर्ट परियोजना एन आई सी को कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में सौंपी गई थी (सितम्बर 2010)। एन आई सी ने ई–कोर्ट परियोजना के अधीन वेंडर के इमपेनलमेंट के द्वारा आपूर्ति, परीक्षण व कम्प्यूटर हार्डवेयर का अनुरक्षण हेतु खुली निविदा दी थी (मई 2011)। नवम्बर 2011, में मैसर्स एच सी एल इन्फोसिस्टम लिमिटेड को हार्डवेयर तथा एल ए एन मदों की अधिप्राप्ति के लिये इमपैनल में डाला गया था जोकि 24 माह की अवधि के लिये 14 नवम्बर 2011 से 13 नवम्बर 2013 तक जिलों व अधीनस्थ कोर्ट में ई–कोर्ट परियोजना के कार्यन्वियन के लिये था, इसमें एक वर्ष से अधिक विस्तार का प्रावधान था। इमपेनलमेंट की वैधता सितम्बर 2014 तक बढ़ा दी गई थी।

डॉलर भिन्नता के कारण कीमत में संशोधन के लिये निविदा दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, निविदा के खंड 19.14.1 व 19.14.2 में अनुबद्ध था कि यदि पूर्तिकार क्रय आदेश स्वीकार करने में विफल रहा तो इमपेनलमेंट के विरूद्ध प्राप्त बोली सुरक्षा व बैंक गारंटी जब्त कर दी जाएगी तथा इमपेनलमेंट रद्द कर दिया जायेगा। वेंडर द्वारा प्रस्तुत ₹ 2 करोड़ की बैंक गारंटी 23 अगस्त 2014 तक वैध थी, जिसे पुनः नवीनीकरण नहीं किया गया था।

एन आई सी ने ई–कोर्ट परियोजना के अधीन विविध स्थलों के लिये मैसर्स एच सी एल इन्फोसिस्टम लिमिटेड को 586 क्रय आदेश नवम्बर 2011 से फरवरी 2014 को दिये थे। यह देखा गया था कि वेंडर ने अगस्त 2013 से क्रय आदेश का क्रियान्वयन करना बंद कर दिया था तथा रू0 के विरूद्ध डॉलर का के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दरों में और संशोधन करने का अनुरोध किया था (दिसम्बर 2013)। मामला प्रवर्तक मंत्रालय अर्थात् विधि व न्याय मंत्रालय (वि व न्या मं) को भेजा गया था (अप्रैल 2014) वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके इसने एन आई सी से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा था (07 जुलाई 2014) ताकि निक्सी एमपेनल्ड वेंडर स्वीकार करके जितना शीघ्र सम्भव हो, मदों की वैकल्पिक अधिप्राप्ति शीघ्र की जा सके तथा उनको बताई गई संविदा के अनुसार वर्तमान वेंडर के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जा सके। इस बीच, वेंडर ने बताया (जून 2014) कि फर्म कीमत संशोधन के बिना ₹ 9.45 करोड़ के 100 क्रय आदेशों के आदेश निष्पादित नहीं कर सकी। मई 2015 तक 100 क्रय आदेंशों से सम्बन्धित कार्य निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि प्रर्वतक मंत्रालय की सलाह के अनुसार वेंडर के विरूद्ध कार्रवाही करने के लिये पर्याप्त समय नहीं था, एन आई सी सम्बन्ध प्रयोक्ता ग्रुप अर्थात् निविदा प्रक्रिया खंड व वित्तीय विंग में समन्वय की कमी के कारण बैंक गारंटी जब्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, वेंडर को ब्लैक लिस्ट करने और न ही वेंडर के विरूद्ध क्षतिपूर्ति मांगने के लिये कार्रवाई की गई है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, एन आई सी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि महानिदेशक (एन आई सी) के निर्देशन व अनुमोदन मांगने के लिये प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है तथा तदनुसार, एन आई सी द्वारा कार्रवाई शुरू की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जुलाई 2014 में मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर, वेंडर की बैंक गारंटी जब्त करने तथा एन आई सी एस आई एमपेनल्ड वेंडर अथवा अन्य वेंडर द्वारा गैर निष्पादित परियोजनाओं की क्रय मदों के लिये शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये थी।

(घ) इन्टरनेट बैंडविथ को किराये पर लेने के लिए नई निविदा की जगह पुरानी निविदा को बढ़ाने के कारण ₹ 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) 06 नवम्बर 2008 ने स्पष्ट निर्देश दिये थे जिसमें अपेक्षित था कि निविदा को प्रारभिक वैधता के भीतर समयबद्ध तरीके से वैधता बढ़ाये बगैर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये। वैधता की अवधि की बढ़ोत्तरी दुर्लभ व आसाधारण प्रकरणों के मामलों में अपेक्षित थी ऐसे प्रकरणों में जहां वैधता की अवधि बढ़ानी थी, उक्त वैधता की अवधि को बढ़ाने व सही ठहराने के लिये मान्य वैध समय व तर्कसंगत आधार को अनिवार्य रूप से अभिलेखो में लाना चाहिये था।

एन आई सी ने 2008 से 2014 की अवधि के दौरान एन आई सी एन ई टी को इन्टरनेट बैडविथ देने के लिये तीन निविदाओं को अंतिम रूप दिया। निविदाओं की वैधता दो वर्ष थी और इसे आपस में सहमत नियम व शर्तो के आधार पर एक साल के लिये और बढ़ाया जा सकता था। निविदा को प्रसंस्करण और अन्तिम रूप देने के बाद दरो व इमपेनलड (सूचीबद्ध) एवं विस्तार के विवरण को नीचे दिया जा रहा है:

फर्म का नाम	निविदा का दिनांक	सूचीबद्ध होने की अवधि	इन्टरनेट बैंडविथ के लिये निविदा में सहमत दरें प्रति एम बी पी एस ₹ में	वास्तविक भुगतान की दर		टिप्पणी
				अवधि	इन्टरनेट बैंडविथ के लिये दर प्रति दर एम बी पी एस ₹ में	
टी टी एस एल	16.12. 2008	27.01.2009 से 26.01.2011	2988	27.01.2009 से 19.05.2010	2988	
				20.05.2010 से 26.01.2011	2208	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	27.01. 2011से 09.05.2011		27.01.2011 से 09.05.2011	2208	प्रस्तावित दरें ₹ 1200 प्रति एम बी पी एस (अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों के अनुसार)

रिलाइन्स	16.12. 2008	06.02.2009 से 05.02.2011	2988	06.02.2009 से 19.05.2010	2988	
				20.05.2010 से 05.02.2011	2208	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	06.02.2011 से 09.05.2011		06.02.2011 से 09.05.2011	2208	प्रस्तावित दरें ₹ 1200 प्रति एम बी पी एस (अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों के अनुसार)
टी टी एस एल	बढ़ी हुई	10.05.2011 से 08.06.2011	1480	10.05.2011 से 08.06.2011	1480 (अप्रैल 2011 में उद्धत दरों के अनुसार)	
रिलाइन्स और एयरटेल	अप्रैल 2011	09.06.2011 से 08.06.2013	1200 (45.66 प्रतिशत पिछले दरों जैसे 2208 की तुलना में कमी)	09.06.2011 से 30.06.2012	1200	
				01.07.2012 से 08.06.2013	1020	सूचीबद्धता की अवधि के भीतर समझौता के द्वारा घटी दरें
	बढ़ी हुई	09.06.2013 से 08.06. 2014	1020	01.07.2012 से 08.06.2013	1020	प्रस्तावित दरें ₹ 554 प्रति एम बी पी एस (पुरानी दरों जैसे 1020 पर 45.66 प्रतिशत में कमी)[7]
रिलाइन्स	फरवरी 2014	09.06.2014 के बाद	275			

लेखापरीक्षा जांच में निम्न पाया गया:

- एन आई सी ने नई निविदा के लिये जाने की जगह उपलब्ध निविदा की वैधता अवधि के समय को फिर से बढ़ा कर सी वी सी के निर्देशो का उल्लघंन किया।
- वर्ष 2008, 2011 व 2014 के लिये तीन निविदाओं के अनुसार इन्टरनेट बैडविथ के संबंध में दरें 2009 से 2014 के दौरान न्यूनतम 35 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रति एम बी पी एस पिछले वर्ष की तुलना में घटी थी।
- जैसाकि उपर्युक्त टेबल में दिखायेनुसार इन्टरनेट बैंडविथ के समान यूनिट के लिये कीमत घटते क्रम मे थी, एन आई सी ने घटती कीमत का फायदा नही लिया और नई निविदा के लिये जाने की अपेक्षा उपलब्ध सूचीबद्धता की अवधि को बढ़ाया। एन आई सी वर्तमान सुचीबद्धो को विस्तार देने की जगह पर यदि उपर बताये प्रस्तावित दरों के अनुसार समय पर नयी निविदा जारी करता तो वह सेवा कर सहित ₹ 15.00 करोड़ बचा सकता था जिसका विस्तृत **अनुलग्नक-X** में है।

लेखापरीक्षा के कहने पर, एन आई सी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) की संम्बन्धित निविदा समझौता की सहमत नियमों और शर्तो के अनुसार सूचीबद्ध को विस्तार प्रदान किया गया था।

7 पुरानी दर ₹ 2208 की तुलना में अप्रैल 2011 में उद्धृत दरों में 45.66 प्रतिशत की कमी थी। उसी आधार पर वढ़ी अवधि 09 जून 2013 से 08 जून 2014 के लिए प्रस्तावित दर ₹ 554 जिसे पुरानी दर ₹ 1020 में से 45.66 प्रतिशत की कमी करके लिया गया है।

मैंनेजमेंट का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि एन आई सी ने बताये गये मामलों में सी वी सी के निदेर्शो का उल्लंधन किया था। जहां वैधता की अवधि को बढ़ाये जाने की मांग दुलर्भ और असाधारण मामलों में होनी थी। जैसा बताया गया था कि वैधता की अवधि बढ़ाने को सही ठहराने के लिए इसे मान्य वैध समय व तर्कसंगत आधार को अनिवार्य रूप से अभिलेखो में लाना चाहिये था। इस प्रकार एन आई सी समय पर निविदा जारी न करने से घटती दरो का लाभ लेने में विफल रहा। परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय रूप ₹ 15.00 करोड़ के साथ–साथ सी वी सी ने निर्देशो का भी उल्लंधन हुआ था।

(ड़) भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) की दरों पर विचार न करने के कारण एस एम एस सेवाओं पर ₹ 3.62 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

एन आई सी ने (सितम्बर 2009) मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (टी टी एस एल) को शार्ट मेसेज सेवा (एस एम एस)– गेटवे सेवा को एक वर्ष के लिये सूचीबद्ध किया जो कि आगे एक वर्ष के लिये ओर बढ़ सकने योग्य थी (एन आई सी के विकल्प व विक्रेता के साथ आपसी अनुबंध पर) एस एम एस सेवा की सूचीबद्ध सहमत दरें निम्न थीं:

क्रम संख्या	एस एम एस की संख्या	प्रति एस एम एस दर पैसों में
1	10000 (0.01 मिलियन तक)	10
2	10001 से 50000 (0.01 से अधिक 0.05 मिलियन तक)	9
3	50001 से 100000 (0.05 से अधिक 0.1मिलियन तक)	8
4	100000 से अधिक (0.1 मिलियन से अधिक)	7.5

सूचीबद्धता आगे फिर एक वर्ष सितम्बर 2011[8] तक की अवधि के लिये बढ़ा (मार्च 2011) दी थी। एन आई सी ने एस एम एस के उपयोग में बढोतरी को ध्यान में रखते हुये टी टी एस एल के साथ समझौते पर गया और नवीनीकरण की अवधि के लिये फर्म ने निम्न दरों पर सहमति दी थी:

क्रम संख्या	एस एम एस की संख्या	प्रति एस एम एस दर पैसों में
1	0.1 करोड़ तक (0.1 मिलियन)	7.0
2	0.1 करोड़ से 1 करोड़ (1.10 मिलियन)	6.5
3	1 करोड़ से 2 करोड़ (10.20 मिलियन)	5.0
4	2 करोड़ से अधिक (> 20 मिलियन)	3.5

नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान सूचीबद्धता सितम्बर 2010 से प्रभावी थी एन आई सी ने भा सं नि लि से एस एम एस की दरों की जानकारी ली। भा सं नि लि ने 2 पैसे प्रति एस एम एस दो करोड़ से पांच करोड़ तक व एक पैसा प्रति एस एम एस पांच करोड़ से ज्यादा के लिये पेशकश (जनवरी 2011) की। यद्यपि भा सं नि लि की दरों टी टी एस एल से बहुत कम थी इस पर विचार नहीं दिया गया व टी टी

8 एन आई सी द्वारा यह ठेका नयी दरों पर अक्तूबर 2011 से अप्रैल 2012 तक के लिये बढ़ा दिया गया था इसे आपसी सहमति से नयी निविदा में एल1 की दरों के शर्त पर मई 2012 से मई 2013 तक फिर से बढ़ा दिया था।

एस एल की सूचीबद्धता यह कहते हुये बढ़ा दी गई थी कि भा सं नि लि वरच्यूल नम्बर[9] की तकनीकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भा सं नि लि ने पुल मैसेज सेवाओं को प्रदान करने को कभी इनकार नहीं किया। इसके बदले भा सं नि लि ने बताया कि पुश और पुल मैसेज सेवायें क्रमशः प्रदान की जायेगी। पुल मैसेज एक अलग सेवा होगी जिसके लिये अलग से छोटे कोड आवंटित होंगे। एन आई सी द्वारा पेशकश की गई सेवाओं पर प्रभार निर्भर होगा। भा सं नि लि द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व का शेयर एन आई सी आधारित प्रश्नों के उत्तर के आधार पर होगा। फिर भी न तो भा सं नि लि को मैसेंज सेवा संविदा कम दरो पर दी गई न ही भा सं नि लि के साथ पुल मैसेज सेवा की संभावित देरी के लिये कोई पूछताछ हुई।

- यातायात प्रतिवेदन से निर्दिष्ट होता है कि पुश एस एम एस 99 प्रतिशत था जबकि पुल एस एम एस केवल एक प्रतिशत था तथापि, सस्ती दर पर भा सं नि लि को पुश संदेश तथा टी टी एस एल अथवा किसी अन्य एजेन्सी को पुल संदेश देने के लिये कोई विकल्प नहीं बताया गया था। एन आई सी ने टी टी एस एल से कोई बातचीत भी नहीं की जिससे कि भा सं नि लि के समानन्तर दर पर एक अलग दर पुश संदेश के लिये दी जा सके।

- फरवरी 2011 में भा सं नि लि दरों पर विचार न करने के कारण, एन आई सी ने मार्च 2011 से मई 2013 में टी टी एस एल को उच्चतर दर का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़[10] का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक-XI** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, एन आई सी ने कोई उत्तर नहीं भेजा था, मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

4.1.1.2 सॉफ्टवेयर का विकास व वेबसाइटों का होसटिंग करना

(क) ई–कार्यालय ऐप्लीकेशन

भारत सरकार ने (दिसम्बर 2009) में एक मिशन मोड परियोजना इलेक्ट्रानिक कार्यालय (ई–कार्यालय), प्रारंभ की जिससे कि पारंपरिक सरकारी कार्यालयों को अधिक प्रभावी व पारदर्शी कार्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जा सके जिससे कि अत्यधिक कागजी कार्य के भार से बचा जा सके। परियोजना स्वतः ही पारदर्शिता के वांछनीय मूल्यों, कार्यक्षमता, जवाबदेही व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। उत्पाद में माडुल्स[11] का एक समूह है जिससे कि मिसिलों से संबंधित कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखे एच आर कोर्ट केस, आर टी आई आदि के कार्यों को इलेक्ट्रानिक तरीके से करने में बढ़ावा मिलेगा। जिससे सरकारी कार्यालयों के भीतर व उनके बाहर भी स्वचालित रूप से कार्य किया जायेगा। भारत सरकार ने एन आई सी को

9 एन आई सी पुश व पुल एस एम एस दोनों सेवायें प्रदान कर रहा है तथा पुल एस एम एस के भाग के रूप में वरच्यूल नम्बर अत्यावश्यक है क्योंकि एकीकृत मांग के साथ उसकी आवश्यकता है।

10 अगस्त 2013 में मैसर्स वेल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 मई 2012 से 31 मई 2013 लिये अंतिम रूप दी गई नई निविदा प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया गया था।

11 मिसिल प्रबन्धन प्रणाली (ई-मिसिल), ज्ञान प्रबन्धन प्रणाली (के एम एस), छुट्टी प्रबन्धन प्रणाली (ई-छुट्टी), कार्मिक सूचना प्रणाली (पी आई एस), टूर प्रबन्धन प्रणाली, सहयोग व संदेश सेवायें।

इस परियोजना को भारत के समस्त केन्द्रीय व राज्य सरकारों के कार्यालयों में लागू करने की जिम्मेदारी सौपी है।

ई–कार्यालय परियोजना के छह एप्लीकेशन माडुल्स की जांच परिक्षण के दौरान कई कमियों को पाया गया। कुछ महत्वपूर्ण कमियों का विवरण नीचे उल्लेखित किया जा रहा है:

- छुटटी प्रबंधन प्रणाली (एल एम एस) माडुल्य–

  छुटटी प्रबंधन प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी के खाते में कोई छुटटी शेष नहीं है तो व असाधारण अवकाश (ई एक्स ओ एल) छुटटी हेतु आवेदन दे सके।

- व्यक्तिगत सूचना प्रणाली

  i) अर्द्धवेतन छुटटी (एच पी एल) को तभी अद्यतन किया जा रहा था जबकि कोई कर्मचारी अर्द्धवेतन छुटटी के लिए आवेदन करना था। अर्द्धवेतन छुटटी को कर्मचारी के खाते में स्वचालित रूप से जब भी वह देय होती थी नहीं जोड़ा जा रहा था।

  ii) साफ्टवेयर स्वचालित रूप से 01 जनवरी व जुलाई को अर्द्धवार्षिक देय अर्जित अवकाशों को जोड़ नहीं रहा था। जब भी कोई कर्मचारी अवकाश पर जाना था तब 01 जनवरी व जुलाई को उसके जमा देय अवकाश को अद्यतन करे बिना अवकाश अवधि में घटाया जा रहा था।

  iii) सेवा पुस्तिका के भाग–IIIअ में एल टी सी का लाभ उठाने वाले कालम में एल टी सी हेतु ली गई छुटिटयों एवं अर्जित अवकाश के नकदीकरण का कोई विवरण नहीं था।

  iv) कर्मचारियों द्वारा सेवा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों के पुष्टिकरण के वार्षिक सत्यापन हेतु किये गये हस्ताक्षर डिजीटली संभव नहीं थे क्योंकि उन्हे डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। यहॉ तक कि सेवा पुस्तिका का प्रिंट आउट लेना भी संभव नहीं था जिससे कि मैनुअल हस्ताक्षर लिये जा सकें।

  v) अर्हक सेवा माडुल्य–विदेश सेवा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ड्रापडाऊन आईकन में कर्मचारियों की पोस्टींग के लिये संगठन/स्टेशन का नाम का काई स्थान नहीं था। जबकि ड्रापडाऊन में केवल देशों के नाम दर्शाये जा रहे थे। इसके आगे विदेशी नियोक्ता से छुटटी सेवा व पेंशन योगदान एल एस पी सी की देय राशि को दिखाने के लिये कोई फील्ड नहीं थी।

- यात्रा प्रबंध प्रणाली

  i) यात्राओं के संबंध में यात्रा परिवर्तन अवधि हेतु कोई फील्ड नहीं था।

  ii) ई–यात्रा व अवकाश प्रबंध प्रणाली के मध्य कोई भी समन्वय नहीं था जिससे कि यदि कोई कर्मचारी यात्रा पर छुटटी हेतु आवेदन देता है तो उसे स्वचालित रूप से छुटिटयों के अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा सके।

iii) जब कोई कर्मचारी यात्रा पर जाता है तो उस कर्मचारी के कार्य को दूसरे कर्मचारियों के कार्य से जोड़ने हेतु नियत्रण अधिकारी के पास कोई प्रावधान नहीं था।

- मिसिल प्रबंधन प्रणाली

i) ई–फाईल – यदि कोई कर्मचारी ई–फाईल में कोई टिप्पणी लिखता है तो इसके लिए कुछ संदर्भो की आवश्यकता होती है जो कि अधिकतर ज्ञान माडूल्स प्रणाली (के एम एम) में होते है। परन्तु ई–फाइलों में के एम एस माडूल्य के संपर्क हेतु कोई भी लिंक नहीं था।

ii) ई–फाईल–इनबाक्सः– लम्बित फाइलों में किसी विषय को चिन्हित करने की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिससे कि महत्वपूर्ण और तत्कालीन फाइलों के निपटान को श्रेणीबद्ध किया जा सके।

iii) ई–फाइलों में शब्दों में होने वाली गलतियों को सुधारने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

- अन्य कमियां

मोटर कार, क्म्प्यूटर, एच बी ए, यात्रा, एल टी सी आदि को अग्रिम राशि के आवेदन व स्वीकृति हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

ऐसा बताये जाने पर (मार्च 2015) में एन आई सी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई कमियों को भविष्य में खुलने वाले ई–कार्यालयों में सम्मिलित करते हुये दूर की जायेगी।

(ख) कृषि बाजार सूचना तंत्र (एगमार्कनेट)

एगमार्कनेट परियोजना का प्रमुख उद्धेश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना तंत्र स्थापित करना है जिससे कि बाजार संबंधी सूचनाऐं व ऑकड़ों को तीव्रता से इकठा किया जा सके व इसके उपरांत इसका प्रयोग ठीक समय पर एक प्रभावी तरीके से किसानों व अन्य लोगों द्वारा किया जा सके। इस परियोजना का प्रयोजन किसानों द्वारा अच्छी कीमतों की उगाही व बाजार तक उनकी पहुॅच से संबंधित सूचना को इकठठा करने व उसका प्रसार करने का भी था। 11वीं योजना के अंत तक एगमार्कनेट ने पूरे देश में 7190 बाजारों में से 3241 बाजारों को आच्छांदित किया। इन सभी 3241 बाजारों में सभी हार्डवेयर एवं साफ्ट्वेयर एवं समवर्गी बाहय उपकरणों को आनलाईन ऑकड़े भरने हेतु स्थापित किया गया।

लेखापरीक्षा की नमूना जॉच के दोरान योजना में कमियॉ पाई गई जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार हैः

- 3241 बाजारों में से 1009 बाजारों ने स्थापना के बाद से कोई रिपोर्ट नहीं दी।
- वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचना जैसे के प्रत्येक फसल के लिए सरकार का समर्थन मूल्य नहीं दर्शाया गया।
- वेबसाइट पर सभी फसलों की कीमतों को दर्शाना चाहिए था परंतु नमूना जॉच में यह पाया गया कि मूल्य पर्चियों पर गन्ने के मूल्य को नहीं दर्शाया गया।

- इस आवेदन में विक्रय ऑकड़ों को भरने हेतु कोई स्थान नहीं था। इसीलिए एक विशेष बाजार में एक विशेष दिन में विक्रय की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए एक विशेष बाजार में एक विशेष दिन में किसी फसल के भण्डार शेष को पहचान पाना कठिन था जिसे भण्डार में रखा जा सके या किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं जैसे वर्षा, बर्फबारी, धुंध, कोहरा आदि के समय बचाव के लिये सुरक्षित रूप से भण्डार में रखा जाये।

एन आई सी/मंत्रालय द्वारा इस कथन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल

भारत का राष्ट्रीय पोर्टल देश के विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सूचनाओं को एकल खिड़की पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाली विभिन्न सूचनाएँ/सामग्री भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा जिला/राज्य/केन्द्र के स्तर पर किए गए सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह पोर्टल ई–शासन योजना के अन्तर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा डिजाइन और रख–रखाव किया जाता है।

राष्ट्रीय पोर्टल की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण खामियॉ पाई गई हैः

1. इस साइट पर मुख्यतया विषय, सेवायें, लोक समूह आदि टंगणी (Tabs) है। जब माउस को इन टंगणी प्रत्येक पर क्लिक करने पर उपविषय दिखाई देता है। यदि इन उपविषयों पर क्लिक करें, तो प्रासंगिक पृष्ठ खुल जाता है। जबकि पोपअप मेनू में मात्र दो या तीन राज्यों के नाम प्रत्येक सेवाएँ हेतु, दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कृषि पर क्लिक करें, तो केवल तमिलनाडु तथा राजस्थान का नाम दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार, शिक्षा के संबंध में मात्र तामिलनाडु, नागालैण्ड व सिक्किम का नाम दिखाई पड़ता है।

2. कर्नाटक राज्य के संबंध में निम्नलिखित त्रुटियॉ पाई गई हैंः

   क. 'नगरपालिका प्रशासनिक निदेशालय' का लिंक 'पृष्ठ नहीं मिला' प्रदर्शित करता है।

   ख. ''उपस्थिति निगरानी प्रणाली' का लिंक खुल नहीं पा रहा था (वेबपृष्ठ उपलब्ध नहीं है)।

   ग. ''मेरी सरकार' लिंक के तहत ''निजी सचिव/सचिवों आदि के नाम' रिक्त पृष्ठ प्रदर्शित कर रहा है।

   घ. 'आपातकालीन नम्बर' लिंक के अर्न्तगत 'रक्तदान' का पृष्ठ नहीं खुल रहा था (वेबपृष्ठ उपलब्ध नहीं था)।

3. उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैंः

   क. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 अपलोड नहीं किया गया था।

   ख. उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की 'आनलाइन' सेवायें नही पाई गई थी।

   ग. 'रक्षक दल' के लिए नामांकन फार्म अपलोड नही किया गया था।

इस प्रकार यह पोर्टल सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नही करा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (मार्च 2015) द्वारा प्रत्युत्तर दिया कि राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण तथा उपलबधता सम्बन्धित स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उत्तर पुष्टि करता है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा आकड़ो व टूटी लिंको के एकीकरण का कार्य समय–समय पर उपयोगकर्ता विभाग के साथ समन्वय कर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

(घ) ई–खरीद पोर्टल

व्यय विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक आपूर्ति पोर्टल (सी पी पी पोर्टल) को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) को इस पोर्टल की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

पोर्टल का प्राथमिक उद्धेश्य अपने–अपने राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, निदेशालयों, संवैधानिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, उपक्रमों/बोर्ड़ों के बीच में किए जाने वाली खरीद सम्बन्धी जानकारी के लिए एकल बिन्दु पहुंच प्रदान करना था। मिशन मोड परियोजना पोर्टल पर यू आर एल http://eprocure.gov.in/mmp से पहुँचा जा सकता है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ यू आर एल सुचारू रूप से कार्य नही कर रहे हैं/ जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:

गृह पृष्ठ	अगली स्क्रीन	टिप्पणी
एम एम पी से सम्बन्धित निर्देश	ई–खरीद के लिए मार्ग दर्शन	पृष्ठ नहीं मिला
नियम एवं प्रक्रिया	आन्ध्रप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	शेष 21 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नियम एवं प्रक्रियों को अपलोड नहीं किया गया था
डाउनलोड करना	नोडल अधिकारी निर्माण प्रपत्र	नहीं मिला
	एम एम पी ई–अधिप्राप्ति पोर्टल इमेज	नहीं मिला
राज्य ई–निविदा पोर्टल	चार राज्य पोर्टल (आन्ध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम तथा गुजरात) कार्य कर रहे है।	1. दादरा तथा नगर हवेली–फाईल या यू आर एल नहीं मिला 2. अडंमान–403: निषिद्ध, प्रवेश निषेद्ध 3. शेष 29 राज्य जुड़े हुए नहीं थे
ई–खरीद मानचित्र		1. छः राज्यों को ग्रे के साथ चिन्हित किया गया है तथा अन्य राज्यों को लाल–ईट से चिन्हित रंगो का संकेत इंगित नही किया गया है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वेबपृष्ठ मध्य प्रदेश (http://mpeprocurement.gov.in) एम एम पी में होस्ट किया गया था व बिहार (https://www.eproc.bihar.gov.in) परन्तु राज्य वेबसाइटों से लिंक नहीं थे। (https://www.eproc.bihar.gov.in)

यह इंगित किये जाने पर, केन्द्रीय सूचना केन्द्र ने स्वीकार करते हुए प्रत्युतर दिया (अप्रैल 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई सभी कमियों को अद्यतन कर लिया गया है, जहॉ तक नियमों एवं प्रक्रियों

का प्रश्न है यह सूचित किया गया था कि यह सभी सूचनाएँ/तथ्य राज्यों के विशिष्ट नोडल अधिकारियों को प्रस्तुत करना है और उनको पुनःस्मरण कराया गया था।

(ड़) कृषि विभाग एंव सहयोगी नेटवर्क (डी ए सी एन ई टी)

कृषि विभाग के विजन 2020 प्रलेख ने इस बात की संभावना पर घ्यान दिया गया था कि आई सी टी के उपकरण न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र का नेटवर्किंग प्रदान करेगें तथा केन्द्र एंव राज्य सरकार के विभाग डेटाबेस का संग्रह होगें और कृषि आनलाईन की स्थापना करके, विचारों और सूचना के विनिमय द्वारा किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को एकजुट करेगें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, सूचना के अंतसक्रिय विनिमय के लिए, योजना बनाने के लिए, दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए एंव किसानों की मांग पर सभी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए (कृषि विभाग एंव सहयोगी नेटवर्क) डी ए सी एन सी टी वेबसाईट की रचना की गई।

डी ए सी एन सी टी वेबपेज के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित यू आर एल कार्य नहीं कर रहे थे।

- 'द्वितीय हरित क्रान्ति' क्षेत्र में 'मिसिल या निदेशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।
- 'जनमत सर्वेक्षण' क्षेत्र कोई भी परिणाम नही दर्शा रहा था। इसे 'सबमिट' पर क्लिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा था।
- भाषण → मंत्रियों के भाषण → 'मिसेल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं'
- 42 वी–सैट के उपयोग उपलब्ध नहीं थें। यह 'प्राप्त नहीं' दर्शा रहा था।
- बाजार मूल्य पर क्लिक करने के पश्चात एगमार्कनेट से जुड़ जाता था एंव तिथियां दर्शा रहा था परन्तु तिथियों पर क्लिक करने पर बाजार मूल्य नहीं दर्शा रहा था।
- निदेशालय पोर्टल के अन्तर्गत → कृषि विपणन विभाग → विपणन एंव निरीक्षण निदेशालय के अन्तर्गत 'मिसिल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।
- पादप निगरानी प्रतिवेदन के अन्तर्गत → पादप स्थिति एकीकृत कीट प्रबन्धन व्यवस्था, जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला के अन्तर्गत 'मिसिल या निर्देशिका उपलब्ध नहीं' दर्शा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2015)।

(च) भारत सरकार के वेब खोज इंजन में कमियां/त्रुटियां

मौजूदा खोज इंजनो जैसे गूगल, माईकोसाफ्ट बिंग इत्यादि ने विश्व व्यापी वेब हेतु खोज तकनीक की उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। खोज तकनीकी इसे उपयोग करने वालो को बड़ी मात्रा में संरचित एव असंरचित आकड़ो की सूचना उद्धृत करने के लिए सरल अंतपृष्ठ देता है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) ने इस को ध्यान में रखते हुए, (अप्रैल 2011) में सरकारी वेबसाईट्स के लिए भारत सरकार वेबखोज

मंच बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य को (अगस्त 2011) में सी–डैक पुणे को ₹ 7.90 करोड़ की लागत पर सौंपा गाया। सी–डैक पुणे द्वारा इस कार्य को जुलाई 2013 में पूर्ण किया गया।

भारत सरकार (जी ओ आई) खोज इंजन का निरीक्षण करने पर आडिट ने पाया

- भारतीय भाषाओं में खोज हेतु कोई प्रावधान नही था और हिन्दी ताथा उर्दू के अतिरिक्त चल कुंजीपटल भी उपलब्ध नही था।
- सामग्री प्रबन्धन हेतु, रैंगने वाले सूची व पहलू शुद्ध, प्रासंगिक एंव उचित नही थे जैसा कि नीचे विमर्श किया गया
    - o एमपी[12]–निजामाबाद के लिये खोजा गया–ससंद सदस्यों की वेबसाईट सी–डैक के प्रस्तावानुसार नही दर्शाई गई थी। अपितु संसद सदस्य का नाम भी नही दर्शाया गया था।
    - o महाराष्ट्र के लिए खोजा गया–इस पर वेब आधारित राज्यों के पते प्राप्त हो रहे थे परन्तु जनसंख्या क्षेत्रफल, राजधानी एंव आधिकारिक भाषा के विवरण नहीं प्रस्तुत कर रही थी।
    - o 'नवोदय विद्यालय' हेतु खोजा गया – अप्रासंगिक परिणाम मिल रहे थे।
    - o 'भारत में सेवाकर की दर क्या है'– सवाल पर प्रतिक्रिया नही दे रही थी। वेवसाईट ने सिर्फ सम्बद्ध पीडीएफ फाईलें एंव वेबसाईट एकीकृत संसाधन निधारिक (यू आर एल) पते ही दर्शाए।
    - o (जनवरी–2015 में) 'भारत के प्रधानमंत्री' के नाम की खोज की गई – यह डॉ मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दर्शा रही थी।
    - o वर्तनी जांच नहीं: i) जब एक प्रश्न जैसे कि 'आयकर' गलत टाईप हो गया तो प्रतिक्रियास्वरूप 'क्या आपका मतलब आयकर है' नहीं पूछा गया। परिणामस्वरूप अप्रासंगिक आंकड़े दिए गए बनस्पत उसके जो आय कर से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में वास्तव में प्राप्त होता। (ii) इसी प्रकार 'सेवा कर' के लिए 'सेवा कर' टाईप किए जाने पर प्रत्युत्तर में पूछा गया ''क्या आपका मतलब सेवाकर से है' परन्तु फलस्वरूप असम्बद्ध आंकड़े ही प्राप्त हुए बनस्पत उसके जो वांछित थे।
    - o सी–डैक के परियोजना प्रस्ताव में इंट्रानेट खोज प्रदान करना निर्धारित किया गया परन्तु इसे प्रदान नही किया गया। समझौते के अनुसार प्रतिक्रिया में लगने वाला समय तीन सैकण्ड था, परन्तु इसकी दर 15 से लेकर 60 सैकण्ड के बीच रही। वेबसाईट पर सवाल की जाने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाला समय एवं परिणामों की संख्या दर्शाने का प्रावधान भी नही था।

इन सब पर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने इस पर्यवेक्षकणों को स्वीकार मार्च 2015 में किया एवं संशोधनात्मक कदम उठाए गए।

12 संसद सदस्य

(छ) मोबाइल फोन के लिए असंगत वेबसाइट

तकनीक के द्रुत विकास के साथ मोबाइल फोन मात्र संचार उपकरण से बहुत सारी जानकारी और सेवाओं का दोहन करने की क्षमता वाला स्मार्ट फोन में विकसित हो गया है। आज एक मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई गई सेवायें, वॉइस कम्यूनिकेशन की अपनी मौलिक भूमिका से परे मूल्य वर्धित सेवाओं की श्रृंखला बन गई है।

ऐसा देखा गया कि एन आई सी की वेबसाइटें मोबाइल प्रौद्योगिकी सेलल्यूलर के लिये संगत नहीं है।

ऐसा इंगित करने पर यह कहा गया (मई 2015) कि एन आई सी सरकारी वेबसाइटों के लिये सामग्री प्रबंधन ढांचे के विकास की प्रक्रिया में था। यह ढांचा ओपन सोर्स तकनीक में विकसित किया जायेगा और सरकारी संस्थाओं को उनकी वेबसाइटों के माइग्रेशन के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्लेटफार्म पर माइग्रेट हुये वेबसाइट मोबाइल संवादात्मक डिजाइन सुविधा के अनुकूल होंगे।

तथ्य यह है कि एन आई सी वेबसाइटें मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिये संगत नहीं थी।

(ज) सरकारी वेबसाइटों में न्यूनतम सामग्री को शामिल न किया जाना

एन आई सी ने जनवरी 2009 में 'भारत सरकार की वेबसाइटों के लिये दिशार्निदेश (जी आई जी डब्ल्यू)' बनाया/तैयार किया था जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। दिशानिर्देश के पैरा 4.5.1 के अनुसार भारत सरकार की वेवसाइटों में नीचे दर्शायी गयी नौ न्यूनतम सामग्री होना चाहिएः

- विभाग का नाम (वैकल्पिक रूप से परियोजना का नाम, सेवा आदि जो भी लागू हो)
- राष्ट्रीय प्रतीक/लोगो (जैसा लागू हो)
- विभाग के बारे में (इसकी मुख्य गतिविधियां व कार्य सहित)
- साइट के सभी प्रमुख मॉड्यूल/भागों के लिए लिंक
- विभाग द्वारा प्रदान की गई सभी नागरिक सेवाओं के लिये लिंक
- वेबसाइट के हमसे 'संपर्क करें' पृष्ठ के लिए लिंक
- 'प्रतिक्रिया दें' पृष्ठ के लिए लिंक
- राष्ट्रीय पोर्टल के लिए लिंक
- खोज/साइट का (नक्शा) मानचित्र
- उपयोग की सेवा व शर्तें

इसके अलावा विभाग के पास पुराने दस्तावेजों के संबंध में एक स्पष्ट अभिलेखनीय नीति यह बताने के लिये होनी चाहिए कि दस्तावेज कितने समय तक ऑनलाइन रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इन पुराने दस्तावेजों को नियामक या कानूनी प्रयोजनों के लिये कभी कभार उद्घृत किया जा सकता था।

क. लेखापरीक्षा ने 526 सरकारी वेबसाइटों को सत्यापित किया और पाया कि मात्र 81 वेबसाइटों पर न्यूनतम सामग्री उपलब्ध थी और बाकी 445 वेबसाइटों में एक या एक से अधिक सामग्री नहीं था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुये यह कहा गया (नवंबर 2014) कि 'भारत सरकार के वेबसाइटों के लिये दिशानिर्देश' (जी आई जी डब्ल्यू) का पालन करने के लिये कदम उठाये गये लेकिन उपयोग कर्ता विभागों द्वार अनुपालन नहीं किया गया। सभी उपयोगकर्ता विभागों को जी आई जी डब्ल्यू के दिशानिर्देशों के पालन हेतु पुनः निर्दिष्ट किया जायेगा।

ख. एन आई सी की वेबसाइटों में यह देखा गया कि ज्यादातार वेबसाइटों के पास वर्षों से अभिलेखीय नीति नहीं थी वेबसाइटों में अभिलेखीय नीति का अनुपालन नहीं करने के कारण सर्वरों में जगह भरी रही जिसके कारण स्टोरेज सर्वरों की जबरदस्ती और अनावश्यक खरीद करनी पड़ी।

इंगित किए जाने पर यह जवाब दिया गया (मार्च 2015) कि ये नीतियां बैंक एंड नीतियां हैं और उनके अस्तित्व/कार्यान्वयन को संबंधित मंत्रालय/विभागों में जांच करने की आवश्यकता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन आई सी वेबसाइट को एन आई सी डाटा सेन्टर में होस्ट करने से पहले इन नीतियों को कार्यान्वियन करना सुनिश्चित करना चाहिये था।

(प) सुरक्षा लेखापरीक्षा के बिना ही वेबसाईट्स की होस्टिंग

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिये एन आई सी के दिशा निर्देशों के अनुसार वेबसाइट प्रबंधन टीमों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी वेबसाइटों का आयोजन के पहले व प्रमुख संशोधन के बाद सुरक्षा ऑडिट अधिकृत पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, एन आई सी, एन आई सी एन इ टी के पास कुल 7743 वेबसाइटें हैं उनमें से केवल 4585 वेबसाइटों का ऑडिट हुआ है, 1929 वेबसाइट का आडिट प्रक्रिया के तहत हैं और 1229 वेबसाइटों का ऑडिट नहीं हुआ है। उपरोक्त से यह भी देखा गया है कि 3158 वेबसाइटों का आयोजन बिना ऑडिट पूर्ण किये ही कर दिया गया है।

इस प्रकार सुरक्षा ऑडिट के अभाव में, एन आई सी ने 3158 वेबसाइटों की सुरक्षा से समझौता किया है। ओर साइबर हमले की संभावना के लिए उन्हें खुला छोड़ दिया है।

प्रबंधन ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2014) कि जरूरत की वजह से सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर वेबसाइटों का उद्घाटन/लांच किया गया था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के पाया कि एन आई सी के योजनाओं और परियोजनाओं के निष्पादन, विभिन्न परियोजनाओं के वेब एप्लीकेशन व डिज़ाईन ओर वेबसाईट के विकास के कामकाज में कमियां पाई गई थी।

एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन होने के नाते एन आई सी को सरकार में आई सी टी समाधान के उचित प्रमोशन और कार्यान्वयन हेतु एक उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए जो कि योजना व परियोजनाओं को उचित समय पर पूर्ण करे, निविदा प्रक्रिया में मितव्यता, सॉफ्टवेयर व परियोजना एप्लीकेशन पर दक्षता से काम करे एवं वेब साईट के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करें।

4.2 सी–डैक द्वारा पुणे में भवन निर्माण तथा जसोला, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण को प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब

सी–डैक पुणे हेतु भवन के पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रस्तावित भवन की लागत में ₹ 66.39 करोड़ की वृद्धि के अतिरिक्त ₹ 47.62 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध हुई। सी–डैक दिल्ली ने भी जसोला, नई दिल्ली में एक भूखण्ड अधिग्रहित किया और सितम्बर 2001 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान कर भौतिक कब्जा लिया। सी–डैक को अभी भी कार्य शुरू करना है (मार्च 2015) और समय समय पर विस्तार प्राप्त करने के लिए डी डी ए को ₹ 6.08 करोड़ के रचना शुल्क तथा दण्ड का भुगतान किया।

प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी–डैक) (पूर्व में भारत का इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति के रूप में मार्च 1988 में स्थापित किया गया था। समिति मूलतः एक अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) संस्था के रूप में स्थापित की गई थी जो कि प्रगत सूचना प्रौद्यौगिकी (आई टी) आधारित समाधानों के डिजाइन एवं विकास में शामिल थी। पुणे में मुख्यालय के साथ सी–डैक के भारत भर में 11[13] केन्द्र हैं।

सी–डैक, पुणेः

पुणे स्थित सी–डैक मुख्यालय पुणे के भीतर पाँच विभिन्न स्थानों पर स्थित किराये के परिसरों से कार्य कर रहा था। सी–डैक ने पाषाण पुणे में 1.50 एकड़ भूमि पर स्वयं के लिए भवन निर्माण करने हेतु एक प्रस्ताव डी ई आई टी वाई, संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मत्रांलय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007)। प्रस्तावित परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्तमान में किराये के पाँच भवनों (74,149 वर्ग फीट) में कार्यरत सी–डैक पुणे के सम्पूर्ण क्रियाकलापों को इसके प्रस्तावित 1.68 लाख वर्ग फुट कार्यात्मक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर किराये[14] पर व्यय की बचत के अलावा अन्य संचालन एवं प्रशासनिक लाभ[15] थे। डी ई आई टी वाई द्वारा परियोजना हेतु ₹ 49.80[16] करोड़ की प्रशासनिक अनुमति दी गयी थी (फरवरी 2008) जिसको की डी ई आई टी वाई तथा सी–डैक के मध्य 60:40 के अनुपात में साझा किया जाना था। परियोजना, स्वीकृति की तिथि से, दो वर्ष के भीतर (यानी फरवरी 2010 तक) पूर्ण की जानी निर्धारित थी।

प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु सी–डैक पूणे द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं (जुलाई 2008)। प्रस्तावित भवन में हाई वोल्टेज एसी, अग्नि सुरक्षा एवं लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त सिविल एवं विद्युतीय कार्य होने

13 बैगलुरू, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुम्बई, नोएडा, पुणे, सिलचर और त्रिरूआनन्तपुरम।

14 वर्तमान (मार्च 2015) में किराये भार ₹ 49.80 लाख प्रति माह है।

15 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे सी–डैक आदि के लिए विभिन्न स्थानों से विभिन्न दलों के बीच तकनीकी विचार विमर्श में सहजता, साझा उपकरणो का प्रतिरूपण एवं उनकी प्रचालन कीमतें किराये के भवन का अनुपयुक्त विन्यास के लिये अपेक्षित था।

16 भारत सरकार से अनुदान ₹ 29.88 करोड़ तथा सी–डैक निधियॉ से आंतरिक संग्रहण ₹ 19.92 करोड़।

थे। भवन को नियामक आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, भूकम्प, आकाशीय बिजली तथा पर्यावरण को पूरा करने के लिए डिजाईन किया जाना था। ₹ 61.73 करोड़ की बोली राशि के साथ मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एन सी सी एल) एल1 बोलीदाता था। चूँकि सफल बोलीदाता (एल1 बोली) की दर स्वीकृत लागत ₹ 49.80 करोड़ से अधिक थी अतः कार्य का क्षेत्र कम कर दिया गया और समस्त तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की बोलियों का कम किये गये कार्यक्षेत्र के आधार पर पुनः मूल्यांकन किया गया। इसमें ₹ 14.59 करोड़ के आंतरिक कार्य, फाल्स फ्लोरिंग (तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप) व सीवेज उपचार संयत्र, जिनको की अलग से एवं बाद में किया जाना था, शामिल नहीं थे। दो डीजी सेट्स जो कि प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थे, निविदा में सम्मिलित किए गए। मैसर्स एन सी सी एल पुनः ₹ 49.18 करोड़ की बोली राशि के साथ एल1 रहा। हालांकि सी–डैक इस तथ्य से अवगत था कि आँतरिक कार्यों आदि के बगैर प्रस्तावित भवन को उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वह आगे बढ़ा और डी ई आई टी वाई को अनुमोदन हेतु संशोधित आँकलन प्रस्तुत करने के बजाए मैसर्स एन सी सी एल को कार्य आदेश देने हेतु डी ई आई टी वाई का अनुमोदन प्राप्त किया (जनवरी 2009)।

सी–डैक ने इस शर्त के साथ एन सी सी एल को मई 2009 में कार्य आदेश जारी किया कि परियोजना कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 महीने में पूर्ण हो जानी चाहिए। मई 2009 के दौरान कार्य आरम्भ किया गया, लेकिन लागत बाध्यताओं को देखते हुये कार्य क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया गया (अप्रैल 2010)। मैसर्स एन सी सी एल द्वारा, कम किये गये कार्य क्षेत्र के अनुरूप, कार्य पूर्ण किया गया (सितम्बर 2011) और परियोजना पर व्यय की गयी कुल धनराशि ₹ 47.62 करोड़ थी।

इस बीच सी–डैक पुणे ने मूल योजनानुसार शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु बढ़े परिव्यय एवं अतिरिक्त धनराशि ₹ 16.12 करोड़ की आवश्यकता हेतु एक प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति (एस एफ सी) को डी ई आई टी वाई की अनुमति के लिए भेजा। (फरवरी 2011) डी ई आई टी वाई ने पुनरीक्षित प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा (सितम्बर 2011) क्योंकि माँगी गई अतिरिक्त धनराशि अनुमोदित परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक थी। तदोपरांत सी–डैक ने व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) की अनुमति हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2011)। बदले में, डी ई आई टी वाई ने सी–डैक को प्रस्ताव की किसी तृतीय पक्ष, अधिमानतः सी पी डब्लू डी, एन बी सी सी अथवा अन्य ऐसे सरकारी विभाग, से जाँच पडताल व पुनरीक्षित कराने की सलाह दी (फरवरी 2012)। यह प्रस्ताव डी ई आई टी वाई द्वारा सी–डैक को संशोधन हेतु पुनः लौटाया गया (अप्रैल 2012)। सी–डैक ने शेष कार्य हेतु एक संशोधित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत किया (सितम्बर 2012) जिसमें कुल परियोजना लागत ₹ 116.19 करोड़ की हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 66.39[17] करोड़ (₹ 116.19 करोड़ – ₹ 49.80 करोड़) अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता लागत वृद्धि (₹ 25.19 करोड़), कार्यक्षेत्र में वृद्धि (₹ 11.16 करोड़), अतिरिक्त मदों में कार्यान्वयन लागत (₹ 5.84 करोड़), वैधानिक एवं अन्य मदें जिन पर प्रारंभिक अनुमानों में विचार नहीं किया गया था (₹ 9.61 करोड़) तथा कार्यक्षेत्र से हटाये गये आंतरिक कार्य (₹14.59 करोड़) के कारण हुई। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग एवं डी ई आई टी वाई द्वारा निर्धारित पुनरीक्षण के बाद ई एफ सी की बैठक सम्पन्न हुई (अक्टूबर 2013) और प्रशासनिक अनुमति प्राप्त हुई (फरवरी 2014)। डी ई आई टी वाई ने संशोधित प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि उक्त कार्य को दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए (यानी फरवरी 2016 तक)।

17 केन्द्र सरकार से अनुदान ₹ 39.83 करोड़ (60 प्रतिशत) तथा आंतरिक संग्रहण से सी–डैक निधियाँ ₹ 26.56 करोड़ (40 प्रतिशत)

तदानुसार, शेष कार्य हेतु केन्द्रीय/राज्य पी एस यू से बोलियाँ आमंन्त्रित की गई (जुलाई 2014) और सी–डैक ने एल1 बोलीदाता मेसर्स इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (ई पी आई एल) के साथ ₹ 51.40 करोड़ का एक अनुबन्ध किया (जनवरी 2015)। ई पी आई एल को स्थल 26 फरवरी 2015 को सौंप दिया गया। अनुबंध के अनुसार, स्थल को सौंपने की तारीख से 15 महीने के भीतर कार्य पूर्ण होना था यानी मई 2016 तक।

लेखापरीक्षा द्वारा सी–डैक के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) ने निम्न को उदघाटित किया:

- निविदायें आमंन्त्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना की लागत स्वीकृत लागत की सीमा के भीतर थी और संशोधित अनुमोदन प्राप्त था, सी–डैक द्वारा परियोजना लागत हेतु यथोचित परिश्रम नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य स्वीकृत परिव्यय के भीतर पूर्ण न हो सका।

- यद्यपि, सी–डैक के पास कोई तकनीकी/अभियांत्रिकी विभाग नहीं है, इसने परियोजना प्राक्कलन तैयार करने के लिए सी पी डब्लू डी या अन्य केन्द्रीय/राज्य पीएसयू या निर्माण गतिविधियों में लगे हुये विभागों से संपर्क करने के बजाए एक निजी सलाहकार (मैसर्स किर्लोस्कर कंसल्टेंट्स लिमेटेड) पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप, प्राक्कलन सही रूप से तैयार नहीं हुये जिस कारण परियोजना हेतु बोलियाँ स्वीकृत लागत से अधिक थी, जो कि दोषपूर्ण योजना बनाने का परिचायक है। यह ई एफ सी द्वारा संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय देखा गया (अक्टूबर 2013) और कहा गया कि अनुमान गलत थे।

- शेष कार्य की स्वीकृति के लिए डी ई आई टी वाई को प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान योजना आयोग ने पाया (अगस्त 2013) कि प्रारम्भिक लागत प्राक्कलनों को तैयार करते समय यथोचित परिश्रम नहीं किया गया था तथा जब वास्तविक व्यय स्वीकृति लागत के 50 प्रतिशत सीमा से अधिक हो गया तब आर सी ई हेतु व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) से सम्पर्क करने के बजाय सी–डैक ने स्वीकृत बजट का लगभग 95 प्रतिशत व्यय करने के उपरांत आर सी ई हेतु अनुमोदन माँगा। सी–डैक को आर सी ई हेतु 2008 में ही अनुमोदन माँगना चाहिए था।

- सी–डैक पुणे द्वारा केवल ढाँचे के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं शेष कार्य को शुरू करने में पर्याप्त देरी के परिणामस्वरूप परियोजना अपूर्ण रही जिसके कारण लागत वृद्धि (₹ 25.19 करोड़) तथा किराये के परिसरों पर किराये (₹ 36.80[18] करोड़) के रूप में अतिरिक्त भार/व्यय ₹ 61.99 करोड़ (**अनुलग्नक XII तथा XIII**) के अलावा छः वर्ष से अधिक के लिए ₹ 47.62 करोड़ की पूँजी अवरूद्ध रही।

यह इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2015) कि:

- सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन के अनुसार कार्य को प्रारम्भ करने की मंशा से कार्य का क्षेत्र कम किया गया था और शुरू में केवल आंतिरक कार्य तथा कुछ अन्य मदें, जैसा डी ई आई टी वाई के अनुमोदन में वर्णित है, कम की गई थीं।

18 परियोजना का निर्धारित समाप्ति फरवरी 2010 थी। किराये पर परिहार्य व्यय की गणना अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के लिए की गई है जिसमें बढ़ोत्तरी की संभावना है अगर परियोजना के पूर्ण होने में और देरी होती है

- पाशान भवन के निर्माण का कार्य एन सी सी एल द्वारा सितम्बर 2011 तक जारी रहा जो कि कार्य को 2009 में उल्लिखित दर पर पूर्ण करने के लिए सहमत था तथा नवीन प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को अनुमोदन हेतु फरवरी 2011 में भेजा गया था। हालांकि, प्रशासनिक कारणों तथा ई एफ सी की लंबित मंजूरी के कारण स्वीकृति संसाधित नहीं की गई। प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2014 में प्राप्त हुई थी।

- संशोधित प्राक्कलन के अनुसार, लागत वृद्धि अनेक कारकों से हुई जिसमें संवैधानिक शुल्कों (लेवी), सिविल कार्य के दायरे में परिवर्तन, बैटरियों की क्षमता में वृद्धि, अनुसूची दरों में परिवर्तन के कारण लागत वृद्धि, आदि सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा को मंत्रालय के उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं:

- निविदाओं में आंतरिक कार्यों को छोड़कर भवन के ढाँचे का निर्माण कराने का निर्णय तथा बोलियों को खोलने के बाद परियोजना दायरे को पुनः घटाने का निर्णय उपयुक्त नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण परियोजना लागत खर्च करने के बाद भी भवन उपयोग में नहीं लाया जा सका।

- अनुमानित लागत से अधिक बोलियों के प्राप्त होने को परियोजना की देरी के लिए एक कारण के रूप में नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि योजना आयोग द्वारा देखा गया कि कार्य का दायरा घटाने के बजाय सी–डैक पुणे को 2008 में ही पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन हेतु अनुमति ले लेनी चाहिए थी।

- परियोजना पूर्व अध्ययन सारे मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये भली भाँति नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप प्रारंभिक स्वीकृत लागत एल1 बोलीदाता द्वारा उल्लेखित राशि के सापेक्ष अत्याधिक कम रही। लागत वृद्धि को समय पर संशोधित लागत प्राक्कलन की अनुमति प्राप्त कर बचाया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, डी ई आई टी वाई अंश के सहायता अनुदान ₹ 39.84 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1 करोड़ एवं 2015-16 के दौरान ₹ 1.5 करोड़ के अति अल्प बजट आवंटन को देखते हुये परियोजना मई 2016 तक पूर्ण होती नहीं दिखती। इस बीच सी–डैक, भवन के पूर्ण होने तक तथा सम्पूर्ण गतिविधियों के स्वयं के परिसर में स्थानान्तरित होने तक ₹12.69 करोड़ प्रति वर्ष (आज की दर पर) खर्च करता रहेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पित अन्य लाभ[19] भी सी–डैक द्वारा दोषपूर्ण योजना बनाने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण छः वर्ष से अधिक विलंबित रहे।

सी–डैक, दिल्ली:

मई 2001 में, सी–डैक दिल्ली को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) द्वारा लीज होल्ड पर जसोला में 3185 वर्ग मीटर का एक प्लाट उसके कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹ 1.52 करोड़ की लागत पर आवंटित किया गया था। भूमि का भौतिक कब्ज़ा सितम्बर 2001 में लिया गया। डी डी ए के आवंटन पत्र की

19 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जैसे सी–डैक आदि के लिए विभिन्न स्थानों से विभिन्न दलों के बीच तकनीकी विचार विमर्श में सहजता, साझा उपकरणों का प्रतिरूपण एवं उनकी प्रचालन कीमतें, किराये के भवन का अनुपयुक्त विन्यास।

धारा-xxii के अनुसार सी–डैक को भूमि/भूखण्ड के भौतिक कब्ज़ा लेने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के भीतर भवन का निर्माण पूर्ण करना था। लेकिन अभी तक (मार्च 2015), भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2008 में कुल अनुमानित लागत ₹ 17.25 करोड़, जिसमें डी ई आई टी वाई अंशदान ₹ 10.35 करोड़ और सी–डैक का ₹ 6.90 करोड़ था, के साथ प्राप्त कर ली गई थी। इस अनुमानित लागत को डी ई आई टी वाई के अंश ₹ 30.33 करोड़ और सी–डैक के ₹ 20.22 करोड़ के साथ फरवरी 2014 में स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) के अनुमोदन के अनुसार ₹ 50.55 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया।

सी–डैक दिल्ली के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2014) में यह पाया गया कि:

- भूमि के भौतिक कब्ज़े की तिथि से 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सी–डैक ने भूमि का उपयोग नहीं किया। भले ही सी–डैक ने उक्त कार्य हेतु 23 सितम्बर 2001 को वास्तुविद की छँटनी (शार्ट लिस्टिंग) के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर निर्माण कार्य के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी तथापि कोई भी अग्रेतर प्रगति नहीं पाई गई;

- बजाय भवन निर्माण कार्य शुरू करने के सी–डैक, डी डी ए से समय समय पर उक्त भवन के निर्माण के लिए विस्तार प्राप्त करता रहा। इन विस्तारों को प्राप्त करने के लिए (नवीनतम विस्तार सितम्बर 2016 तक प्राप्त) सी–डैक, डी डी ए को जमीन का किराया, संयोजन शुल्क तथा ब्याज/दण्ड देता आ रहा था। अभी तक, सी–डैक दिल्ली ने ₹ 6.08 करोड़ जमीन किराया, संयोजन शुल्क, ब्याज भूमि की कीमत के अलावा (₹ 1.52 करोड) का भुगतान किया है;

- क्योंकि सी–डैक दिल्ली, 14 वर्षों से भी अधिक बीत जाने के बाद भी अपने कार्यालय के भवन का निर्माण शुरू करने में नाकाम रहा, इसलिए इकाई अपने संचालन, किराये के परिसर से जारी रखने को विवश थी। जमीन किराया, संयोजन शुल्क आदि भुगतान करने के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर कहा गया है, सी–डैक दिल्ली अप्रैल 2004 से नवम्बर 2014 तक ₹ 4.04 करोड़ किराये पर लिए गए परिसरों के किराए के रूप में भुगतान कर चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर सी–डैक दिल्ली ने कहा (मार्च 2015) कि:

- जसोला भवन परियोजना प्रारम्भ में विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी करणों की वजह से अमल में नहीं लाई जा सकी तथा काफी लम्बे समय के लिये ठन्डे बस्ते में पड़ी रही।

- वर्ष 2007 में सी–डैक गवर्निंग काऊंसिल ने उक्त भूमि पर सी–डैक के भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुऐ स्वीकृत 100 एफ ए आर के सापेक्ष 150 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ ए आर) हेतु भवन की ड्राइंग डी डी ए को मई 2008 में प्रस्तुत की गई। डीडीए द्वारा एफ ए आर शुल्क के मुद्दे के कारण परियोजना प्रगति नहीं कर सकी।

- निर्माण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव डी ई आई टी वाई को जुलाई 2013 में प्रस्तुत किया गया जिसको डी ई आई टी वाई की एसएफसी ने फरवरी 2014 में 60:40 हिस्सेदारी के साथ स्वीकृत किया। परन्तु उनकी माँग के बावजूद, बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिए डी ई आई टी वाई द्वारा आवंटन नहीं किया गया था और इसलिए परियोजना में और देरी हुई।

- लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया परिहार्य व्यय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तव में फलदायी था कि जसोला भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 50 करोड़ से अधिक है।

सी–डैक दिल्ली का उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- सी–डैक का उत्तर स्वयं असामान्य विलम्ब की पुष्टि करता है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि परियोजना लम्बे समय तक ठण्डे बस्ते में पड़ी रही।

- भवन के निर्माण के लिए गवर्निंग काऊंसिल को अपनी स्वीकृति देने में लगभग छः वर्ष से भी अधिक समय लगा।

- फ्लोर एरिया आवश्यकता हेतु पहले से उचित योजना नहीं बनाई गई थी जिसके कारण परियोजना प्रगति नहीं कर सकी और बुरी तरह से विलंबित रही जिससे भवन की अनुमानित लागत ₹ 17.25 करोड़ से बढ़कर ₹ 50.55 करोड़ हो गई।

➢ चूँकि 2015.16 के दौरान डी ई आई टी वाई अंश के ₹ 30.33 करोड़ हेतु विस्तृत अनुदान माँग में राशि ₹ 1.50 करोड़ के अलावा बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी परियोजना के निकट भविष्य में पूर्ण होने पर संदेह है। इस प्रकार तथ्य यह बना रहता है कि 14 वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी इकाई अपने संचालन को किराये के परिसर से जारी रखने को विवश थी।

➢ प्रबंधन का तर्क कि भूमि पर व्यय की गई राशि, इस तथ्य के साथ फलदायक थी कि भूमि का वर्तमान मूल्य ₹ 50 करोड़ से अधिक है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भूमि का आवंटन एवं अर्जन विशिष्ट उद्देश्य के लिए था न कि मूल्य वर्द्धन के लिए।

इसके अतिरिक्त, आवंटित भूखण्ड (जसोला, नई दिल्ली) पर अर्जन के 14 वर्ष बाद भी तथा इसकी गवर्निंग काऊंसिल द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने के सात वर्ष बाद भी, भवन निर्माण में सी–डैक की निर्णयहीनता के कारण किराया, संयोजन शुल्क, ब्याज के रूप में ₹ 10.12 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.3 सी–डैक प्रबंधन के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण नोएडा से भूखण्ड क्रय करने में ₹ 91.78 लाख का परिहार्य भुगतान

सी–डैक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी भवन का निर्माण करने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश (यूपी) से 20,000 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड ₹ 1375 प्रति वर्ग मीटर की दर से लीज़ आधार पर क्रय किया। लीज़ डीड में भुगतान कार्यक्रम के अनुसार, सी–डैक को आवंटन राशि के भुगतान के बाद ब्याज सहित 30 अर्द्ध–वार्षिक किस्तें देनी थी। सी–डैक भुगतान कार्यक्रम से विचलित हो गया और केवल कुछ अवधि के लिए मूल राशि का भुगतान किया तथा इसके उपरांत एक मुश्त राशि का भुगतान किया। नोएडा ने सी–डैक के ब्याज मुक्ति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप सी–डैक को ₹ 477.68 लाख के सापेक्ष ₹ 569.45 लाख का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 91.78 लाख के परिहार्य भुगतान के अतिरिक्त ब्याज ₹ 31.54 लाख की हानि ऐसे अग्रिम भुगतान करने के कारण हुई।

प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी–डैक), नोएडा केन्द्र ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से नेशनल इन्सटीयूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (एन आई ए टी) भवन के निर्माण एवं स्थापना के उद्देश्य से 20,000 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड रियायती दर ₹ 1375 प्रतिवर्ग मीटर से 90 वर्ष की लीज़ पर प्राप्त किया। लीज़ डीड की शर्तों में से एक यह भी था कि निर्माण कब्ज़े की तिथि से छः माह के भीतर शुरू होना चाहिए तथा कब्ज़े की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर पूर्ण होना चाहिए।

लीज़ डीड में निहित भुगतान योजना के अनुसार, आवंटन राशि ₹ 27.50 लाख (कुल भूमि प्रीमियम ₹ 275 लाख का 10 प्रतिशत) के भुगतान के बाद, दिसम्बर 2001 में लीज़ डीड निष्पादित की गई तथा अवशेष प्रीमियम ₹ 247.50 लाख को ₹ 8.25 लाख की 30 अर्द्ध–वार्षिक समान किश्तों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्द्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चूक राशि (डिफाल्टेड राशि) पर विलम्बित समय के लिए ब्याज आरोपित किया जाना था। इस प्रकार भुगतान के कार्यक्रम का समय पर पालन करने के मामले में, सी–डैक द्वारा अवशेष प्रीमियम तथा ब्याज के रूप में 24 अप्रैल 2001 से 24 अक्टूबर 2015 तक ₹ 477.68 लाख का भुगतान करना था, जैसा **अनुलग्नक-XIV** में दर्शाया गया है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने उदघाटित किया (अगस्त 2014) किः

i. लीज़ डीड में उल्लेखित भुगतान योजना के उल्लंघन में सी–डैक ने अप्रैल 2001 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य नोएडा को छः अर्द्ध–वार्षिक किश्तों में केवल मूलधन का भुगतान किया।

ii. अपर सचिव, एम ओ सी एवं आई टी, डी ई आई टी वाई (पूर्ववर्त्ती डी आई टी) ने अक्टूबर 2003 में किश्तों पर ब्याज की माफी अथवा माफी की गैर व्यवहार्यता के मामले में नगदी भुगतान के आधार पर अवशेष प्रीमियम के समाधान हेतु नोएडा से सम्पर्क किया परन्तु नोएडा ने प्रतिक्रिया नहीं दी।

iii. सी–डैक प्रबंधन ने दिसम्बर 2003 में विवेकहीन व एक तरफा निर्णय लिया और 24 अर्द्ध–वार्षिक किश्तों के सापेक्ष ₹ 198 लाख का एक मुश्त भुगतान कर दिया।

iv. चूँकि भुगतान लीज़ अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गये थे, नोएडा ने ₹ 204.83 लाख की माँग उठाई (जुलाई 2011)। माँगी गई राशि का सी–डैक द्वारा अक्टूबर 2011 में भुगतान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, मई 2014 में, सी–डैक ने ₹ 117.12 लाख का भुगतान अवशेष भुगतान/दण्डात्मक ब्याज के रूप में किया।

v. इस प्रकार भुगतान कार्यक्रम से विचलन के कारण सी–डैक नोएडा ने पूर्व निर्धारित राशि ₹ 477.68 लाख के स्थान पर ₹ 569.45 लाख का भुगतान किया, जिस कारण ₹ 91.78 लाख का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इस प्रकार सी–डैक नोएडा द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण ₹ 91.78 लाख का परिहार्य व्यय होने के अलावा भारतीय स्टेट बैंक के प्राईम लेण्ड़िग रेट के आधार पर ₹ 31.54 लाख ब्याज की हानि हुई जिसका विवरण **अनुलग्नक-XV** में दर्शाया गया है।

प्रकरण मंत्रालय को मार्च 2015 के दौरान में भेजा गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुऐ उत्तर दिया (मई 2015) कि:

i. सी–डैक नोएडा ने शुरू में बिना ब्याज के छः किश्तो का उनकी नियत तिथियों पर भुगतान किया। वर्ष 2003 के दौरान, सी–डैक ने ब्याज शुल्क बचाने हेतु बची हुई 24 किश्तों का भुगतान एक ही बार में करने का प्रस्ताव दिया।

ii. अपर सचिव, डी ई आई टी वाई ने प्रकरण को अक्टूबर 2003 के दौरान सी–डैक नोएडा के साथ भी उठाया, जिन्होंने, एकमुश्त भुगतान को स्वीकार करते हुए, इंगित किया कि बकाया मुद्दे, यदि कोई हों, पर चर्चा की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये जाऐंगे।

iii. इसके उपरान्त, नोएडा प्राधिकरण ने सिवाय जुलाई 2011 में ₹ 204.83 लाख के मॉग पत्र को भेजने के अलावा 2003 से 2011 के मध्य किसी भी शेष भुगतान के लिए कभी नहीं कहा।

iv. सी–डैक अधिकारियों ने यह प्रकरण नोएडा के साथ 26 जुलाई 2011 की निजी बैठक के माध्यम से उठाया तथा अगस्त 2011 एवं सितम्बर 2011 में उनके साथ पत्राचार किया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नही रहा। सी–डैक ने पुनः दिसम्बर 2011, अक्टूबर 2013 और नवम्बर 2013 में भी नोएडा प्राधिकरण से सम्पर्क किया लेकिन नोएडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

v. चूँकि नोएडा प्राधिकरण ने सी–डैक द्वारा बकाया देयों का भुगतान न करने की स्थिति में भूखण्ड रद्द करने की धमकी दी थी अतः 14 अक्टूबर 2011 को आपत्ति के तहत ₹ 2.05 करोड़ का भुगतान समस्या का समाधान करने के लिए किया गया था।

vi. बाद में, नोएडा प्राधिरकण ने जनवरी 2014 और मई 2014 में शेष भुगतान और ब्याज के लिए क्रमशः ₹ 78.25 लाख और ₹ 38.87 लाख की दो और माँगें भेजी थी।

vii. समिति के हित में तथा कानूनी जटिलताओं से बचने हेतु, सी–डैक नोएडा ने क्रमशः ₹ 78.25 लाख और ₹ 38.87 लाख का भुगतान भी कर दिया तथा भुगतान भारत सरकार की समिति से अन्य राज्य संगठन को लीज अनुबन्ध धारा के अंतर्गत जारी किया गया था।

प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न कारणों से स्वीकार्य नही हैः

1. सी–डैक/ डी ई आई टी वाई (पूर्ववर्ती डी आई टी) ने ब्याज माफी एवं एकमुश्त भुगतान स्वीकार करने हेतु प्रकरण को अक्टूबर 2003 में ही उठाया। ब्याज में छूट देने के मामले को नोएडा के साथ उठाने के पहले भी, सी–डैक ने अप्रैल 2001 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य केवल मूल धनराशि का ही भुगतान किया।

2. नोएडा ने ब्याज माफी के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी और अपर सचिव के ब्याज माफी के अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा (नवम्बर 2003) कि मुद्दे यदि कोई हों, तो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनके बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. नेशनल इन्सटीयूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (एन ई ए टी) के भवन निर्माण एवं स्थापना के प्रयोजन हेतु सी–डैक को लीज पर भूमि देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

इस प्रकार, नोएडा से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बगैर, सी–डैक लीज डीड में निहित मूल भुगतान योजना से विचलित हुआ। इस विचलन ने ब्याज/दण्ड ब्याज को आकर्षित किया तथा परिणामस्वरूप ₹ 91.78 लाख के अधिक एवं परिहार्य भुगतान हुआ जिसको किए गए अग्रिम भुगतान पर प्राप्त होने वाले ब्याज को खोने के अलावा बचाया जा सकता था।[20]

4.4 सी–डैक पुणे द्वारा रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने में विफलता के कारण ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

यद्यपि, सी–डैक पुणे ने उद्योग निदेशालय, पुणे से 2005 में आई टी ई एस इकाई के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर लिया था, तथापि उन्होंने इसके पुर्नवैधीकरण के लिए 2008 के बाद प्रयास नहीं किया और उपयुक्त रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप पुणे में किराये पर लिए गये भवनों[20] के लिए 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान विद्युत देयों के रूप में हुआ।

पुणे स्थित मुख्यालय प्रगत संगणक विकास केन्द्र (सी–डैक) के पुणे में, किराए के परिसरों में अपने कार्यालय/इकाईयाँ है। वर्ष 2005 में सयुक्त निदेशक उद्योग, पुणे क्षेत्र ने सी–डैक पुणे को ''आईटी समाधान प्रदाता/क्रियान्वयनकर्ता'' की श्रेणी के अंतर्गत आईटी सक्षम सेवायें (आई टी ई एस) इकाई रूप में पंजीकरण प्रदान किया था।

20 एन एस जी आई टी पार्क/वैस्टइण्ड सेन्टर तथा पुणे विश्वविद्यालय परिसर

महाराष्ट्र की (आई टी/आई टी ई एस) नीति 2009ए के तहत (आई टी/ आई टी ई एस) इकाईयों को महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयुक्त के शुल्क दर आदेशों के तहत विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाएगी और ये विद्युत शुल्क के भुगतान से मुक्त होगी।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस ई डी सी एल) के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 01 अक्टूबर 2013 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटी उपभोक्ता (आई टी पार्क) वैध एल ओ आई पंजीकरण प्रपत्र के साथ, आई टी पार्क में स्थित आई टी/आई टी ई एस इकाईयों हेतु व्यक्तिगत कनेक्शनों के लिए एम एस ई डी सी एल को आवेदन करेंगे। यदि एच टी उपभोक्ता (आई टी पार्क) आई टी पार्क में स्थित उपर दर्शाए गए आई टी/आई टी ई एस इकाईयो के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं लेना चाहता तब वह एचटी उपभोक्ता एम एस ई डी सी एल को वितरण फ्रैंचाईजी (डी एफ) हेतु (एम ओ यू के जारिए) आवेदन करेगा। ऐसे प्रकरण में, आपूर्ति डी एफ अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो द्वारा संचालित होगी।

सी–डैक, पुणे में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2014) बताती है कि सी–डैक (लाईसेंस धारक) द्वारा भूस्वामियों (लाईसेंस प्रदाता) के साथ परिसरों को किराए पर लेने हेतु किए गए समस्त लीज और लाईसेंस अनुबन्ध में एक धारा थी कि ''लाईसेंस प्रदाता, लाईसेंस धारक एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. (एम एस ई डी सी एल) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध होने तक, लाईसेंस धारक, एम एस ई डी सी एल द्वारा लाइसेंस प्रदाता के नाम से संबन्धित फ्लोर हेतु सब मीटर के लिए जारी विद्युत बिल के अनुसार, उपयुक्त विद्युत प्रभारों का भुगतान करेगा, और त्रिपक्षीय अनुबन्ध होने के पश्चात बिल लाईसेंस धारक के नाम से प्राप्त होगे और लाइसेंस धारक एम एस ई डी सी एल को विद्युत प्रभारों का भुगतान करेगा। इसने इंगित किया कि सी–डैक स्वयं को मिलने वाली विद्युत रियायत से भलीभाँति परिचित था तथा जिसके लिए इसने अन्य पक्षों से नामतः भू स्वामी एवं एम एस ई डी सी एल से स्वयं के नाम पर एक अलग विद्युत कनकेशन हेतु आवेदन करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया था। भूस्वामियो को भी, इस धारा को स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति नहीं थी कि सी–डैक के पास अपना मीटर है तथा अपने नाम से विद्युत बिलों का भुगतान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कोड के प्रावधानों एवं आपूर्ति नियमन 2005 की अन्य शर्तों के अनुसार सी–डैक लाइसेंस प्रदाताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने नाम से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर सकता था।

हालांकि, सी–डैक ने न तो विद्युत कनेक्शन को अपने नाम पाने के लिए कोई प्रयास किया न ही वितरण फ्रैंचाईजी मार्ग हेतु आवेदन किया जिसके लिए वह महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस नीति 2009 के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर रियायती शुल्क दर पाने का हकदार था। इसके अतिरिक्त सी–डैक ने उद्योग निदेशालय द्वारा फरवरी 2005 में जारी आई टी ई एस इकाई पंजीकरण के नवीनकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाए, जो फरवरी 2008 में समाप्त हो गया।

इस कारण सी–डैक पुणे किराये पर लिये गये भवनों के स्वाामियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सब मीटरों की रीडिंग के आधार पर ₹ 3.40 से ₹ 7.01 प्रति इकाई की औद्योगिक दरों पर रियायती शुल्क दर का लाभ प्राप्त करने के बजाय ₹ 7.15 से ₹ 9.83 प्रति इकाई की उच्चतम दरों [21] से भुगतान करता रहा

21 वाणिज्यिक श्रेणी के अधीन शुल्क दर (एन एस सी आई टी पार्क/वेस्टइन्ड सेन्टर) तथा लोक सेवाओ/शिक्षण संस्थाओ पर लागू शुल्क दर (पूणे विश्वविद्यालय)

जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 (सितम्बर 2014 तक) की समयावधि के दौरान ₹ 4.78 करोड़ (**अनुलग्नक-XVI एवं XVII**) के परिहार्य अतिरिक्त व्यय के अलावा किराये के भवनों नामतः एन एस जी आई टी पार्क/वेस्ट एंड सेंटर एवं पुणे विश्वविद्यालय परिसर पर पुनः आवर्ती प्रभाव हुआ।

यह इंगित किये जाने पर (नवम्बर/दिसम्बर 2014), सी–डैक पुणे/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि:

i. रियायतों का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ता का प्रासंगिक श्रेणी में व्यक्तिगत कनेक्शन होना चाहिए एवं किराये के भवनों के विद्युत कनेक्शन भवन स्वामियों के नाम पर थे तथा सी–डैक को किसी भी भवन स्वामी ने व्यक्तिगत कनकेशन लेने के लिए अनुमति नहीं दी थी तथा रियायती शुल्क दर पाने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध आधार नहीं था। भवन स्वामियों ने परिसरों हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा जैसा ट्रॉसफारमर, स्विच गियर आदि पहले ही स्थापित कर दिया था।

ii. चूँकि भवन स्वामियों ने एम एस ई डी सी एल के साथ कोई फ्रैंचाइजी नहीं ली थी अतः सी–डैक व्यक्तिगत कनेशक्शन नहीं ले सका तथा भवन स्वाामियों के द्वारा भुगतान किये गये शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क का लाभ नहीं ले सका। एम एस ई डी सी एल से स्वीकृत दरों पर विद्युत बिल भवन स्वामियों के नाम पर जारी किये जा रहे हैं तथा सी–डैक प्रशुल्कों को एम एस ई डी सी एल द्वारा आरोपित की जा रही समान दरों पर कर रहा था।

iii. पुनः आगे कहा गया कि पुणे विश्वविद्यालय में किराए पर लिए गये आवास के संबंध में, पूणे विश्वविद्यालय द्वारा लोक सेवा श्रेणी के अंतर्गत रियायती शुल्क दर का लाभ लिया और विद्युत शुल्क के भुगतान की छूट के साथ सी–डैक को पारित किया। इस प्रकरण में यदि सी–डैक ने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए आवेदन किया होता तो भी नाम मात्र एक पैसा प्रति यूनिट की बचत होती।

iv. प्रकरण को मार्च 2015 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस ई डी सी एल) के पास भेजा गया जिसने सूचित किया कि पार्कों में आई टी/आई टी ई एस प्रयोजन के लिए आपूर्ति हेतु आवेदन करने वाली कम्पनियों को या तो वितरण फेंचाईजी मार्ग से संचालित होना होगा या प्रत्येक आई टी इकाई के लिए सम्बन्धित शुल्क दर श्रेणी के तहत व्यक्तिगत कनेक्शन लेना होगा। एम एस ई डी सी एल ने आगे कहा कि इस प्रकरण में कनेक्शन आई टी पार्क स्वामी के नाम है इसलिए औद्योगिक शुल्क दर सी–डैक पर लागू नहीं होगी, भले ही सी–डैक आई टी पंजीकृत इकाई है।

सी–डैक का उत्तर निम्न कारणों से स्वीकार्य नही है:

i. महाराष्ट्र विद्युत वितरण कोड के प्रावधानों एवं आपूर्ति नियमन 2005 की अन्य शर्तो के अनुसार, सी–डैक लाइसेंस प्रदाताओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने नाम विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लेना था तथा इस तरह से उपयुक्त रियायती शुल्क दर प्राप्त कर सकता था। रियायत शुल्क दर प्राप्त करने से हुई बचत ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि पर हुये प्रारंभिक बुनियादी व्यय को दीर्धकाल में पार कर सकती थी।

ii. यह तर्क कि भवनस्वामियों ने एम एस ई डी सी एल से फ्रैंचाईजी नहीं ली है और इसलिए सी–डैक व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं ले सका, तर्क संगत नही है क्योंकि एम एस ई डी सी एल के दिशानिर्देशो के संदर्भ में एचटी उपभोक्ता या तो फ्रैंचाईजी मार्ग के माध्यम से संचालित होने के हकदार थे अथवा प्रत्येक आई टी इकाई के लिए प्रासंगिक शुल्क दर के अंतर्गत व्यक्तिगत कनेक्शन लेना था।

iii. सी–डैक का तर्क कि 'यदि पुणे विश्वविद्यालय के लिए व्यक्गित कनेक्शन ले लिया गया होता तो भी नाम मात्र एक पैसे की बचत हुई होती' तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि एक पैसे के अंतर की गणना औद्योगिक शुल्क दर में विद्युत शुल्क /17 प्रतिशत जोड़कर की गई थी। चूँकि महाराष्ट्र सरकार की आई टी एवं आई टी एस एस नीति के अनुसार आईटी एवं आई टी एस एस इकाईयाँ विद्युत शुल्क भुगतान से मुक्त होने के साथ रियायती औद्योगिक शुल्क दर की पात्र थी, अतः अप्रैल 2010 से सितंबर 2014 के दौरान लोक सेवा श्रेणी एवं औद्योगिक शुल्क दर के मध्य प्रति इकाई वास्तविक अंतर ₹ 1.20 से ₹ 4.97 प्रति इकाई के बीच आया।

इस प्रकार महाराष्ट्र आई टी/आई टी ई एस नीति 2009 के अंतर्गत उपलब्ध रियायती विद्युत शुल्क दर का लाभ लेने में सी–डैक प्रबन्धन की विफलता के कारण 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2014 तक) विद्युत प्रभारों पर ₹ 4.78 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय भविष्य में पुनः आवर्ती प्रभाव के साथ हुआ।

4.5 कार्मिक एवं स्थापना प्रकरणों के नियमन में कमियाँ

सी–डैक पुणे ने अपनी गर्वनिंग कॉंउसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित स्टाफ रूल के विभिन्न प्रावधानों का न केवल उल्लंघन किया बल्कि जीएफआर तथा एफआर एवं एसआर का भी उल्लंघन किया। यह उसके अपात्र कर्मचारियों को अनियमत रूप से लीज पर आवास की सुविधा, ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान, प्रबंन्धन बोर्ड के निर्देशों के उल्लंधन में आतंरिक संकाय को अनियमित मानदेय का भुगतान, स्टाफ को उपहारो का अनियिमित प्रावधान, तकनीकी/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों की भाड़े पर भर्ती में पारदर्शिता का अभाव तथा कानूनी सलाहकार की नियुक्ति पर असामान्य व्यय में फलित हुआ।

सामान्य वित्तीय नियम 209 (6) (iv) (अं) के अनुसार, सभी अनुदानित संस्थायें और संगठन जो कि अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान के रूप में पाते हैं को आमतौर पर अपने कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तें बनानी चाहिए, जो सामान्यतः कुल मिलाकर केन्द्र सरकार में समान श्रेणी के कर्मचारिओं पर लागू होते हैं, से उच्च नहीं होने चाहिए। असाधारण मामलो में वित मंत्रालय (एम ओ एफ) से परामर्श के साथ छूट प्रदान की जा सकती है।

लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर–दिसम्बर 2014) ने प्रकट किया कि सी–डैक केन्द्र सरकार से पचास प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है और इसके स्वयं के स्टाफ नियम गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित

हैं, तथापि अनेक कार्मिक एवं स्थापना प्रकरणों के क्षेत्रों में सी–डैक पुणे अपने स्वयं के स्टाफ नियमो[22] और भारत सरकार (जी ओ आई) के नियमों से विचलित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.29 करोड़ का अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि अनुगामी अनुच्छेदो में चर्चा की गई है।

I. अपात्र कर्मचारियों को लीज पर आवास की सुविधा प्रदान करने के कारण अधिक भुगतान।

वित मंत्रालय, व्यय विभाग ने (मई 2009) मत्रांलय/विभागों को शक्तियों का प्रत्तयोजन किया, जिसके अनुसार वे स्वायत्त संस्थाओं के मुख्य कार्यकारियों के लिए कुछ निश्चित सीमाओं[23] के अधीन आवासीय सुविधा किराए पर लेने के लिए सक्षम थे।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2014/अगस्त 2015) कि सी–डैक पुणे ने वित मंत्रालय की सहमति प्राप्त किए बगैर अपने कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारियों के अलावा, वेतन एवं ग्रेड पे के 40 प्रतिशत पर लीज आवासीय सुविधा (स्वंय–लीज सहित) प्रदान की जो कि पुणे में देय 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता से दुगना था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सी–एम ई टी पुणे, जो कि डी ई आई टी वाई के अधीन एक इकाई है, ने अपने कर्मचारियों, अपने मुख्य कार्यकारियों सहित, को लीज आवसीय सुविधा प्रदान नहीं की। सी–डैक पुणे के अपात्र कर्मचारियों की जी एफ आर एवं एम ओ एफ के आदेशों के उल्लधंन में लीज आवासीय सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप 2010.15 के दौरान ₹ 6.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। (**अनुलग्नक XVIII**)

सी–डैक पुणे ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अभी तक अपने विचार/टिप्पणियाँ नहीं प्रस्तुत की।

II. ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान

सी–डैक के स्टाफ नियम (सेवा शर्ते एवं कर्मचारी लाभ) 2006 प्रावधान करते हैं कि इसके कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारियों पर 01 जनवरी 2006 से प्रभावी ग्रेच्युटी योजना के अनुरूप ग्रेच्युटी के पात्र होगें। हालॉकि, दिसम्बर 2014 के दौरान सी–डैक पुणे इकाई के ग्रेच्चूटी भुगतानों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सी–डैक ने अपने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का भुगतान, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम[24] 1972 के प्रावधानों के अनुसार किया जो कि अशासकीय कर्मचारियों पर लागू है। ग्रेच्युटी का भुगतान सी सी एस (पेंशन) नियम के अधीन अधिकतम देय ग्रेच्युटी ₹ 10 लाख से अधिक किया गया जो कि स्टाफ नियम के प्रावध ानों के भी विपरीत है। उन कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया जिन्होने त्यागपत्र दे दिया था और ग्रेच्युटी हेतु पात्र नही थे क्योंकि उन्होने सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के अधीन न्यूनतम अर्हक सेवा पूर्ण नहीं की थी। यह मार्च 2006 एवं जून 2013 के मध्य सेवानिवृत्त हुऐ/त्यागपत्र दे चुके कर्मचारियों को ₹ 0.40 करोड़ के अधिक भुगतान में फलित हुआ जैसा कि (**अनुलग्नक–XIX**) में दर्शाया गया है।

---

22 सी–डैक के स्टाफ नियम– अक्टूबर 2006 समिति के प्रशासन एवं प्रबन्धत हेतु उपनियमों के अधीन संरचित सी–डैक कर्मचारियों के लिए सेवाशर्तें तथा स्टाफ लाभ।

23 वाई श्रेणी शहरों के संदर्भ में, ₹ 8700 ग्रेड पे या उससे अधिक वाले मुख्य कार्यकारियों हेतु मंत्रालय/विभाग ₹ 18400 से लेकर ₹ 32000 प्रतिमाह तक के आवास किराये पर ले सकते हैं, सी–डैक पुणे ने यद्यपि, एमओएफ द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का भी पालन नहीं किया।

24 यह अधिनियम कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रो, बंरदगाहों, दुकानों एवं अन्य स्थापनाओं में लगे हुए कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान करता है।

यह उत्तर दिया गया (दिसम्बर 2014) कि सी–डैक के मेमोरंण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रिक्रूटमेंट रूल्स (एम ओ ए आर आर) के अनुसार सभी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने/सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी देय थी और जिसकी गणना पूर्ण सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक परिलब्धियों के 15/26 भाग पर की जानी थी तथा संशोधन के उपरांत, ग्रेच्युटी का भुगतान सरकारी कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी योजना के अनुसार किया गया था।

सी–डैक का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सी–डैक के स्टाफ नियमों के अनुरूप नही था जोकि 01 जनवरी 2006 से लागू है, तथा साथ ही भारत सरकार के सी सी एस (पेंशन) नियम 1972 के भी अनुरूप नहीं था।

III. आंतरिक संकाय को मानदेय का अनियमित भुगतान।

मौलिक नियमों (एफ आर) के अनुसार, मानदेय को आकस्मिक एवं आंतरायिक प्रकार के विशेष कार्य हेतु सरकारी कर्मचारियो को एक आवर्ती अथवा गैर–आवर्ती भुगतान किये गये पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी, उस किए गए कार्य के लिए, जो आकस्मिक अथवा आतंरायिक है तथा वह या तो इतना श्रमसाक्ष्य है अथवा ऐसी विशेष योग्यता वाला है जो एक विशेष प्रतिफल के औचित्य को सिद्व करता है, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को अधिकतम मानदेय ₹ 5000/- प्रतिवर्ष प्रदान कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है।

सी–डैक अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से, जिसमें पुणे केन्द्र भी एक है, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। आंतरिक संकाय को मानदेय के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, सी–डैक प्रबन्धन ने आंतरिक संकाय को मानदेय भुगतान नहीं करने का भी निर्णय लिया (अक्टूबर 2013)।

तथापि, नवम्बर 2014 की लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि:

- सी–डैक पुणे ने 2009-10 से 2013-14 (**अनुलग्नक XX**) के दौरान 62 कर्मचारियों को (आंतरिक संकाय के रूप) ₹ 53.75 लाख का भुगतान से उच्चतम सीमा ₹ 5000 प्रतिवर्ष से अधिक किया ।
- वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान ₹ 5000 से अधिक का किसी व्यक्ति को किया गया अधिकतम भुगतान ₹ 3.51 लाख था (श्री आशीष कुवेलकर, आंतरिक संकाय)।
- ₹ 53.75 लाख के कुल अधिक भुगतान किये गये मानदेय में से ₹ 13.50 लाख (25.93 प्रतिशत) मात्र एक कर्मचारी को किया गया था (श्री आशीष कुवेलकर, आंतरिक संकाय)।
- सी–डैक ने 2014-15 के दौरान किए गए मानदेय के भुगतान का विवरण नहीं दिया और इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या अभी मानदेय का अधिकतम सीमा से ज्यादा भुगतान जारी है या नहीं।
- इस प्रकार, मौलिक नियमो के उल्लंधन में, प्रबन्धन बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी करते हुए, शक्तियों के प्रत्यायोजन में प्रावधान के बिना मानदेय का भुगतान करना, ₹ 53-75 लाख के अधिक/अनियमित भुगतान में फलित हुआ।

सी–डैक पुणे ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि मानदेय को वेतन आय में जोड़ते हुए आयकर के प्रयोजन हेतु माना गया था। तथापि, उत्तर निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय के भुगतान पर, शाक्तियों के प्रत्यायोजन के बिना मानदेय के भुगतान तथा प्रबंन्धन बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन में इसके भुगतान पर मौन था।

IV. कर्मचारियों को उपहारों का प्रावधान अनियमित व्यय में फलित हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2013 एवं अप्रैल 2015) कि सी–डैक ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपने कर्मचारियों को उपहार[25] प्रदान करने के लिए ₹ 1.08 करोड़ खर्च किये। यह भी देखा गया कि उपहार की खदीद पर व्यय मिशन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कोर अनुदान से किया गया जो कि एफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में था क्योंकि अनुदान से व्यय उसी प्रयोजन हेतु करना था जिस प्रयोजन के लिए यह दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी–डैक के स्टाफ नियमों/भारत सरकार के नियमों तथा विनियमों में सरकारी कर्मचारियों को उपहार देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, सी–डैक द्वारा स्टाफ को दिए गए उपहार जी एफ आर के नियम 215 (1) (iii) के अधीन उल्लिखित सुविधाओं की सूची में नहीं आते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को उपहार पर ₹ 1ण08 करोड़ का व्यय करना अनियमित है।

सी–डैक ने उत्तर दिया (जुलाई 2013 एवं अप्रैल 2015) कि व्यय डी ई आई टी वाई द्वारा मिशन परियोजनाओं के अधीन जारी किये गए अनुदानो में से किया गया है एवं वे स्टाफ कल्याण व्यय के रूप में लेखाबद्ध हैं तथा भुगतान महानिदेशक सी–डैक के अनुमोदन के साथ किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सी–डैक अपने कर्मचारियों को प्रदत्त उपहारों हेतु समुचित प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार के व्यय को मिशन परियोजनाओं पर आरोपित करना अनियमित है क्योंकि मिशन परियोजनाओं के लिए आवंटित राशियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना था जिसके लिए वे स्वीकृत/आवंटित थी।

V. तकनीक/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों को किराये पर लेने में पारदर्शिता का अभाव

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2014) कि सी–डैक पुणे ने मई 2009 से अक्टुबर 2014 के दौरान तकनीकी/परियाजना कार्यो के लिए 48 सलाहकारों किराये पर लेने में ₹ 3.50 करोड़ व्यय किये। इनमें से 18 सलाहकार (व्यय ₹ 1.38 करोड़) विभाग प्रमुख के अनुरोध पर लिए गए और दो सलाहकार (व्यय ₹ 0.08 करोड) आवश्यकता के अनुसार चिन्हित किये गये थे। चार सलाहकारों (व्यय ₹ 0.42 करोड़) के चयन का तरीका उपलब्ध नहीं था शेष 24 सलाहकार (व्यय ₹ 1.62 करोड़) साक्षात्कार के आधार पर किराये पर लिए गए बताए गए। सी–डैक पुणे ने सलाहकारों को किराये पर लेने के लिए विज्ञापनों के निर्गत होने तथा उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

इस प्रकार तकनीकी/परियोजना कार्यों के लिए सलाहकारों को किराये पर लेने में कोई पारदर्शिता नहीं थी तथा ₹ 3.50 करोड़ का व्यय किया जो कि भारत सरकार के आदेशों तथा जी एफ आर के प्रावधानों के उल्लधंन में था।

25 उपहार जैसे कि इलैक्ट्रिक कुकर, डिनर सैट, मिक्सर/ग्राइन्डर, फैशन बैग, कम्बल, सैण्डविच टोस्टर, कटलरी, सूटकेस, वेक्यूम क्लीनर आदि

VI. विधिक सलाहकार की नियुक्ति पर असमान्य व्यय।

सी–डैक पुणे के पास विधिक एवं संविदा प्रमुख की अध्यक्षता में तीन से चार विधिक सलाहकारों द्वारा सहायता प्राप्त एक विधिक शाखा है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 11 विधिक प्रकरण (तीन न्यायालय प्रकरण और आठ कैट प्रकरण) 17 नवम्बर 2014 की तिथि में लम्बित थे। समस्त प्रकरण स्थापना मामलों, जैसे प्राथियों द्वारा निलम्बन को चुनौती (तीन समान प्रकरण), प्रार्थियों द्वारा वेतन नियतन को चुनौती (तीन समान प्रकारण) आदि से सम्बन्धित थे तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में काई भी प्रकरण लम्बित नहीं थे।

उपरोक्त को देखते हुये विधिक शुल्क के मद में वृहत् व्यय की कोई संभावना नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि 2013-15 के दौरान (नवम्बर 2014 तक), सी–डैक पुणे ने विधिक परामर्शदाती फर्म मैसर्स पवन दुग्गल एसोसियट्स विभिन्न मामलों/चुनौतियों के विधिक सलाह प्रभार के लिये सी–डैक को (₹ 55.67 लाख), विभिन्न आर टी आई प्रश्नों पर सलाह (₹ 24.42 लाख), विधिक सम्मेलन पर सलाह (₹ 13.58 लाख) और अन्य विविध मुद्दों (24.08 लाख)[26] पर सलाह, प्रदान के लिए विधिक परामर्श प्रभार ₹ 1.18 करोड़ (**अनुलग्नक–XXI**) का भुगतान किया। यह भी देखा गया कि विधिक परामर्शदाता को ₹ 16666 प्रति घंटा से लेकर ₹ 25000 प्रति घंटा के मध्य फीस का भुगतान बहुत ऊँची दरों पर किया गया था। सी–डैक पुणे ने न तो पुणे में उपलब्ध स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं की सेवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया और न ही विधिक एवं न्याय मंत्रालय (एम ओ एल जे) द्वारा अधिसूचित फीस से पारिश्रमिक सीमित किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सी–डैक ने एम ओ एल जे, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर निजी विधिक सलाहकार की नियुक्ति की जो कि एम ओ एल जे द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 2002 और जनवरी 2015) के उल्लघंन में था। विधिक सलाहकारों को फीस/पारिश्रमिक का नियमन एम ओ एल जे द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार किया जाना है जिसका भी सी–डैक द्वारा पालन नहीं किया गया। यह देखा गया कि एम ओ एल जे के निर्देशों (सितम्बर 2011) के अनुसार स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई में भाग लेने के लिए अधिकतम देय फीस ₹ 9000 प्रतिदिन है। जबकि सी–डैक ने विधिक सलाहकरों को फीस का भुगतान ₹ 25000 प्रतिघंटे की दरों तक किया वो भी बिना किसी विशेष आवश्यकता के। सी–डैक ने विधिक सलाहकारों की नियुक्ति के आधार को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त सी–डैक ने विधिक सलहाकारों को मार्च 2013 तक तथा नवम्बर 2014 से आगे के लिए किए गए भुगतानों का विवरण तथा प्रत्येक प्रकरण में विधिक सलाहकार से सम्पर्क करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।

सी–डैक ने उत्तर दिया कि पेशेवर जैसे चिकित्सक, अधिवक्ता विज्ञापन के माध्यम से चयनित अथवा नियुक्त नहीं किए जाते वरन उनको उनकी निपुणता/विशेषज्ञता/प्रतिष्ठा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह भी कहा गया कि आरटीआई आवेदनों की बढ़ती प्रवृति के कारण अपने विधिक हितों की रक्षा करने के लिए विधिक सलाहकारों से परामर्श आवश्यक समझा गया। आगे भी कहा गया कि निजी

26 सीसीएस (सीसीए) नियमों पर सलाह, अपराधिक विधि अधिनियम में संशोधन आईई कार्यवाहियों में प्रेजेन्टिंग आफिसर्स हेतु टेम्पलेट की ड्राफिटंग, इलेक्ट्रनिक रूप मे डाटा तथा सूचना हेतु अपनायी गई, तर्कसंगत सुरक्षा प्रथायें तथा प्रक्रियायें, कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम 2013) के बारे में कर्मचारी जागरूकता इत्यादि।

अधिवक्ताओं की नियुक्ति से सम्बन्धित एमओएलजे का परिपत्र सी–डैक पर लागू नहीं था जो कि निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक परिपूर्ण विधिक शाखा होने के बावजूद भी सी–डैक ने जी ओ आई/जी एफ आर के विभिन्न ओदशों के तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत एक विधिक फर्म को नियुक्त करने में व्यय किया। अपनायी गई दरें बहुत अधिक हैं। सी–डैक पुणे में उपलब्ध स्थायी/पैनल अधिवक्ताओं की सेवाऐं नही ली।

इस प्रकार सी–डैक पुणे ने न केवल अपनी गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित भारत सरकार के नियमों पर आधारित स्टाफ नियमों का ही नहीं बल्कि जी एफ आर एवं एफ आर और एस आर का भी उल्लंघन किया। सी–डैक के द्वारा की गई यह चूक अधिक/अनियिमित/परिहार्य व्यय में फलित हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

4.6 किराए की जगहों के लिए आंतरिक साजसज्जा का काम पूरा करने में असामान्य देरी के कारण परिहार्य एवं निष्फल किराया व्यय

ईआरएनईटी इण्डिया ने अगस्त 2010 में मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से जगह किराए पर ली। यद्यपि कार्यादेश जून 2012 में जारी हुआ था, तथापि कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं हो सके। इसके परिणामस्वरूप ई आर एन ई टी किराए की जगह पर कार्य करता रहा और अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2014 के मध्य ₹ 5.52 करोड़ किराए का भुगतान किया। अगस्त 2010 से दिसम्बर 2014 तक कि अवधि के दौरा किराए पर भवन को लेने के लिए किराए पर एक अतिरिक्त परिहार्य व्यय ₹ 7.17 करोड़ भी किया गया।

ऐजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ई आर एन ई टी)[27] इंण्डिया ने फरवरी 2010 में दिल्ली मैट्रो रेल कापोरेशन (डी एम आर सी) से लगभग 700 वर्ग मीटर स्थान किराये पर लिया जिसके लिए अगस्त 2010 में एक लीज अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। बाद में, अप्रैल 2011 में, ई आर एन ई टी इण्डिया ने अपने सभी कार्यालय और परिचालन गतिविधियों को एक ही छत के नीचे स्थानान्तरित करने के विचार से डी एम आर सी को मौजूदा आवंटित स्थान के बदले में 1858.1 वर्ग मीटर स्थान आवंटित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। अगस्त 2011 में डी एम आर सी आई टी पार्क भवन दिल्ली में 1869.109 वर्ग मीटर सुपर बिल्ड अप एरिया हेतु में पुनरीक्षित लीज अनुबन्ध ई आर एन ई टी और डी एम आर सी के बीच किया गया। संशोधित लीज अनुबन्ध ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

(i) एक मासिक लाईसेंस शुल्क (किराया) ₹ 675 प्रति वर्गमीटर तथा उस पर लागू सेवा कर एवं अधिभार सहित डी एम आर सी को भुगतान किया जाना था। इसको तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि की समाप्ति के बाद लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत से संशोधित किया जाना था।

(ii) लाईसेंस की प्रारंभिक अवधि छः वर्षो के लिए थी और ई आर एन ई टी ने ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा हेतु ₹ 1.51 करोड़ जमा कर दिये।

27 ईआरएनईटी इण्डिया 1998 में डीईओटीवाई के अधीन एक स्वयतशासी संस्था के रूप में स्थापित की गई थी।

(iii) सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु एक मासिक राशि ₹ 1.81 लाख तथा उस पर लागू सेवा कर और पार्किगं प्रभार का अलग से भुगतान किया जाना था।

(iv) अनुबन्ध की धारा 11 यह उपबन्धित करती थी कि लाईसेंस धारक समस्त आंतरिक विभाजन योजना हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

ई आर एन ई टी ने किराये के स्थान के आंतरिक साज सज्जा कार्य के लिए निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) की तथा ₹ 1.61 करोड़ का क्रय आदेश जून 2012 में मैसर्स वुडफन इन्टीरीयर्स एंड डैकोरेटर्स को जारी किया। क्रय आदेश में निर्धारित था कि क्रय आदेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर[28] समस्त कार्य सब प्रकार से पूर्ण हो जाना चाहिए। विलंब की दशा में ठेकेदार को अपूर्ण कार्यों के संविदा मूल्य के एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से, अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत तक, क्षतिपूर्ति[29] करना था।

ई आर एन ई टी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2015) ने उद्घाटित किया किः

क. कुल परियोजना लागत ₹ 1.60 करोड़ के विरूद्ध जून 2013 तक ₹ 65.41 लाख के व्यय पर मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था।

ख. विभाजन कार्य की प्रक्रिया में, डी एम आर सी ने पी वी सी पाईप बिछाने की अनुमति नहीं दी और जी आई पाईप के लिए जोर दिया जो निविदा की मद नहीं थी। इसके कारण जी आई पाईप की दरो को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ जिस कारण ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु चार विस्तार बिना एल डी प्रभारों के दिये गये। अक्टूबर 2013 में संविदा निरस्त कर दी गई।

ग. ई आर एन ई टी कब्जे की तिथि से चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी किराए की जगह के गैर–अधिग्रहण के बावजूद किराया (लाइसेंस फी) देता रहा। अगस्त 2010 से दिसम्बर 2014 तक किराया, अनुरक्षण तथा विद्युत एंव जल प्रभारों के मद में डी एम आर सी को ₹ 7.17 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त ई आर एन ई टी ने अप्रैल 2011 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य वर्तमान जगह का किराया प्रभारों की मद में ₹ 5.52 करोड़ की राशि का भी व्यय किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित (सितम्बर 2015) किए जाने पर, मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि डी एम आर सी, एक सरकारी संगठन, को भुगतान किए गए किराए को सरकारी खजाने की हानि नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा गया कि ठेकेदार को बिना एल डी प्रभार लागू किए अनेक बार विस्तार इसलिए दिए गए क्योंकि ई आर एन ई टी इण्डिया डी एम आर सी के भवन में स्वयं को स्थानान्तरित करने हेतु कार्य पूर्ण कराने के लिए उत्सुक था तथा ठेकेदार की विफलता सुनिश्चित करने के उपरांत संविदा 25 अक्तूबर 2013 को निरस्त कर दी गई। यह भी कहा गया कि ठेकेदार ने सिविल कार्यों के अधीन उल्लेखित मूल्य पर अग्निशमन प्रणालियों हेतु जी आई पाईप की आपूर्ति करने से मना कर दिया क्योंकि जी आई पाईप विद्युत कार्यो में निविदा मद के रूप में सम्मिलित नहीं थे जिसके कारण एक निश्चित अपरिहार्य विलम्ब

28 क्रय आदेश की धारा 21

29 क्रय आदेश की धारा 16

हुआ। यह भी सूचित किया गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान एलडी प्रभारों का दावा किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। डी एम आर सी को किराये का भुगतान एक निष्फल व्यय है क्योंकि किराए पर लेने की तिथि से चार वर्ष बाद भी विभाजन कार्य के अपूर्ण रहने के कारण आवंटित स्थान को ई आर एन ई टी द्वारा ग्रहण नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त लाईसेंस अनुबंध की धारा 11 के अनुसार ई आर एन ई टी को समस्त आंतरिक विभाजन कार्य शुरू करने से पहले डी एम आर सी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना था। यद्यपि, यह नही किया गया जिस कारण डी एम आर सी ने पी वी सी पाईप को बिछाने में आपत्ति की और बदले में जी आई पाईप पर जोर दिया। इससे भी कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब तथा फर्म को जारी कार्यादेश के निरस्त होने में फलित हुआ।

इस प्रकार ई आर एन ई टी के लचर प्रबन्धन/अनिर्णय की स्थिति ₹ 7.17 करोड़ के निष्फल एवं परिहार्य व्यय में फलित हुई। लीज अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने की तिथि से चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी ई आर एन ई टी किराए पर लिए गए स्थान का उपयोग करने में असमर्थ था।

4.7 दण्डात्मक ब्याज का गैर आरोपण

एस टी क्यू सी निदेशालय के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (ई आर टी एल) कोलकाता, इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र (ई टी डी सी) बैगंलोर तथा जयपुर द्वारा सरकारी प्राप्तियों को केन्द्र सरकार के खाते (भारत की समेकित निधि) में विलम्बित प्रेषण हेतु अपने बैंकरो पर ₹ 0.67 करोड़ दण्डात्मक ब्याज का गैर–आरोपण।

इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) भारत सरकार से संबंध एक कार्यालय, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) निदेशालय, इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (ई आर टी एल) तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्रो (ई टी डी सी) के एक देशव्यापी तन्त्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ प्रदान करता है। इन सेवाओं में सार्वजनिक और निजी संगठनों के लिए परीक्षण, मापांकन, प्रशिक्षण और प्रमाणन शामिल है।

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्तियां एवं भुगतान) प्रारम्भिक एवं सामान्य सिद्धांतो का नियम 8 कहता है कि सरकारी राजस्व, प्राप्तियां अथवा देयों के प्राप्त होते ही, प्राप्तकर्ता बैंक शाखा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर बी आई) द्वारा संधारित सरकार के जमाओं में, नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार जो यह निर्दिष्ट करता है कि जब तक अन्यथा न उल्लेखित हो, केन्द्र सरकार के खाते में जमा की गई राशियाँ जिनका नगद व्यवसाय बैंक द्वारा नही किया जाता है या तो आर बी आई अथवा केन्द्रीय खजाने द्वारा धारित की जाएँगी, तुरंत सम्मलित करेगा।

आर बी आई के जनवरी 2007 के पत्रानुसार, ₹ 1 लाख एवं उससे अधिक के लेनदेन में विलम्ब की अवधि बैंक दर में दो प्रतिशत जोड़कर विलम्बित अवधि के ब्याज को आकर्षित करेगी। इसके अतिरिक्त ₹ 1 लाख से कम के प्रत्येक लेनदेन हेतु पाँच कैलेण्डर दिवसों तक विलम्बित अवधि ब्याज बैंक दर पर होगा

तथा पाँच कैलेण्डर दिवसों से अधिक के लिए विलम्ब की पूरी अवधि हेतु ब्याज बैंक दर में दो प्रतिशत जोड़कर होगा। बैंक दर आर बी आई द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर होगी।

एस टी क्यू सी इकाईयों नामतः ई टी डी सी बैंगलोर, ई टी डी सी जयपुर तथा ई आर टी एल कोलकाता द्वारा सरकारी देयों के प्रेषण हेतु खोले गये चालू खातो[30] के जनवरी 2009 से मार्च 2015 तक की अवधि के बैंक विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि आई टी सेवाओ एवं एस टी क्यू सी के मद में प्राप्तियों को एस टी क्यू सी इकाईयाँ अपने शहरो में सम्बन्धित बैंको में खोले गये अपने चालू खातों में प्रतिदिन प्रेषित कर रही थीं। बैंक को प्रतिदिन के आधार पर प्रेषित की गई राशियॉ बैंक द्वारा तुरंत केन्द्र सरकार के खातो में जमा की जानी चाहिए थी। हालांकि बैंको ने अधिकतर प्राप्तियों को स्वयं के बैक खातों में रखते हुए उनको आंशिक रूप से माह में एक या दो बार प्रेषित किया। यह प्राप्तियाँ और भुगतान नियमों की लागू होने वाली धाराओं के उल्लंघन में था तथा इसलिए जनवरी 2009 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ₹ 0.67 करोड़ के (**अनुलग्नक-XXII**) दण्डात्मक ब्याज को आकर्षित किया। जिससे समान राशि से केन्द्र सरकार को राजस्व हानि की हानि हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2015), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि ऐसी खामियों को रोकने के लिए कदम उठाए गये हैं। ईआरटीएल कोलकाता इकाई ने उत्तर दिया कि संबन्धित बैंको से दण्डात्मक ब्याज भारत की समेकित निधि में प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया गया है। इसी प्रकार, ई सी टी डी बैंगलोर तथा जयपुर ने उत्तर दिया कि बैंकरों द्वारा केन्द्र सरकार के खाते में सरकारी प्राप्तियो के विलम्बित प्रेषण हेतु ब्याज का भुगतान करने के लिए क्रमशः प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया बैंगलोर एवं बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर को पत्र भेजे जा चुके हैं।

तथापि, यह तथ्य बना रहता है कि एस टी क्यू सी इकाईयों द्वारा समुचित निगरानी के अभाव में सम्बन्धित बैंको ने सरकारी धन का विलम्बित प्रेषण किया तथा सरकार को कोई ब्याज का भुगतान किए बिना धन का उपयोग किया। अतः वे सरकार को ₹ 0.67 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

30 जमा पर कोई ब्याज नही दिया गया

अध्याय -V
मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल)

कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) 1986 में स्थापित की गई थी और यह मुम्बई और दिल्ली में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन व संचालन हेतु उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगर शहरों में फिक्सड लाईन दूरसंचार सेवा व जी एस एम मोबाइल सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल अलग से अनन्य गैर लाइसेंस अनुबन्ध करार के अर्न्तगत दिल्ली और मुम्बई में डायल अप इन्टरनेट सेवा को भी प्रदान करता है। यह ब्राडबैंड व 3जी सर्विस भी प्रदान करता है। वर्ष 2013-14[1] के दौरान एम टी एन एल का वित्तिय कारोबार ₹ 3787 करोड़ था तथा उसे ₹ 7825 करोड़ का लाभ[2] हुआ।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि)

अक्तूबर 2000 में गठित, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर देश के कोने–कोने में दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक उन्मुक्त कम्पनी है तथा जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवायें नामतः लैन्डलाईन पर दूरभाष सेवायें, डब्ल्यू एल एल, जी एस एम मोबाइल, ब्राडबैंड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लंबी दूरी की दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है। वर्ष 2013-14[3] के दौरान भा सं नि लि का कारोबार ₹ 27,996.35 करोड़ था तथा उसे ₹ 7,019.76 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (आई टी आई लिमिटेड)

आई टी आई लिमिटेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आइ टी आई ने 1948 में बंगलुरू में अपना संचालन प्रारंभ किया जिसका कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्कड़ में निर्माण संयत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तार किया गया। वर्ष 2013-14[4] के दौरान ₹ 745.79 करोड़ का कारोबार किया एवं उसे ₹ 344.26 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आइ एल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली टेलीकम्यूनिकेंशस कंसलेंट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य

1 एम टी एन एल का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन

2 डी.ओ.पी. व पी. डब्ल्यु के नोटिफिकेशन क्रमांक 138 (ई) दिनांक 3 मार्च 2014 की अधिसूचना के परिपेक्ष्य में एम.टी.एन.एल. में समाहित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व गेज्युटी के प्रावधान/वापस लेखन के कारण था तथा बी.डब्ल्यु. स्पेक्ट्रम की राशि को परिशोधित वापिस लेखन के कारण भी था। जो कि भारत सरकार के निर्णय से बी.डब्ल्यु. ए. स्पेक्ट्रम के लिये एक मुश्त प्रवेश शुल्क की वापिसी के कारण था।

3 बी एस एन एल का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन

4 आई टी आई का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये उचित विपणन रणनीति विकसित कर और आधुनिक तकनीकी को प्राप्त करने के लिये 1978 में हुई थी। कम्पनी ने वर्ष 2013-14[5] के दौरान ₹ 816.52 करोड़ का कारोबार किया और ₹ 14.75 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), एक स्पेशल परपज व्हेकिल (एस पी वी) को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) को कार्यान्वित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया। बी बी एन एल को देश के 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुये आप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहां आवश्यक हो वहां ग्राम पंचायतों और प्रखण्डों के मध्य सम्पर्कता अन्तराल को भरने के लिये वृद्धिशील फाइबर बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है जो कि उपयुक्त बैन्डविड्थ के साथ ब्राडबैंड सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2013-14[6] के दौरान कम्पनी ने ₹ 8.40 करोड़ का कारोबार किया और ₹ 1.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

मीडिया लैब एशिया

मीडिया लैब एशिया, एक 'गैर लाभकारी कम्पनी' की स्थापना कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत जन साधारण तक आई सी टी का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। मीडिया लैब एशिया के अनुप्रयोग क्षेत्र मे स्वास्थ सेवाएं, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तिकरण में आई सी टी का उपयोग करना है। कम्पनी विकास कार्य आरंभ करने के लिये अग्रणी संस्थाओं के साथ कार्य करती है। कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 54.74 करोड़ अर्जित किए, इसमें से ₹ 54.64 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान ₹ 0.91 करोड़ की राशि फिक्स्ड परिसम्पत्ति के लिए रखे गए रिजर्व से स्थानांतरित की गई।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई) को सरकारी संस्थाओं को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधीन कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 25 में कम्पनी के रूप में 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत में आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वर्ष के दौरान कम्पनी की आय ₹ 612.90 करोड़ थी एवं कर के बाद अधिशेष ₹ 36.10 करोड़ था।

वर्ष के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष का विवरण नीचे दिया गया है।

5 टी सी आई एल का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन

6 बी बी एन एल का वर्ष 2013-14का वार्षिक प्रतिवेदन

5.1 भा सं नि लि में सी डी आर आधारित सम्मिलित बिलिंग एवं ग्राहक सेवा सिस्टम

प्रस्तावना

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने चार जोनल केन्द्रों में स्थित सभी सैकण्ड्री स्विचिंग एरिया (एस एस ए) के बिलिंग केन्द्रों को समेकित करने के उद्देश्य से लैंड लाइन एवं ब्राडबैंड सेवाओं के लिये काल डिटेल रिकार्ड (सी डी आर) पर आधारित ग्राहक सेवा व सम्मिलित बिलिंग सिस्टम को कार्यान्वित करने एवं मीटर आधारित बिलिंग सिस्टम को सी डी आर आधारित बिलिंग सिस्टम में विस्थापित करने हेतु प्रस्ताव (जून 2002) किया। भा सं नि लि ने सी डी आर, प्रोजेक्ट–1 जिसमें दक्षिण व पूर्वी जोन तथा प्रोजेक्ट 2 जिसमें उत्तर व पश्चिम जोन शामिल थे, हेतु सम्मिलित निविदा मंगाई (अगस्त 2006)। निविदा में सी डी आर आधारित ग्राहक सेवा व सम्मिलित बिलिंग प्रणाली की शुरू से लेकर अंत तक की डिजाइनिंग, आयोजन, आपूर्ति, स्थापना, अनुकूलन, कमिशनिंग, ट्रेनिंग, प्रचालन एवं रख रखाव शामिल था। भा सं नि लि ने प्रोजेक्ट–1 (दक्षिण व पूर्वी जोन) के अन्तर्गत बिलिंग समाधान का कार्य मैसर्स एच सी एल को तथा प्रोजेक्ट–2 (उत्तर व पश्चिम जोन) का कार्य मैसर्स टी सी एस लिमिटेड को दिया (जून 2007)। स्टोरेज एक्सेस नेटवर्क का कार्य मैसर्स विप्रो लिमिटेड को दिया (जुलाई 2007) था। प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन सभी 334 एस एस ए में अप्रैल 2012 में पूर्ण हुआ था।

5.1.1 परियोजना की आयोजना, अधिप्राप्ति व कार्यान्वयन

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में परियोना की अधिप्राप्ति व क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियों का पता चलाः

5.1.1.1 आई ओ बी ए एस के कार्यान्वयन में देरी के कारण ₹ 18.77 करोड़ का परिहार्य व्यय

सी डी आर आधारित ग्राहक सेवा व सम्मिलित बिलिंग सिस्टम में इंटर आपरेटर बिलिंग व लेखा प्रणाली (आयोबास–आई ओ बी ए एस) शामिल था। आयोबास पॉइन्ट आफ इन्टरकनेक्ट (पी ओ आई) पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं/सी डी आर पर आधारित आपरेटर्स के बीच समायोजन राशि की गणना के लिये अपेक्षित था। आयोबास के लिये एजेंसी आधारित आदर्श समाधान के लिये बी एस एन एल ने तीन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइर्डस (ए एस पी) नामतः दक्षिण व पूर्वी जोन के लिये मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर, उत्तरी जोन के लिये मैसर्स टेक महेन्द्रा एवं पश्चिमी जोन के लिये मैसर्स एच सी एल इनफो सिस्टम लिमिटेड से अनुबन्ध किया (मार्च 2005)। जैसे ही सी डी आर प्रोजेक्ट का आयोबास माड्यूल तैयार होता, ए एस पी के डाटा सेन्टर पर किये गये सभी प्रचालन सी डी आर डाटा सेन्टर को स्थानान्तरित होने थे। सी डी आर परियोजना के सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस आई) नामतः मैसर्स टी सी एस व एच सी एल इन्फो सिस्टम लिमिटेड को वर्तमान आयोबास प्रणाली के ए एस पी मॉडल को सी डी आर आधारित प्रणाली में विस्थापित करना था। अग्रिम क्रय आदेश में दी गई अनुसूची के अनुसार सी डी आर को चालू करने की निर्धारित तिथि 05 दिसम्बर 2008 थी। लेखा परीक्षा ने पाया कि सी डी आर बिलिंग पेकेज में आयोवास 27 माह बिलम्ब के बाद मार्च 2011 में कार्यान्वित हुआ। आयोवास के कार्यान्वयन में बिलम्ब से भा सं नि लि को सभी तीनों ए एस पी की निविदा मार्च 2011 तक बढ़ानी पड़ी। परिणामस्वरूप जनवरी 2009 से मार्च 2011

तक की अवधि के लिये आयोबास प्रभार के रूप में ए एस पी को भुगतान हेतु ₹ 18.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2008-09 के लिये औसत मासिक खर्च: (3 माह के लिये ₹ 96.48 लाख)	2.89
2	वर्ष 2009-10 के लिये औसत मासिक खर्च: (12 माह के लिये ₹ 78 लाख)	9.36
3	वर्ष 2010-11 के दौरान किया गया वास्तविक खर्च	6.52
कुल		18.77

भा सं नि लि ने बताया (अगस्त 2015) कि डिजाइन व कार्यान्वयन में सी डी आर प्रोजेक्ट बहुत पेचीदा प्रोजेक्ट था एवं प्रोजेक्ट पर विचार करते समय आई टी टीम द्वारा सभी चुनौतियों के बारे में अनुमान लगाना कठिन था। समय सीमा बहुत कठिन थी। तथापि भुगतान प्राधिकारी द्वारा वेन्डर से लागू शास्तियां वसूली जा चुकी है। भा सं नि लि ने आगे यह बताया कि यदि यह विचार किया जाये कि आयोबास प्रणाली दिसम्बर 2008 में चालू की जाती तो भा सं नि लि को इस अवधि में आयोबास के प्रचालन व रख रखाव तथा ए एम सी पर ₹ 18.83 करोड़ के लगभग खर्च करना पड़ता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा सं नि लि ने निविदा प्रलेख सभी चुनौतियों व पेचीदगियों को सम्मिलित कर बनाये थे व समय सीमा निर्धारित की थी। एस आई समाहित पेचीदगियों से अवगत थे तथा उन्होंने निविदा विस्तृत अध्यन के बाद स्वीकृत की थी। भा सं नि लि द्वारा बताया गया कि इस अवधि में आयोबास के लिये प्रचालन व रख रखाव एवं ए एम सी पर लगभग ₹ 18.83 करोड़ खर्च होता, केवल अनुमान है व तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिये स्वीकार्य नहीं है। उत्तर को तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिये कि प्रोजेक्ट के विलम्ब से पूर्ण होने से भा सं नि लि, .सी डी आर प्रोजक्ट के पूर्ण होने वाले फायदे से वंचित रहा, इसके अतिरिक्त आयोबास के लिये ए एस पी पर निर्भर रहना पड़ा।

5.1.1.2 वारंटी तिथि का निर्धारण करना

निविदा की विशिष्ट शर्तों का अनुच्छेद 10.2 अनुबन्धित है कि परियोजना के लिये पहुंचाये गये या आपूर्ति किये गये सभी स्टोर उपकरण, साफ्टवेयर, सेवा इत्यादि की वारंटी, रोल आऊट अवस्था की समाप्ति की दिनांक से प्रारंभ होगी अर्थात जिस दिन जोन युग्म के अन्तर्गत सभी एस एस ए ने सफलता पूर्वक नई बिलिंग सिस्टम में रोल आउट किया। परियोजना–1 (दक्षिण और पूर्व जोन) के अन्तर्गत एस एस ए के अंतिम रोल आउट की तिथि बंगलूरू एस एस ए के लिये 23 अप्रैल 2012 थी और परियोजना–2 (उत्तर और पश्चिम जोन) के अन्तर्गत बडोदरा के लिये 28 मार्च 2012 थी। निविदा की शर्तों के अनुसार परियोजना–1 के लिये वारंटी 23 अप्रैल 2012 से तथा परियोजना–2 के लिये वारंटी 28 मार्च 2012 से प्रभावी थी। निविदा की शर्तों के विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि भा सं नि लि बोर्ड द्वारा वारंटी शुरू होने की दिनांक दक्षिण, पूर्व और उत्तर जोन के लिये 1 अप्रैल 2011 तथा पश्चिम जोन के लिये 15 जनवरी 2011 अनुमोदित (जनवरी 2013) की गई। वारंटी को एक वर्ष पहले चालू करने के परिणामस्वरूप ए एम

सी पर अतिरिक्त खर्च ₹ 17.56 करोड़ (दक्षिण–पूर्व जोन के लिये ₹ 15.29 करोड़ और उत्तर पश्चिम जोन के लिये ₹ 2.27 करोड़) हुआ।

भा सं नि लि ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि प्रबन्धन समिति द्वारा, सी डी आर सिस्टम एस एस ए उपकरण की वारंटी को प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई थी। समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सी डी आर नेटवर्क के रखरखाव के लिये उनको एस आई की सहायता की आवश्यकता थी और इसको ध्यान में रखते हुये कि एस एस ए के उपकरण की वारंटी प्रारंभ होने की समान दिनांक हो, यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभ दिनांक वह दिनांक होगी जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक एस एस ए आरम्भ हो चुके हों (या तो सी डी आर या आइ ओ बा स) या जिनकी जांच परख और स्वीकृति हो चुकी हो। भा सं नि लि प्रबन्धन द्वारा तथ्यों और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, परियोजना को जारी रखने हेतु वारंटी दिनांक नियत करने का निर्णय लिया गया जिसने अनेक प्रकार से भा सं नि लि को लाभ पहुंचाया। प्रबन्धन द्वारा आगे सूचित किया गया कि एस आई ने अवधारणा का प्रमाण चरण के उपकरणों की दिनांक जून 2008 से तथा रोल आउट चरण उपकरणों की जून 2009 से वारन्टी प्रारम्भ करने की मांग की थी।

तथ्य यह रह जाता है कि वारंटी का प्रारंभ किया जाना जब रोल आउट का कार्य प्रगति पर था निविदा की शर्तों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप ₹ 17.56 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के अलावा एस आइ को अनुचित लाभ हुआ ।

5.1.1.3 निविदा शर्तों के उल्लंघन में विक्रेताओं के बीच अनियमित गठजोड़

निविदा प्रलेख के खंड IV-ई, की धारा 6.4.2 के अनुसार दो परियोजनाओं के लिये दो अलग बिलिंग एप्लीकेशन साफ्टवेयर समाधान होंगे। धारा 6.5 दर्शाती है कि यदि कोई योग्य बोली–कर्ता उपकरण आपूर्ति के लिये सहमत नहीं हो रहा है या बीएसएनएल द्वारा आदेश देने के लिये विचारित नहीं किया गया तो इस स्थिति में बोलीकर्ता की वरिष्ठता को बदला जाना था जिससे कि एक ही बोलीकर्ता को दोनों परियोजनाओं के लिये ठेका प्रदान नहीं किया जायेगा। इस शर्त को सुनिश्चित करना था कि बोलीकर्ता जो परियोजना का निष्पादन कर रहे हैं दोनों परियोजनाओं यानि सी डी आर परियोजना–1 और सी डी आर परियोजना–2 के लिये अलग अलग होंगो। दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच यह दर्शाती है कि उपरोक्त शर्त के विपरीत विक्रेता मैसर्स एचसीएल और मैसर्स टी सी एस द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ अनुबंध किया गया जिसके अन्तर्गत सभी चार क्षेत्रों के लिये दोनों परियोजनाओं के हार्डवेयर भाग को मैसर्स एच सी एल द्वारा निष्पादित किया जाना था और मैसर्स टी सी एस द्वारा साफ्टवेयर भाग के कार्यों को निष्पादन करना था। इस प्रकार निविदा की इस शर्त कि दोनों परियोजना क्षेत्रों के लिये दो अलग साफ्टवेयर समाधान और दो अलग विक्रेता होंगे, का उद्देश्य विफल रहा।

भा सं नि लि ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि

(i) परियोजना को समय पर पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का सबसे बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिये यह किया गया था;

(ii) ओ एण्ड एम गतिविधियों को सम्बंधित एसआइ द्वारा नियंत्रित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अन्य विक्रेता को कार्य के निष्पादन का आदेश निविदा की शर्तों का उल्लंघन था और यह भा सं नि लि के हितों की सुरक्षा नहीं करता था। भा सं नि लि द्वारा एकमात्र विक्रेता पर बहुत ज्यादा आश्रित होने से एकमात्र विक्रेता द्वारा सहायता की वापिसी से कम्पनी को खतरा हो सकता था और इसलिये निविदा के अन्तर्गत यह अपेक्षित था कि दोनों परियोजनाओं के लिये विक्रेता अलग होना चाहिये थे।

5.1.1.4 एम टी ई की अधिक अधिप्राप्ति से ₹ 8.80 करोड़ का परिहार्य व्यय

निविदा प्रलेख के खण्ड VI-I के अनुच्छेद 7.1 में बताये अनुसार प्रत्येक बिलिंग केन्द्र में स्विच की संख्या तकनीक के अनुसार एवं दिये गये विवरणानुसार भा सं नि लि में ई–10 बी के 203 एक्सचेंज थे। ई–10–बी एक्सचेंजों को सी डी आर प्रोजेक्ट से मेनेटिक टेप ईम्यूलेटर (एम टी ई) के द्वारा जोड़ा जाना था। मैसर्स एच सी एल व मैसर्स टी सी एस को दिए गए (जून 2007) अग्रिम क्रय आदेश में 210 एम टी ई की आपूर्ति शामिल थी। भा सं नि लि आई टी पी सी, पूना के उत्तर के अनुसार (फरवरी 2015), एस एस ए/परिमण्डलों की निश्चित आवश्यकता के हिसाब से मात्रा में संशोधन कर 162 कर दिया गया था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि केवल 43 एम टी ई का उपयोग हुआ था तथा शेष 119 एम टी ई बेकार पड़ी थी जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	ए पी ओ मात्रा	प्राप्त एम टी ई	उपयोग की गई एम टी ई	बेकार पड़ी एम टी ई	दर प्रति इकाई	अतिरिक्त एम टी ई कुल कीमत (₹ में)
दक्षिण	57	46	23	23	1103621	2,53,83,283
पूर्व	40	27	14	13	1114842	1,44,92,946
उत्तर	51	43	6	37	576169	2,13,18,253
पश्चिम	62	46	0	46	583424	2,68,37,504
कुल	210	162	43	119		8,80,31,986

ई–10 वी एक्सचेंज बन्द/सेवामुक्त हो गये थे जिससे ज्यादातर एमटीई बेकार पड़ी थी। इस प्रकार ई–10बी स्विचों के समापन/प्रतिस्थापन और अपेक्षित एम टी ई के आकलन के संबंध में आई टी पी सी पूना व प्रादेशिक परिमण्डलों/कॉरपोरेट कार्यालय के बीच समन्वय की कमी के कारण 119 एम टी ई जिसकी कीमत ₹ 8.80 करोड़ थी बेकार हो गयी थी।

भा सं नि लि ने बताया (अगस्त 2015) कि एम टी ई की जरूरत कार्यक्षेत्र में उपयोग की गई स्वीचिंग तकनीक के अनुसार सी डी आर प्रोजेक्ट को समय पर चालू करने व नियमितता को सुनिश्चित करने के लिये एक व्यवस्था थी। अंततः ई–10बी एक्सचेंजों के बन्द होने ओर ग्राहको के एन टी स्विच में स्थान्तरण के साथ ही सभी एम टी ई अनावश्यक हो गई। वास्तविक जरूरत 210 की थी जबकि केवल 162 ही अधिप्राप्त किये गये। इस प्रकार ₹ 4 करोड़ की बचत की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि क्रय आदेश संशोधन के पूर्व एसएसए/परिमण्डल/निगम कार्यालय से ई 10बी स्विचों के बन्द करने की योजना को ध्यान में रखकर एमटीई की वास्तविक जरूरत का निर्धारण किया जाना चाहिए था।

5.1.1.5 सी डी आर विलिंग पैकेज में गबन प्रबंधन समाधान एवं राजस्व आश्वासन का आशिंक कार्यान्वयन

भा सं नि लि ने राजस्व रिसाव को बन्द करने हेतु राजस्व आश्वासन (आर ए) प्रणाली को कार्यान्वित किया। आर ए प्रणाली संग्रह, परितुलन बिलिंग में ग्राहक यूसेज डाटा का सामंजस्य स्थापित करने, मध्यस्थता, रेटिंग एवं दूसरे संबंधित एप्लीकेशन द्वारा ग्राहक विलिंग सत्यापन विधि के लिये प्रावधान करती है। आर ए प्रणाली का गबन प्रबंधन समाधान (एफ एम एस) के साथ एक इंटरफेस था और जिसका उद्देश्य टेलीकाम सेट अप में समाहित राजस्व लीकेज बिन्दुओं की पहचान करना व संशोधनात्मक कार्यवाही करना था ताकि इसे बन्द किया जा सके।

राजस्व आश्वासन व गबन प्रबंधन समाधान (आर ए एफ एम एस) सी डी आर बिलिंग प्रणाली के भाग थे और भा सं नि लि की आवश्यकतानुसार सिस्टम इंटीग्रेटर को सभी अपेक्षित आर ए एफ एम एस समाधान कार्यान्वित करने थे। प्रोजेक्ट–1 व प्रोजेक्ट–2 के लिये आदेशित दोनों आर ए तथा एफ एम एस समाधान के लिये कुल कीमत ₹ 20.92 करोड़ निहित थी।

यह पाया गया कि कुछ समाधान आंशिक रूप से कार्यान्वित किये गये जबकि 31 आर ए एफ एम एस प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न है:

आर ए प्रतिवेदन		एफ एम एस प्रतिवेदन	
ग्राहक सामंजस्य	4	उपयोग गबन प्रबन्धन	5
यूसेज सामंजस्य	9	सदस्यता गबन प्रबन्धन	4
विन्यास सामंजस्य	3		
कॉल परीक्षण	2		
अलार्म और के पी आई	4		
कुल	**22**		**9**

भा सं नि लि ने (अगस्त 2015) में आर ए व एफ एम एस एप्लीकेशन के आंशिक कार्यान्वयन के तथ्य को स्वीकार किया एवं एस आई को कार्य पूर्ण करने के अनुदेश जारी किये, इसके अतिरिक्त आर ए एफ एम एस हेतु देय राशि का 10 प्रतिशत रोक लिया गया।

इस प्रकार डाटा केन्द्रों के 2010 के दौरान शुरू होने के पांच वर्ष पश्चात् भी आर ए एफ एम एस समाधान का आंशिक कार्यान्वयन हुआ इस वजह से राजस्व लीकेज बिन्दू का पता नहीं लगा और जिस उद्देश्य हेतु आर ए एफ एम एस का कार्यान्वयन ₹ 20.92 करोड़ पर किया गया था, वह विफल रहा।

5.1.2 ढ़ांचागत कमियां

5.1.2.1 सी डी आर बिलिंग पेकेज में कमी के करण डिफॉल्टिंग प्रकरणों के विच्छेदन में अनावश्यक विलम्ब

निविदा के अनुच्छेद 3.19.1 की धारा VI (जे) की शर्तों में अपेक्षित था कि विच्छेदन (डनिंग) तात्कालिक होना चाहिये। सी डी आर बिलिंग पैकेज आने तक बकाया के गैर भुगतान के लिये विच्छेदन संबंधित एस एस ए प्राधिकारियों द्वारा किये जाते थे। सी डी आर प्रणाली में, एस एस ए के लिए उनके प्राधिकार क्षेत्र के अर्न्तगत डनिंग (विच्छेदन) संबंधित डाटा केन्द्र में होने थे। डाटा केन्द्रो का डनिंग अनुभाग डिफालटिंग ग्राहको के विच्छेदन समय पर करने के लिये जिम्मेदार था। निर्गम (ओ जी) पर रोक बिल जारी होने की तिथि के 35 वे दिन पर प्रभावी होना था, आगम (आई/सी) पर रोक बिल तिथि के 50 दिनों के बाद प्रभावित होना था एवं स्थायी विच्छेदन बिल के जारी होने की तिथि से 90 दिनो के बाद होना था। तथापि, दक्षिण एवं पश्चिम डाटा केन्द्रो पर यह देखा गया कि विच्छेदन उस दिन पर प्रभावी नही हो रहे थे एवं विच्छेदन में विलंब एक दिन से तिरसठ दिनो की रेंज में हो रहा था।

डाटा केन्द्र हैदराबाद ने उत्तर में बताया कि

- समान्यतय प्रत्येक विलिगं साईकल में ओ/जी बार, आई/सी बार, पी सी ओ, मल्टीपल बिलों एवं वी आई पी विच्छेदन सहित 5 लाख के आस–पास विच्छेदन हुये थे।
- कभी–कभी प्रणाली में समस्या के कारण प्रक्रिया को समय पर पूर्ण अथवा परिगणित नही किया जा सका क्योंकि उसमें विच्छेदन प्रक्रिया के दूसरी प्रक्रियायों जैसे बिलिंग, उप खाता बही आदि के साथ–साथ नहीं चल सकने की बाध्यता थी।
- निलम्बन आदेशों (विच्छेदन) को क्रियान्वित करने के लिये क्लेरिटी एप्लीकेशन की अधिकतम क्षमता प्रति रात्रि (प्रकरण) केवल 45000 तक सीमित थी।

भा सं नि लि ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि एस एस ए द्वारा डनिंग में कोई बडी चुनौती नहीं बताई गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब से विच्छेदनो के कारण बकाया रखने वाले ग्राहकों को भी सेवा मिलती रही जिसके फलस्वरूप बकाया राजस्व का संग्रहण भी बढ़ा। यद्यपि 45000 सस्पेशन प्रति प्रकरण का प्रतिबंध सी डी आर बिलिंग पैकेज के शुरू होने से ही लागू था, भा सं नि लि के द्वारा एस आई के माध्यम से प्रतिबंध से निपटने बावत और नियमों का पूरी तरह से पालन कर बकाया राजस्व के संग्रहण से बचने हेतु कोई कदम नही उठाया गया।

5.1.2.2 आई पी डी आर की बिलिंग न करना/बिलिंग में देरी

इन्टरनेट प्रोटोकाल डाटा/विस्तृत रिकार्ड (आई पी डी आर एस) ब्राडबेंड सेवा के उपयोग की सूचना और अन्य इन्टरनेट गतिविधियो के बारे में जानकारी देता है। जब भी ब्राडबेंड सर्विस का उपयोग हुआ, राष्ट्रीय इन्टरनेट बैकबोन (एन आइ बी)/नेटवर्क ऑपरेशन सर्किल (एन ओ सी.) बंगलरू ने आई पी डी आर एस जेनेरेट किए और संम्बधित डाटा केन्द्रो को श्रेणी निर्धारण और बिलिंग के लिये प्रसारित किया।

आई पी डी आर एस जोकि ''मास्टरलेस[7] '' था उसका श्रेणी निर्धारण और बिलिंग नही किया गया क्योंकि

(i) बिलिंग में यूज़र आइ डी बनाने के पहले आई पी डी आर जेनेरेट हुआ;

(ii) एस एस ए ने ग्राहको को पी2 सरवर से पी3[8] सरवर में स्थानांतरित किया;

(iii) विभिन्न जोन में पोर्ट बाध्यकारी नही होने के कारण यूज़र आई डी का उपयोग हुआ;

(iv) बंद संयोजन पर एन आइ बी/एन ओ सी में तकनीकि कारण और

(v) ग्राहको के पासपोर्ट–बाध्यकारी नहीं होने के कारण।

पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र के डाटा केन्द्रों की लेखापरीक्षा के दौरान, 39424 आइ पी डी आर एस की जनवरी 2015 तक बिलिंग नहीं हुई थी नीचे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

डाटा केन्द्र	जनवरी 2015 में लंबित आई पी डी आर एस की संख्या	आई पी डी आर एस संबंधित अवधि	सबसे पुराना आई पी डी आर एस
पश्चिम क्षेत्र	5790	अप्रैल 2013 से मई 2014	अप्रैल 2013
उत्तर क्षेत्र	22339	अप्रैल 2012 से नवम्बर 2014	अप्रैल 2012
दक्षिण क्षेत्र	11295	जनवरी 2012 से नवम्बर 2014	जनवरी 2012

वित्तिय प्रभाव को नही मापा जा सका क्योंकि शुल्क दर/दर ग्राहको द्वारा चयनित योजना के आधार पर थी। डाटा केन्द्र प्राधिकारियों, एस एस ए एस और एन ओ सी प्राधिकारियों द्वारा बिल नही किये गये आइ पी डी आर एस की जॉच और निपटान किया जाना अपेक्षित था।

भा स नि लि कारपोरेट कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया (अगस्त 2015) कि मास्टरलेस प्रकरण का मुद्दा डॉटसाफ्ट व्यवस्था में बगैर पते के बिल के मुद्दे के समान था जिसमें सेवाएँ, नेटवर्क तत्व में बनायी गईं परन्तु ग्राहक लेखा सूचना बिलिंग व्यवस्था में उपलब्ध नहीं थी। तीन माह पुरानी त्रुटी आई पी डी आर एस लगभग शून्य थी। खरबों आइ पी डी आर एस की तुलना में पर्यवेक्षित त्रुटि अंक नगण्य और मामूली था।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सॉफ्टवेयर समाधान में मात्रा महत्व नही रखती परन्तु कमियाँ गिनी जाती हैं। सी डी आर बिलिंग पैकेज एक व्यापक पैकेज है इसीलिए उपयोगकर्ता के लेखाओं को सी डी आर/आई पी डी आर एस में उचित लिंकेज़ प्रदान करते समय सावधानी बरती जानी चाहिये थी। सी डी आर आधारित बिलिंग लागू करने के पॉच वर्ष के बाद भी सही ग्राहको को पहचानने में और मास्टरलेस आई पी डी आर एस के बिलिंग करने के लिये सिस्टम को हस्तचलित हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष

भा सं नि लि ने सी डी आर आधारित बिलिंग और ग्राहक समाधान सेवा स्पर्धा के कारण नयी चुनौतियों का सामना करने, संचालन की लागत को कम करने, अधिक राजस्व वसूली, राजस्व रिसाव बिन्दुओं को

7 जहां सदस्य का बुनियादी विवरण बिलिंग मॉडयूल में उपलब्ध नहीं

8 पी2 पुराना संस्करण एवं पी3 नया संस्करण है

ढूढ़ँने और रोकने, इसके अतिरिक्त ग्राहको को दक्ष एवं प्रभावी सेवा देने के उद्देश्य से लागू किया था। लेखापरीक्षा ने योजना में कमियॉ देखी जिससे एम टी ई की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय ₹ 8.80 करोड़ हुआ, राजस्व गारंटी और गबन प्रबंधन सिस्टम को आंशिक लागू किया गया इसके अतिरिक्त आई पी डी आर एस के बिल जारी नही किए गए/देरी से बिल जारी किए गए। प्रबंधन को इन मुद्दों का समाधान और सी.डी.आर. बिलिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिये जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा उत्कृष्ट हो, राजस्व रिसाव बंद हो और राजस्व वसूली बढ़े, इसके अतिरिक्त बुनियादी और ब्राडबैंड सेवा को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

5.2 गैर भुगतान के बावजूद भी लीज्ड सेवाओं का विच्छेदन न करना

गैर सरकारी/निजी संगठनो द्वारा तीन वर्षो से अधिक के लिए बकाया के गैर भुगतान के बावजूद भी लीज्ड लाइन/सर्किटस चालू रखने के परिणामस्वरूप छः दूरसंचार परिमंडलो व एक दूरसंचार क्षेत्र में ₹ 223.99 करोड़ बकाया का संचयन हुआ।

लीज्ड सर्किटस एक समर्पित लिंक है जोकि एक ग्राहक को दो निश्चित जगह के बीच विशिष्ट उपयोग के लिये प्रदान की जाती है। भारतीय टेलीग्राफ नियम (आई टी आर)–501 के अनुसार लीज्ड लाइन/सर्किटस के लिये प्रारंभिक प्रथम वर्ष का अग्रिम किराया व स्थापना प्रभार मांग पत्र के माध्यम से वसूले जाते है तथा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक अग्रिम किराया परम्परागत माह में बिल में मांगा जाता है।

इसके अतिरिक्त भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने 2001 में निर्देश जारी किया जिसमें अपेक्षित था कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम किराये का मॉग पत्र जारी किया जाना था जिसका भुगतान कम से कम उस तिमाही की समाप्ति के सात दिन पहले होना था जिसके लिये भुगतान पहले से ही प्राप्त हो चुका है। उपयोगकर्ता उपयोग किये गये सर्किटस् हेतु यदि अग्रिम किराया भुगतान करने में असफल रहता है तो सुविधा का विच्छेदन किया जाना है। भा सं नि लि निगम कार्यालय बकाया राशि के समय पर संग्रहण व विच्छेदन आदि के लिये समय–समय पर निर्देशो को दोहराता रहा है और निर्देशित करता रहा है कि बिल तारीख के 21वें दिन तक भुगतान होना है जिसके बाद सात दिनों का समय देकर विच्छेदन का नोटिस देना है तथा सर्किटस विच्छेदन 35 से 40 दिनों में करना है।

एक टेलीकाम क्षेत्र[9] व छः टेलीकाम परिमण्डलों[10] के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जॉच (दिसम्बर 2014–मार्च 2015) में पाया गया कि 1854 मामलों के संबंध में लीज्ड सर्किटस 90 दिनों से 2697 दिनों (2001-02 से 2014-15) तक अग्रिम लीज्ड किराया प्रभार ₹ 399.38 करोड़ का (**अनुलग्नक–XXIII**) भुगतान नही किये जाने के बावजूद भी चलती रही।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (दिसम्बर 2014-मार्च 2015) परिमण्डल प्रबंधन व जिला दूरभाष ने तथ्यो की पुष्टि करते हुए निम्न उत्तर प्रस्तुत कियेः

- **महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल** – बकाया ग्राहको द्वारा विवाद उठाने के कारण था। सात दिन का नोटिस जारी करने के बाद विच्छेदन आदेश जारी किया जायेगा।

9 उत्तरी टेलीकॉम क्षेत्र

10 महाराष्ट्र, चैन्नई, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और गुजरात टेलीकाम परिमण्डल

- **चैन्नई दूरसंचार परिमण्डल** – उच्च प्रतियोगी वातावरण के परिप्रेक्ष्य को ध्यान मे रखते हुये बडे (कारपोरेट) ग्राहकों को विच्छेदन किये बगैर लगातार उनके देयक समाधान के लिये अनुस्मरण कराया जा रहा था।

- **कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल** – ग्राहकों द्वारा बकाया बिल विवादित किये गये थे और मुद्दों के समाधान के लिये ग्राहकों के साथ समन्वय बैठक होनी थी।

- **गुजरात और उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार परिमण्डल/जिला** : सत्यापन प्रगति पर है, कार्यवाही/रद्दीकरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

- **उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल** –राशि प्राप्ति के लिये ग्राहकों से पत्राचार किया जा रहा है और चूक कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाही की जायेगी।

- **उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र**– समाधान के द्वारा और चूककर्ता ग्राहकों को नोटिस जारी कर बकाया देयकों की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

भा सं नि लि प्रबंधन द्वारा यह उत्तर भी दिया गया (सितम्बर 2015) कि देय किराये के भुगतान न करने के लिये लीज्ड सर्किट स्व–विच्छेदन का प्रावधान सिस्टम में नही है।

मंत्रालय (अक्टूबर 2015) ने प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार किया तथा प्रबंधन के उत्तर को संलग्न किया। आगे यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद पॉच परिमण्डलों[11] में ₹ 175.39 करोड़ प्राप्त हो गये है। उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल एवं उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र के लिए वसूली की स्थिति वांछित थी।

मंत्रालय का उत्तर निश्चित करता है कि कार्पोरेट कार्यालय के अनुदेशों के बाद भी परिमण्डल नोटिस जारी करने तथा विच्छेदन सुनिश्चित करने में असफल रहे जिसके कारण तीन वर्षो से अधिक के लिये ₹ 223.99 करोड़ के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ।

यहाँ यह बताना जरूरी है कि इसी प्रकार का अवलोकन सी एम टी एस पोस्ट पेड कनेक्शनों के संबंध में थ्रस्होल्ड सीमा को लांघने पर सी ए जी के 2015 के प्रतिवेदन क्रमांक 20 में भी लिया गया था परन्तु उक्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि भा स नि लि आज की तारीख में लीज्ड सर्किटस के स्व विच्छेदन के लिये सिस्टम विकसित करने में सक्षम नहीं है।

5.3 शास्ति का परिहार्य भुगतान

मध्यप्रदेश परिमण्डल में भा सं नि लि द्वारा अद्योसंरचना स्थलों के अनुप्रयुक्त रख–रखाव से वाधारहित मोबाइल सेवा को प्रदान नही करने के कारण ₹ 22.27 करोड़ की शास्ति का परिहार्य भुगतान।

विशिष्ट ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रो में मोबाईल सेवा प्रदान करने के लिये यूनिवर्सल सेवा प्रदाता (यू स पी) के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) ने प्रशासक, यूनिवर्सल सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध (मई 2007) किया।

11 गुजरात, उत्तर प्रदेश (पूर्व), महाराष्ट्र, कर्नाटक, और चैन्नई टेलीफोन

अनुबंध के अनुच्छेद 2.3 भाग बी की वित्तिय शर्तों में अपेक्षित था कि किसी भी कारण से सेवा में दीर्धकालीन बाधा के कारण यू एस पी यथानुपात शास्ति का भुगतान करेगा। अनुच्छेद 2.4 के अनुसार यदि तिमाही में सात दिनो तक की अवधि की मोबाईल सेवा में बाधा है तो कोई शास्ति देय नहीं होगी यदि तिमाही में सेवा में बाधा सात दिनों से अधिक है तो शास्ति ₹ 500/- प्रतिदिन के हिसाब से देय थी और यदि तिमाही में सेवा में बाधा 45 दिनों से अधिक है तो शास्ति पूरी तिमाही के लिये देय थी।

भा सं नि लि ने अधोसंरचन प्रदाता (आई पी) के रूप में दूसरे यू एस पी से सेवा स्तरीय अनुबंध (एस एल ए) (अक्तूबर 2008) भी किया जिसमें अनुबंध (भाग–अ) अनुच्छेद 13 की धारा VIII (विशेष अनुदेश) के अनुसार चौबीस घंटे मोबाईल सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करानी थी।

मध्य प्रदेश (एम पी) दूरसंचार परिमण्डल के पास 933 साइट थी और भा सं नि लि मध्य प्रदेश परिमण्डल ने 930 साईट रेडियेट की थी जिसमें तीन यू एस पी (भा सं नि लि, आइडिया और रिलायंस) थे, 376 साइट में 2 यू एस पी (भा सं नि लि और आइडिया या रिलायंस) और 141 साइट पर भा सं नि लि अकेला यू एस पी था। उक्त प्रमाण यह दर्शाता है कि भा सं नि लि 930 साइट में दोनो यू एस पी के साथ–साथ आई पी भी था जिससे भा सं नि लि पर बाधारहित मोबाईल सेवा देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्तूबर 2012–अप्रैल 2015) कि मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल जून 2008 से दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान बाधारहित मोबाईल सेवा नहीं संधारित कर पाया और जिसके लिये दूरसंचार विभाग ने ₹ 19.57 करोड़ की शास्ति व ₹ 2.70 करोड़ ब्याज लगया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ में)

अवधि	मूल शास्ति की राशि	मूल पर ब्याज की राशि	कुल शास्ति
2008-09	395000	210930	605930
2009-10	1731500	629829	2361329
2010-11	24544000	5412491	29956491
2011-12	47842500	5675620	53518120
2012-13	78904500	12057491	90961991
2013-14	42324500	2964884	45289384
कुल	195742000	26951245	222693245

मध्यप्रदेश परिमण्डल ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि सेवा में बाधा के मुख्य कारण सुनिश्चित पावर सप्लाई की अनुपलब्धता, डीजल की अनुपलब्धता, डीजल जनरेटर सेटो में खराबी, उच्च ओपेक्स के कारण ग्रामीण व दूरदराज की प्राकृतिक छवि के साथ तीन से कम आपरेटर्स जोकि आर्थिक रूप से व्यवहारिक नही थे, बताये।

तथ्य यह रहा कि भा सं नि लि प्रबंधन बाधारहित मोबाईल सेवा प्रदान करने में असफल रहा जिसके कारण दूरसंचार विभाग को ₹ 22.27 करोड़ की शास्ति का भुगतान किया। इससे वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखने के साथ–साथ ज्यादा राजस्व प्राप्ति हेतु ग्राहक आधार बढ़ाने के लिये दीर्धकालिक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आगे, बाधारहित मोबाईल सेवा देना सुनिश्चित नहीं होने से मोबाईल ग्राहको को अच्छी व त्वरित सेवा प्रदान करने के निजी सेवा प्रदाता द्वारा दी गई चुनौती को पूरा करने का उद्धेश्य भी पूरा नहीं हुआ।

5.4 आई टी सी की बिक्री पर अनावश्यक सेवा कर का दायित्व

आई टी सी के उपयोग को सुनिश्चित करने, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के लिये बने थे भारत संचार निगम लिमिटेड विफल रहा। परिणामस्वरूप भा सं नि लि ने सेवा कर और उस पर दण्ड ₹ 5.40 करोड़ अवशोषित किया, इसके अतिरिक्त स्वयं को परिहार्य मुकदमेंबाजी में डाला।

भा सं नि लि का इण्डिया टेलिफोन कार्ड[12] (आई टी सी) पूर्वप्रदत्त वास्तविक कॉल करने वाला कार्ड है जिससे किसी भी भा सं नि लि फोन से लोकल/एस टी डी/आई एस डी कॉल कर सकते हैं और कार्ड में दर्शाये गये गुप्त (पिन) नम्बर से कॉल प्रभारित होना था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर आई टी सी कार्ड जो दूसरे राज्यों में बेचा गया उसमें सर्विस टैक्स का अंश था जबकि भा सं नि लि को जम्मू कश्मीर में सेवायें देने के लिये सर्विस टैक्स के भुगतान से छूट[13] थी। इसलिये भा सं नि लि को आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना था कि जो कार्ड जम्मू और कश्मीर के लिये हैं उनकी बिक्री और उपयोग केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में ही हों।

भा सं नि लि ने आई टी सी कार्ड जिनकों जे. एण्ड के. राज्य और देश के अन्य राज्यों में उपयोग किया जाना था की छपाई के लिये दो ई–पिन वितरकों[14] को नियुक्त (2007) किया। आई टी सी कार्ड पर जो प्रिन्ट क्रमबद्ध संख्या (पी एस एन), निजी पहचान संख्या (पी आई एन) और क्रम संख्या छपने थे उसे एन्क्रिप्टेड रूप में ई–पिन वितरक को दिया गया था और छपे हुए आई टी सी को राष्ट्रीय इंटरनेट बोन को आगे सेकण्डरी स्विचिंग एरिया (एस एस ए) को पूर्ति हेतु वितरित कर दिया गया था। भा सं नि लि के उप महाप्रबन्धक (प्रचालन) को भा सं नि लि के सर्विस कंट्रोल पाइंट (एस सी पी) लखनऊ से पिन जनरेट करना था और भा सं नि लि लखनऊ के उपमंडल अभियंता {इंटेलीजेंट नेटवर्क (आई एन) सेवा} द्वारा कार्ड का क्रियान्वन होना था। कार्डो की बिक्री सेकण्डरी स्विचिंग एरिया (एस एस ए) को भा सं नि लि के फ्रेन्चाइजी, एस टी डी/पी सी ओ होल्डर के माध्यम से तथा उसके क्षेत्राधिकार में ग्राहक सेवा केन्द्र द्वारा की जानी थी। एक बार बेचा गया कार्ड ग्राहक द्वारा किसी भी भा सं नि लि फोन से भारत में कहीं भी उपयोग किया जा सकता था।

आंध्रप्रदेश दूरसंचार परिमंडल व केरल दूरसंचार परिमंडल ने आई टी सी की बिक्री, विपणन व मुद्रण के लिये दो ई–पिन वितरक से कारपोरेट कार्यालय की ओर से अनुबंध हस्ताक्षरित किया (2007)। दोनों ई–पिन वितरकों ने जम्मू और कश्मीर परिमंडल से प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) न करने का वचन/अनुबंध निष्पादित किया और एक शपथपत्र भी दिया कि आई टी सी जो जम्मू कश्मीर के लिये बने हैं वह मौजूदा भा सं नि लि फ्रेंचाईजी के माध्यम से केवल जम्मू और कश्मीर में उनके द्वारा बेचे जायेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2014) कि भा सं नि लि को केन्द्रीय आबकारी इंटेलीजेन्स ने सूचित किया (मई 2009) कि आई टी सी जो जम्मू और कश्मीर के लिये बने थे वह फ्रेंचाईजी द्वारा सेवा कर के भुगतान के बिना हिमाचल प्रदेश व पंजाब परिमंडलों में बेचे जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब परिमंडलों में

12 आई टी सी ₹ 100, ₹ 200 और ₹ 500, के मूल्यवर्ग में उपलब्ध थे, 18 महीने की समाप्ति की अवधि के लिये किया था, क्रमशः तीन, चार, और पांच महीने के भीतर इस्तेमाल किये जाने थे।

13 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 64 के अनुसार

14 मैसर्स बालाजी वॉच एवं मोबाईल प्राइवेट लिमिटिड, नीलौर, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसर्स फैज़ल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पालकाकंद, केरल

जम्मू और कश्मीर के लिये बनाये गये आई टी सी की बिक्री के तथ्य की पुष्टि (जून 2009) लुधियाना एस एस ए द्वारा भी की गई। फिर भी भा सं नि लि ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। एस डी ई लखनऊ द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिये मुद्रित आई टी सी के विस्तृत विवरण प्रदान करने के आधार पर महानिदेशक केन्द्रीय आबकारी इंटेलीजेन्स {डी जी (सी ई आई)} ने पाया कि ₹ 24.00 करोड़ के 23,98,663 आई टी सी 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर परिमंडल द्वारा मुद्रित और बेचे गये थे उसमें से ₹ 22.50 करोड़ कीमत के 22,50,143 आई टी सी का उपयोग जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर हुआ। लेखापरीक्षा ने डीजी (सी ई आई) की रिपोर्ट में आगे पाया कि

- ई–पिन वितरक मैसर्स फैज़ल प्राईवेट लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर में आई टी सी के बिक्री व प्रमोशन के लिये मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स को अपने बड़े थोक व्यापारी के रूप में नियुक्त किया। ई–पिन वितरक ने 2008-09 व 2009-10 के दौरान ₹ 100 मूल्यवर्ग के 675000 व 100000 आई टी सी की प्रिंट व बिक्री की। यद्यपि मैसर्स फैज़ल प्राईवेट लिमिटेड ने डी जी (सी ई आई) को बताया कि ई–पिन वितरक ने ₹ 100 मूल्यवर्ग के 675000 आई टी सी मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचे थे, डी जी (सी ई आई) ने पाया कि मैसर्स फैज़ल प्राईवेट लिमिटेड से मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा केवल 95000 आई टी सी खरीदे गये थे। डी जी (सी ई आई) द्वारा यह भी बताया गया कि मैसर्स फैज़ल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मुद्रित आई टी सी जो कि जम्मू और कश्मीर के लिये थे मुख्यतः केरल व तमिलनाडु के आसपास उपयोग हो रहे थे।
- ई–पिन वितरक मैसर्स बालाजी वाच एण्ड मोबाइल प्राईवेट लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर में आई टी सी की बिक्री व प्रमोशन के लिये मैसर्स महावीर रेडियो को अपना बड़ा थोक व्यापारी नियुक्त किया। ई–पिन वितरक ने 2007-08 व 2008-09 के दौरान ₹ 100 मूल्यवर्ग के 195000 एवं 755000 आई टी सी का मुद्रण व बिक्री की थी। यद्यपि मैसर्स बालाजी वाच एण्ड मोबाईल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कुल 1172000 आई टी सी मुदित किये थे, थोक व्यापारी द्वारा ₹ 100 मूल्यवर्ग के केवल 135000 आई टी सी तथा ₹ 200 मूल्यवर्ग के 10000 आई टी सी खरीदे गये थे। डी जी (सी ई आई) द्वारा यह भी बताया गया कि मैसर्स बालाजी वाच एण्ड मोबाईल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिये मुद्रित किये गये आई टी सी मुख्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर उपयोग किये गये।

जम्मू और कश्मीर के लिये बनाये गये आई टी सी को दूसरे राज्यों में बेचने के कारण आई टी सी पर सेवा कर का संग्रहण नहीं किया गया। डी जी (सी ई आई) ने संग्रहण नहीं किये गये सेवा कर की राशि ₹ 2.88 करोड़ आंकी। आयुक्त केन्द्रीय आबकारी एवं कस्टम ने ₹ 2.69 करोड़ सेवा कर की मांग व लगायी गई शास्ति ₹ 2.69 करोड़ की भी पुष्टि की (मार्च 2012)। आयुक्त ने आगे बताया कि यदि ब्याज सहित सेवा कर ₹ 2.69 करोड़ का आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर भुगतान होता तो शास्ति की राशि ₹ 0.67 करोड़ होती। भा सं नि लि ने एक करोड़ रूपये कस्टम आबकारी सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रीब्यूनल (सी ई एस टी ए टी) को जमा किये (मार्च 2013) व अपील दायर की। अपील लंबित थी (अक्टूबर 2015)। इस सम्बंध में, निम्नलिखित पर्यवेक्षण किये गये हैं:

- आई टी सी कार्ड प्रिंट क्रमबद्ध संख्या (पी एस एन) के द्वारा पहचाने गये थे। चूँकि आई टी सी का क्रियान्वयन भा सं नि लि द्वारा किया गया था, कार्डों को क्रियान्वित करने के दौरान पर्याप्त

आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करना था जिससे जम्मू और कश्मीर के लिये बनाये गये आई टी सी का क्रियान्वयन केवल जम्मू और कश्मीर में ही होता। पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होने के कारण जम्मू और कश्मीर के लिये बनाये गये आई टी सी का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों में हुआ, जिससे सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ, शास्ति का आरोपण और परिहार्य मुकदमेबाजी हुई।

- ई–पिन वितरक के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार, जब तक भा सं नि लि के देयक पूरी तरह से अनुबंध के अनुसार भुगतान नहीं होते और भा सं नि लि उसके दावे पूर्ण किये गये हों या पूरा अदा किये गये हों या जब तक भा सं नि लि संतुष्ट होता कि फ्रेंचाईजी द्वारा अनुबंध की सेवा और शर्तें पूरी और उचित ढंग से निष्पादित की गई हो तब बैक गारंटी (बी जी) तक प्रभावशाली रहनी थी। जम्मू–कश्मीर के लिये बने आई टी सी को अन्य राज्यों में बेचने के मामले को मई 2009 में जब सूचित किया गया उस समय दोनों फ्रेंन्चाइजी की बैंक गारन्टी वैद्य थी। फिर भी भा सं नि लि द्वारा बैंक गारन्टी आगे बढ़ाने के लिये कोई शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी। मैसर्स बालाजी वाच एण्ड मोाबाइल प्राईवेट लिमिटेड की पांच लाख रूपये की बैंक गारन्टी 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुई जबकि मैसर्स फैज़ल ट्रेडर प्राईवेट लिमिटेड की एक करोड रूपये की बैंक गारन्टी 10 नवम्बर 2012 को समाप्त हुई। ई–पिन वितरकों की बैंक गारन्टी नहीं बढ़ाने के कारण भा सं नि लि को पूरा नुकसान सहना पड़ा अन्यथा कुछ नुकसान की वसूली ई–पिन वितरक से हो सकती थी।

- जैसा डीजी (सी ई आई) के आंकलन से स्पष्ट होता है, जम्मू कश्मीर के लिये बने 2398663 आई टी सी में से 2250143 आई टी सी दूसरे राज्यों में बेचे गये। इसलिये अनुबंध के अनुसार ₹ 2.49 करोड़ का फ्रेंचाईजी भुगतान किया गया कमीशन जो कि को आई टी सी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये दिया गया था, नियमानुसार नहीं था, क्योंकि विक्रेता ने अनुबन्ध के अनुसार आई टी सी को केवल जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं बेचा था।

भा सं नि लि ने यह बताते हुए उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय आबकारी इंटेलीजेन्स से दिसंबर 2010 में नोटिस प्राप्त होने के बाद भा सं नि लि जम्मू और कश्मीर परिमंडल ने ई–पिन वितरक के विरूद्व कार्यवाही प्रारम्भ की। मैनेजमेंट ने आगे बताया कि भा सं नि लि जम्मू और कश्मीर परिमंडल बैंक गारन्टी का अभिरक्षक नहीं था और वहां ऐसी कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी जो आई टी सी कार्ड के उपयोग के गंतव्य को जाँच सकें।

मंत्रालय ने उत्तर में (अक्टूबर 2015) यह बताया कि ई–पिन वितरक के साथ अनुबंध की अवधि के दौरान भा सं नि लि को कोई उल्लंघन संज्ञान में नहीं आया और एक बार उत्पाद/सेवा, ग्राहक को बेचे गये तो यह ग्राहक का कर्तव्य होता है कि सेवा/उत्पाद का उपयोग/खपत जमीन के कानून के अनुसार किया जाये। भा सं नि लि को ग्राहको द्वारा उल्लंधन करने के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा सं नि लि को तथ्यों की पूरी जानकारी थी कि आई टी सी कार्ड जो कि जम्मू और कश्मीर के लिये बना है, दूसरे राज्यों की तुलना में कम कीमत का होने के कारण दुरूपयोग होना संभावित था। आगे यद्यपि, जून 2009 में स्वयं एस एस ए लुधियाना ने जम्मू और कश्मीर के लिये बने

कार्ड के दुरूपयोग की पुष्टि की, कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गई तथा जम्मू और कश्मीर के लिये बने कार्डों का क्रियान्वयन देश के अन्य भागों में न हो सके, कोई आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित नहीं किया गया। तथ्य यह रह जाता है कि जम्मू और कश्मीर के लिये बने आई टी सी कार्ड का उपयोग उसी राज्य में सुनिश्चित करने में भा सं नि लि विफल रहा। परिणामस्वरूप सर्विस टैक्स के रूप में ब्याज और उस पर शास्ति का नुकसान हुआ इसके अतिरिक्त भा स नि लि ने अपने को परिहार्य मुकदमेबाजी में डाला।

5.5 टॉवर की शेयरिंग में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

कार्पोरेट कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार दूसरे ऑपरेटर के साथ टॉवर शेयरिंग में जहां जरूरत थी वहां भा सं नि लि अधोसंरचना उन्नयन में अपनी ओर से सक्रिय कार्यवाही करने में असफल रहा जिससे 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिये ₹ 2.83 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व को पैदा करने का अवसर गंवा दिया।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) के पास अपने मोबाइल प्रचालन के सुगम व आसान संचालन हेतु विभिन्न स्थानों पर टॉवर लगाने के लिये जगह उपलब्ध थी। भारत संचार निगम मिमिटेड ने परिचालन लागत कम करने व अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के उद्देश्य से निर्णय लिया (जनवरी 2009) कि वह अपने पैसिव अधोसंरचना[15] की अतिरिक्त क्षमता दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रदाताओं (शेयरिंग ऑपरेटर) के साथ सांझा करेगा। भा सं नि लि के कार्पोरेट कार्यालय ने परिमंडलों को सक्रिय कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये (मई 2009) और निर्देशों के अनुसार परिमंडल प्रमुखों को प्राधिकृत किया गया थाः

- कि वह शीघ्र उन्नयन के उद्देश्य के लिये अलग विशिष्ट समूह बनायें व दूसरे सेवा प्रदाताओं को भा सं नि लि की पैसिव अधोसंरचना साइटों को किराये पर दे;
- कि भा सं नि लि की शेयरिंग बढ़ाने हेतु जहाँ जरूरत हो उसके अनुसार आगे कदम उठायें जिसमें भा सं नि लि का राजस्व बढ़ सके;
- कि टॉवर में शेयर होने योग्य पैसिव अधोसंचरना तत्व जैसे बैटरी, पावर प्लान्ट डीजी सेट, सेल्टर/जगह आदि का उन्नयन कर;

भा सं नि लि निगम कार्यालय ने शेयर करने वाले ऑपरेटरों के साथ मास्टर सर्विस अनुबंध (एम एस ए) किया (सितम्बर/नवम्बर 2009) जिसमें अपेक्षित था कि साइट अनुबंध, शुरू होने कि तिथि से सात वर्षों की लॉक–इन–अवधि के साथ 10 वर्षों के लिये मान्य होगा। अनुबंध में आगे यह भी अपेक्षित था कि शेयर करने वाला ऑपरेटर लाक–इन अवधि के दौरान यदि छोड़ता है, तो शेयर करने वाला ऑपरेटर भा सं नि लि को सात वर्षों की अवधि तक का भविष्य के सभी देय किराया भुगतान करने के लिये उत्तरदायी था।

एम एस ए में आगे यह भी बताया गया था कि शेयरिंग ऑपरेटर को उपकरण लगाने से पहले निम्न विधि का पालन करना होगाः

15 पैसिव अधोसंरचनो में इलीमेंट वीटीएस के लिये माउटिंग एमटीन व टॉवर स्पेस समाहित है तथा पॉसिव उपकरण जैसे शेलटर, डीजी सेट, पावर प्लान्ट एयर कंडीशनर, अर्थिंग व वैटर बैंक भी समाहित है।

- दूसरे शेयरिंग ऑपरेटर से साइट अनुरोध की प्राप्ति पर, भा सं नि लि शेयरिंग ऑपरेटर को साइट प्रस्ताव के रूप में उस साइट अनुरोध की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति देगा।

- साइट प्रस्ताव की तिथि से एक सप्ताह के अंदर शेयरिंग ऑपरेटर सेवा आदेश जारी करेगा इसके बाद एक सप्ताह के अंदर भा सं नि लि द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

- भा सं नि लि द्वारा सेवा आदेश को स्वीकारना उसे वैध माना जायेगा व अनुबंध का भाग होगा। भा सं नि लि शेयरिंग ऑपरेटर को 30 दिनों के भीतर साइट रेडी फार इन्सटालेशन ऑफ इक्यूपमेंट (आर एफ आई ई) उपलब्ध करायेगा।

- शेयरिंग ऑपरेटर को आर एफ आई ई की तारीख से 15 दिनों की समयावधि उसके उपकरण लगाने/माउंट के लिये देनी होगी।

- चालू करने की तिथि आर एफ आई ई तिथि से 15 दिन मानी जायेगी और किराया चालू होने की तिथि से ऑपरेटर द्वारा देय होगा।

आठ परिमंडलों[16] में जनवरी 2015 से जून 2015 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया कि 297 साईट अनुरोध प्राप्त हुए थे एवं फरवरी 2010 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान सेवा आदेश जारी किये थे। यह पाया कि इन प्रकरणों में, सर्विस आदेश (एम एस ए के अनुच्छेद 6.4 व 6.5) को जारी करने की तिथी से 45 दिनों के अपेक्षित निर्धारित समय के विरूद्व, उपकरणों/अद्योसंरचना के उन्नयन व चालू करने में 643 (रेन्ज) दिनों की अवधि तक का विलम्ब था। आठ[17] परिमंडलों में 90 दिनों तक, 365 दिनों तक एवं 365 दिनों से अधिक विलम्ब के कारण ₹ 2.83 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परिमण्डल	टॉवर शेयरिंग में विलम्ब दिनों में (सेवा आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिनों के बाहर)			राशि (₹ करोड़ में)
		10 से 90	91 से 365	365 से ज्यादा	
1	आन्ध्रप्रदेश	9	0	0	0.03
2	बिहार	33	17	1	0.52
3	कर्नाटक	21	8	0	0.22
4	मध्य प्रदेश	16	1	0	0.05
5	महाराष्ट्र	105	28	6	1.40
6	उड़ीसा	23	23	1	0.58
7	तमिलनाडु	4	1	0	0.03
8	चेन्नई				
	कुल	211	78	8	2.83

16 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु

17 सभी परिमंडलों में इसकी जाँच की बिन्दू केवल आठ परिमंडलों मे ही इस पर टिप्पणी किये गये दूसरे परिमंडलों में महत्वपूर्ण राशि नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर परिमंडलों ने बताया कि टॉवर शेयरिंग में विलम्ब अधोसंरचना के उन्नयन जैसे बैटरी, पावर प्लांट, डी जी सेट आदि की समस्याओं तथा सिविल कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने के कारण थे।

तथ्य यह रह जाता है कि परिमंडलों ने अधोसंरचना के उन्नयन के लिए मुख्यालय के निर्देशों (मई 2009) का पालन नहीं किया। जैसा कि साइट की शेयरिंग में विलम्ब का कारण परिमण्डलों ने अधोसंचरना के उन्नयन में समस्याओं का सामना करने को बताया, भा सं नि लि ने साइट अनुरोध की प्राप्ति के तत्काल बाद अधोसंचरना का उन्नयन सुनिश्चित नहीं करने के कारण 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिये ₹ 2.83 करोड़ अतिरिक्त राजस्व पैदा करने की संभाावना खो दी। यह उस समय और अनिवार्य हो जाता है जबकि भा सं नि लि की वित्तीय स्थिति बहुत ठीक नहीं है।

5.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएँ इकं द्वारा अपने कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता व एल टी सी का अनियमित भुगतान

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएँ इकं (एन आई सी एस आई) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अर्न्तगत धारा 25 में बगैर फायदा वाली कम्पनी है जिसने अपने अधिकारियों जो कि राष्ट्रीय सूचना को केन्द्र से प्रतिनियुक्ति पर थे, को 2010-11 से 2013-14 के दौरान परियोजना प्रोत्साहन ₹ 2.11 करोड़, परिवाहन भत्ता ₹ 48.87 लाख, मकान किराया भत्ता ₹ 16.58 लाख व एल टी सी की प्रतिपूर्ति ₹ 1.90 करोड़ का भुगतान किया जो कि वित मंत्रालय/ कार्मिक विभाग व प्रशिक्षण /लोक उद्यम विभाग के निर्देशो के विरूद्व था।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रानिक विभाग (डी ई आई टी वाई), सूचना तकनीकी व संचार मंत्रालय के अर्न्तगत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएँ इकं (एन आई सी एस आई) की सार्वजनिक क्षेत्र कंम्पनी के रूप में कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत अगस्त 1995 में स्थापना की गई थी। एन आई सी, डी ई आई टी वाई के अर्न्तगत संलग्न कार्यालय है इसलिए एन आई सी के कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों व फायदे के लिए पात्र थे। लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिनांक 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन (ओ एम) के अनुसार सरकारी अधिकारी जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी पी एस ई) में प्रतिनियुक्ति पर है वह उनके मूल विभाग में मिलने वाले वेतन का नियमित आहरण करेगे। चूंकि एन आई सी एस आई में एन आई सी के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर थे उनके लिये उक्त निर्देश लागू होंगे। इसलिए एन आई सी एस आई में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मिलने वाले वेतन भत्तों व फायदे के लिये हकदार थे। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त निर्देशों के विरूद्ध एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को एन आई सी एस आई ने निम्न भुगतान किये जो कि सही नहीं थेः

i. **परियोजना प्रोत्साहन** – एन आई सी से एन आई सी एस आइ में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनिुक्ति भत्ता के अलावा परियोजना प्रोत्साहन का भुगतान किया। परियोजना प्रोत्साहन कम्पनी द्वारा अर्जित करने के बाद फायदे से संबंधित था जो मूल वेतन के साथ ग्रेड पे पर 15 प्रतिशत निश्चित था यदि कर के बाद फायदा ₹ 3 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50 करोड़ से कम होता एवं मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत यदि कर के बाद फायदा ₹ 50 करोड़ से अधिक होता। प्रोजेक्ट प्रोत्साहन की राशि ₹ 2.11 करोड़ का 2007-08 से 2013-14

के अवधि में भुगतान किया था। यह प्रोत्साहन डी पी ई के निर्देर्शो में कवर नही होता था इसलिए एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर आये एन आई सी एस आई के कर्मचारियो को देय नही था।

ii. **परिवहन भत्ता**– एन आई सी एस आई की सेवा नियमों के अनुसार, एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर आये उनके कर्मचारियों को परिवहन भत्ता निश्चित दर पर स्वीकार्य था जो कि ईंधन की निश्चित मात्रा के बराबर अथवा निश्चित दरों पर वास्तिविक उपभोग के सापेक्ष एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को देय मंहगाई भत्ता के साथ जो भी राशि कम हो देय थी। सेवा नियमों में यह छूट/संशोधन वित मंत्रालय/प्रशिक्षण व कार्मिक विभाग (डी ओ पी टी)/डी पी ई के बगैर अनुमोदन के किये गये थे जिससे जनवरी 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 48.87 लाख का अधिक/अनयिमित भुगतान हुआ।

iii. **मकान किराया भत्ता**–एन आई सी एस आई ने मकान किराया भत्ता (एच आर ए) के नियमो में छूट दी (मई 2006) जो कि जुलाई 2007 से प्रभावी थी और मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के स्थान पर एच आर ए मूल वेतन प्लस महगांई भत्ता प्लस प्रतिनियुक्ति भत्ता के प्रतिशत् के आधार पर एन आई सी एस आई में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को आहरण करने की अनुमति दी, जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों व प्रावधानों के विरूद्ध था। एन आई सी एस आई सेवा नियमों के अनुसार दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद व बैंगलोर के लिये मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता पर 30 प्रतिशत की दर पर देय था जबकि दूसरे शहरो में मूल वेतन महंगाई वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता की 22.5 प्रतिशत की दर से देय था। सेवा नियमो में यह छूट/संशोधन वित मंत्रालय/प्रशिक्षण व कार्मिक विभाग (डी ओ पी टी) डी पी ई की बगैर अनुमति के किये गये थे। प्रतिनियुक्ति भत्ता को एच आर ए में सम्मिलित करना तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिये लागू दरो से भिन्न दरो से भुगतान के कारण मार्च 2010 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान एच आर ए में ₹ 16.58 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

iv. **छुट्टी यात्रा रियायत** –एन आई सी एस आई के निदेशक मण्डल द्वारा सेवा नियमों का अनुमोदन किया गया (मई 2006) जिसमें बताया था कि एन आई सी के कर्मचारियों पर लागू एल टी सी के नियम एन आई सी एस आई के कर्मचारियों को उसी रूप में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए लागू होंगे। जैसा कि एन आई सी, डी ई आई टी वाई के अर्न्तगत सहचारी कार्यालय था, अतः एन आई सी के कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय एल टी सी के पात्र थे। एन आई सी एस आई ने सेवा नियमों में संशोधन (सितम्बर 2010) किया जो इस प्रकार था।

- भारत भ्रमण एल टी सी पर एन आई सी एस आई के कर्मचारियों की विदेश यात्रा स्वीकार्य थी जिसमें कर्मचारी के मुख्यालय से भारत में दूरस्थ बिन्दु के बराबर किराये की पात्रता थी। कर्मचारी को एल टी सी के लिये आवेदन देते समय भारत में दूरस्थ बिन्दु की घोषणा करनी थी। संशोधन के कारण एन आई सी एस आई के कर्मचारियो ने 41 प्रकरणों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान भारत में दूरस्थ बिन्दु पर बगैर वास्तविक भ्रमण किये काल्पनिक दावे प्रस्तुत किये।

- सी सी एस (एल टी सी) के नियमों के अर्न्तगत एयर इंडिया से यात्रा जरूरी थी किन्तु सेवा नियमों में ऐयर इण्डिया फ्लाइट से यात्रा जरूरी नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 26

प्रकरणों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान कर्मचारियों ने ऐयर इण्डिया फ्लाइट से यात्रा नहीं कि जबकि यात्रा भारत में ही की गई थी।

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आठ प्रकरणों में स्वयं की कार/टैक्सी में की गई यात्राओं के दावों को मान्य किया था जो कि सी सी एस (एल टी सी) नियमों के भी विरूद्ध थे।

एन आई सी एस आई ने ₹ 1.90 करोड़ के एल टी सी के दावे भारत से बाहर यात्रा के लिये तथा एयर इण्डिया द्वारा यात्रा (भारत के भीतर भी) न करने के लिए मान्य किये जो कि अनयिमित थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई/नवम्बर 2015) कि:

(अ) एन आई सी एस आई एक विशिष्ट स्थापना थी जिसमें उसके कंपनी सचिव को छोड़कर इसके सभी अधिकारी एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर हैं और वह बगैर किसी स्टेप अप के लगातार वही वेतन आहरण कर रहे थे जो वह एन आई सी में आहरित कर रहे थे। अधिकारियो की सूक्ष्म संख्या, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के लिये विकल्प दिया, के पास कार्य का भारी बोझ भी था जो एन आई सी एस आई की पुष्टि के साथ बढ़ रहा था। एन आई सी से पर्याप्त प्रतिभा को आकर्षित करने के लिये नियमों के अनुसार देय प्रतिनियुक्ति भत्ता के अलावा प्रोत्साहन का भुगतान, 'परियोजना प्रोत्साहन' नामक दक्षता प्रोत्साहन, जरूरी था और सेवा नियमों में आशिंक परिवर्तन कर उच्च दरों पर मकान किराया भत्ता व परिवाहन भत्ता सभी अधिकारियों को समान दर पर उनके साथ में काम करने को ध्यान में रखते हुये दिया गया था। एन आई सी जो कि एन आई सी एस आई के लिये कार्मिक का एक मात्र स्त्रोत था खुद ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा था।

(ब) एन आई सी एस आई के सेवा नियम एन आई सी एवं डी ई आई टी वाई दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों के गठित व डी ई आई टी वाई के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाले निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित थे, तथा सेवा नियमों मे पात्रता को प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों को जारी होने वाले ऑफर लेटर में भी दिखाया जा रहा था तथा जिसे एन आई सी को पृष्ठांकित किया गया था जिसे एन आई सी द्वारा स्वीकार किया गया था। एन आई सी एस आई में प्रतिभा को रोकने के लिये यह प्रोत्साहन जरूरी थे क्योंकि यहां पर भी निर्धारित से बहुत कम कर्मचारी थे।

(स) एन आई सी एस आई विगत वर्षों से डी पी ई को प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को देय भत्तों के बारे में उनके निर्देशों में एन आई सी एस आई की विशेष प्रकृति पर विचार करते हुये छूट के लिये लिखता रहा है क्योंकि यहां पर 100 प्रतिशत अधिकारी एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर है।

(द) डी पी ई ने बताया कि डी ई आई टी वाई जो मूल विभाग है के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान किया जायेगा और इस बीच एन आई सी एस आई अपने मूल संगठन एन आई सी व डी ई आई टी वाई द्वारा अभिपुष्टि किये अपने सेवा नियम को बनाने की प्रक्रिया में था।

(ई) डी ई आई टी वाई ने संबधित कर्मचारियों/अधिकारियों से अनियमित भुगतान की गई एल टी सी की राशि की वसूली के आदेश जारी किये (फरवरी 2015)। एन आई सी एस आई ने कर्मचारियों/स्टाफ को वसूली पत्र जारी किये (अप्रैल 2015)। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06 जून 2015 के द्वारा एन आई सी एस आई को निर्देशित किया कि कर्मचारियों को दिये गये एल टी सी की राशि की वसूली के लिये कोई जोर जबरदस्ती वाली स्टेप न ले। मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

निम्नलिखित कारणो से उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है:

- परियोजना प्रोत्साहन, परिवहन भत्ता, एच आर ए और एल टी सी के विदेश यात्रा के दावों का डी पी ई के दिशानिर्देशों के विरूद्ध भुगतान जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी पी एस ई) में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारी पैतृक विभाग में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन एवं भत्ते का नियमित आहरण करेंगे;
- भुगतान करने के पहले कर्मचारियों के मूल संवर्ग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नही किया गया;
- कर्मचारियो के ऑफर पत्र में यह लाभ नही दर्शाये थे;
- सेवा नियमो में छूट/संशोधन एम ओ एफ/डी ओ पी टी/डी पी ई की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर किये गये थे। लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के बाद ही भारत सरकार (डी ई आई टी वाई) को सेवा नियम अनुमोदन हेतु अग्रेषित किये गये थे।

5.7 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

लेखापरीक्षा के कहने पर बी एस एन एल के चार परिमण्डलों ने विक्रेता/दूसरे सेवा प्रदाता से ₹ 16.04 करोड़ के बकाया देयक वसूल किये।

मई 2002 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान चार दूरसंचार परिमण्डलों से सम्बंधित अभिलेखों की जांच प्रकट करती है कि बदले हुये एक्ट प्रभार, आई एम पी सी एस परियोजना पर अधिक भुगतान, बिद्युत बिलों का गैर–समायोजन और खराब बैटरी पर क्षतिपूर्ति की गैर–वसूली की राशि ₹ 20.34 करोड़ अभी तक वसूल की जानी थी जैसा कि **अनुलग्नक XXIV** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर सम्बन्धित परिमण्डलों द्वारा ₹ 16.04 करोड़ वसूले/समायोजित किये गये थे।

5.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–(वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्व प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्याँकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधी समिति (सी आ पी यू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चयनित नहीं किया गया था। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए अनुशंसा कीः

- पृथक–पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पीएसयू से सम्बन्धित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बंध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा
- समिति को संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सी ओ पी यू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक–पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) मे समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी हेतु स्वंय डी पी ई मे एक पृथक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तद्नुसार, अगस्त 2000 के बाद से सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी करने के लिए डी पी ई में एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों के भीतर भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के भीतर सीएजी लेखापरीक्षा अनुच्छेद और पी ए सी की अनुशंसाओं पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें। इस निर्णय (जुलाई 2010) को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एवं आई टी), दूरसंचार विभाग, के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड और मेसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से सम्बंधित वर्ष 2015 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि, सितम्बर 2015 की स्थिति में, 96 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में ए टी एन लम्बित थे, जिनमें से 13 अनुच्छेदों पर ए टी एन अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा परिशिष्ट-I में वर्णित है।

अध्याय-VI
सामान्य

6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही –(सिविल)

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, इनके सदन पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही दर्शाते हुए टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (एटीएन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की, कि मार्च 1996 से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के समस्त अनुच्छेदों पर एटीएन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के भीतर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पीएसी को एटीएन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2015 की अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि सितम्बर 2015 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत तीन विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और डीईआईटीवाई से सम्बन्धित 24 अनुच्छेदों में एटीएन लम्बित थे, जिनमें से 09 अनुच्छेदों मे एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा कि परिशिष्ट–II मे वर्णित है।

मीरा स्वरूप.

नई दिल्ली
दिनांक : 7 जनवरी, 2016

(मीरा स्वरूप)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 12 जनवरी, 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	2X1.75 मेगा हर्ट्ज	28.00	7.00
2	मुम्बई	160.00		28.00	7.00
3	केरल	60.00	2X6 मेगा हर्ट्ज	36.00	9.00
4	हरियाणा	60.00		36.00	9.00
5	पंजाब	60.00		36.00	9.00
6	कोलकाता	60.00		36.00	9.00
7	कर्नाटक	160.00		96.00	24.00
8	महाराष्ट्र	160.00		96.00	24.00
9	आन्ध्रप्रदेश	160.00		96.00	24.00
10	बिहार	15.00		9.00	2.25
11	असम	15.00		9.00	2.25
12	गुजरात	160.00		96.00	24.00
13	हिमाचल प्रदेश	15.00		9.00	2.25
14	जम्मू एवं कश्मीर	15.00		9.00	2.25
15	मध्यप्रदेश	60.00		36.00	9.00
16	उत्तर पूर्व	15.00		9.00	2.25
17	उड़ीसा	15.00		9.00	2.25
18	राजस्थान	60.00		36.00	9.00
19	तमिलनाडू	160.00		96.00	24.00
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60.00		36.00	9.00
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	60.00		36.00	9.00
22	पश्चिम बंगाल	60.00		36.00	9.00
	कुल	**1750.00**		**914.00**	**228.50**

अनुलग्नक - II
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स एयरसेल लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपा. तिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	2x6 मेगा हर्ट्ज	96.00	24.00
2	मुम्बई	160.00		96.00	24.00
3	केरल	60.00		36.00	9.00
4	पंजाब	60.00		36.00	9.00
5	कर्नाटका	160.00		96.00	24.00
6	महाराष्ट्र	160.00		96.00	24.00
7	आन्ध्रप्रदेश	160.00		96.00	24.00
8	बिहार	15.00		9.00	2.25
9	गुजरात	160.00		96.00	24.00
10	हिमाचल प्रदेश	15.00		9.00	2.25
11	मध्य प्रदेश	60.00		36.00	9.00
12	उड़ीसा	15.00		9.00	2.25
13	राजस्थान	60.00		36.00	9.00
14	तमिलनाडू	160.00		96.00	24.00
15	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60.00		36.00	9.00
16	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	60.00		36.00	9.00
	कुल	**1,525.00**		**915.00**	**228.75**

अनुलग्नक - III
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स रिलाइन्स से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	2x6 मेगा हर्ट्ज	96.00	24.00
2	मुम्बई	160.00		96.00	24.00
3	कोलकाता	60.00		36.00	9.00
4	कर्नाटका	160.00		96.00	24.00
5	महाराष्ट्र	160.00		96.00	24.00
6	आन्ध्रप्रदेश	160.00		96.00	24.00
7	गुजरात	160.00		96.00	24.00
8	तमिलनाडू	160.00		96.00	24.00
	कुल	**1,180.00**		**708.00**	**177.00**

अनुलग्नक - IV
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	6 मेगा हर्ट्ज	48.00	12.00
2	मुम्बई	160.00		48.00	12.00
3	केरल	60.00		18.00	4.50
4	हरियाणा	60.00		18.00	4.50
5	पंजाब	60.00		18.00	4.50
6	कोलकाता	60.00		18.00	4.50
7	कर्नाटका	160.00		48.00	12.00
8	महाराष्ट्र	160.00		48.00	12.00
9	आन्ध्रप्रदेश	160.00		48.00	12.00
10	बिहार	15.00		4.50	1.13
11	असम	15.00		4.50	1.13
12	गुजरात	160.00		48.00	12.00
13	हिमाचल प्रदेश	15.00		4.50	1.13
14	जम्मू एवं कश्मीर	15.00		4.50	1.13
15	मध्यप्रदेश	60.00		18.00	4.50
16	उत्तर पूर्व	15.00		4.50	1.13
17	उड़ीसा	15.00		4.50	1.13
18	राजस्थान	60.00		18.00	4.50
19	तमिलनाडू	160.00		48.00	12.00
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60.00		18.00	4.50
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	60.00		18.00	4.50
22	पश्चिम बंगाल	60.00		18.00	4.50
	कुल	**1,750.00**		**525.00**	**131.25**

अनुलग्नक - V
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स ट्रैक ऑनलाइन लिमिटेड से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	2X1.75 मेगा हर्ट्ज	28.00	7.00
2	मुम्बई	160.00		28.00	7.00
3	कर्नाटक	160.00		28.00	7.00
4	तमिलनाडू	160.00		28.00	7.00
	कुल	**640.00**		**112.00**	**28.00**

अनुलग्नक - VI
(पैराग्राफ 2.2)
मैसर्स तुलीप से एक बार के प्रभार की वसूली नहीं किये जाने को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	2.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में 20 मेगा हर्ट्ज बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये रिजर्व मूल्य (2010)	3.3 गीगा हर्ट्ज आबंटित बैंड में (मेगा हर्ट्ज)	3.3 गीगा हर्ट्ज में 20 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य	3.3 गीगा हर्ट्ज बैंड में सितम्बर 2015 तक 5 वर्षों के लिये आबंटित बैडविथ का अनुपातिक मूल्य
1	दिल्ली	160.00	2x1.75 मेगा हर्ट्ज	96	24.00
2	केरल	60.00		36	9.00
3	हरियाणा	60.00		36	9.00
4	पंजाब	60.00		36	9.00
5	कर्नाटका	160.00		96	24.00
6	महाराष्ट्र	160.00		96	24.00
7	आन्ध्रप्रदेश	160.00		96	24.00
8	बिहार	15.00		9	2.25
9	असम	15.00		9	2.25
10	गुजरात	160.00		96	24.00
11	हिमाचल प्रदेश	15.00		9	2.25
12	जम्मू एवं कश्मीर	15.00		9	2.25
13	मध्यप्रदेश	60.00		36	9.00
14	उत्तर पूर्व	15.00		9	2.25
15	उड़ीसा	15.00		9	2.25
16	राजस्थान	60.00		36	9.00
17	तमिलनाडू	160.00		96	24.00
18	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60.00		36	9.00
19	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	60.00		36	9.00
	कुल	**1470.00**		**882**	**220.50**

अनुलग्नक - VII

(पैराग्राफ 2.3)

नये खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों पर किए गए व्यय को दर्शाता विवरण

व्यय	2013-14	2012-13
वेतन भत्ते	33639483	24283832
यात्रा भत्ता/परिवहन भत्ता	6077332	2520173
मेडिकल/एल टी सी/एल एस पी सी इत्यादि	4119572	5049880
अचंल सम्पति	700058	19227627
किराया व विद्युत प्रभार	20251221	22410765
विविध व्यय (कार्यालय व्यय)	1650374	1245129
कुल ₹	66438040	74737406
कुल योग ₹	**141175446 या 14.12 करोड़**	

अनुलग्नक - VIII
(पैराग्राफ 3.2)
बार कोडिड बैग लेबल की अधिप्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	परिमण्डल का नाम	पी एस डी का नाम	अधिप्राप्त लेबल की संख्या	लेबल का मूल्य	जिस अवधि में अधिप्राप्त किये गये
			(लाख में)	(लाख ₹ में)	
1	केरल	त्रिसूरए तिरवन्तपुरम और कालीकट	41.00	14.89	अगस्त से अक्तूबर 2012
2	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	57.00	20.20	नवम्बर 2012 से जनवरी 2013 और जनवरी–फरवरी 2015
3	पंजाब	लुधियाना	17.00	6.25	जुलाई 2012 से जनवरी 2015
4	हरियाणा	अम्बाला	22.18	7.99	जुलाई 2012 से मार्च 2013
5	हिमाचल प्रदेश	शिमला	12.00	4.82	दिसम्बर 2012
6	तमिलनाडू	चैन्नई, त्रिनुलेवली, कोयम्बटूर, त्रिची	38.38	14.03	जुलाई 2012 से नवम्बर 2013
7	मध्यप्रदेश		23.00	8.11	सितम्बर 2012 से जनवरी 2015
8	छत्तीसगढ़	रायपुर	3.13	1.18	
9	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, नागपुर, मुम्बई	46.42	17.70	सितम्बर 2012 से मार्च 2015
10	उड़ीसा	भुवनेश्वर	4'50	1.92	अगस्त 2012 से मार्च 2015
11	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	30.00	9.25	अगस्त 2013 से जून 2014
12	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर और अजमेर	69.30	24.18	अक्तूबर 2012 से मार्च 2014
13	दिल्ली	दिल्ली	33.00	11.68	अक्तूबर 2013
14	गुजरात	वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद	36.15	12.90	अगस्त 2012 से जनवरी 2015
15	बिहार	पटना	3.75	1.58	अगस्त 2012 से मई 2014
16	झारखण्ड	रांची	2.40	1.00	
17	कर्नाटक	बंगलौर, अरिशेकरी और हुबली	37.00	13.17	अक्तूबर 2012 से जनवरी 2013
कुल			**476.21**	**170.85**	

अनुलग्नक - IX

(पैराग्राफ 4.1.1.1 (क))

वर्ष 2005-06 के दौरान खरीदे गये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत का दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	विवरण	मात्राा	दर	कुल राशि
	नियत्रंण केन्द्र हेतु हार्डवेयर			
1	हाई एण्ड आर आई एस सी आधारित सर्वर	6	1838174	11029043
2	उपभोक्ता वर्कस्टेशन	30	40600	1218000
3	ए4 साईज कलर लेज़र प्रिन्टर	6	249000	1494000
4	ए0 साईज कलर रेस्टर प्लोटर	6	429905	2579430
	कुल			16320473
	नियंत्रण केन्द्र हेतु सॉफ्टवेयर			
1	विंडोज़ एक्स पी, ऑपरेटिंग सिस्टम (गलती से प्रतिष्ठापित)	30	0	0
2	ऑफिस एक्स पी	6	14830	88980
3	स्पेटियल ओरेकल मीडिया के उपभोक्ता लाइसेंस के साथ (प्रत्येक शहर)	6	376362	2258172
4	प्रत्येक शहर हेतु जी आई एस सॉफ्टवेयर	6	2208980	13253880
	कुल			15601032
	दूरस्थ केन्द्र के लिये सॉफ्टवेयर			
1	सर्वर मशींन	30	132796	3983880
2	उपभोक्ता वर्कस्टेशन	150	40600	6090000
3	ए0 साईज कलर रेस्टर प्लोटर	30	429905	12897150
	कुल			22971030
	दूरस्थ केन्द्र के लिये हार्डवेयर			
1	विंडोज़ एक्स पीए ऑपरेटिंग सिस्टम (गलती से प्रतिष्ठापित)	30	0	0
2	एक्स पी 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम	30	52113	1563390
3	स्पेटियल ओरेकल सॉफ्टवेयर (प्रत्येक शहर)	6	129260	775560
4	प्रत्येक शहर हेतु जी आई एस सॉफ्टवेयर	30	1588595	47657850
	कुल			49996800
1	पाइप व केबल लोकेटर	120	123779	14853480
2	फैरो मेगनेटिक लोकेटर	30	41189	1235670
	कुल			**16089150**
	कुल योग			**120978485**

अतः ₹ 12.10 करोड़

अनुलग्नक - X

(पैराग्राफ 4.1.1.1 (घ))

पुरानी निविदाओं के विस्तार के कारण अतिरिक्त व्यय के विस्तृत को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ रुपए में)

क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	बैण्डविथ	अवधि		प्रति एम बी पी एस प्रति माह अदा की गई दर	प्रति एम बी पी एस प्रति माह अनुमानित दर	प्रति एम बी पी एस प्रति माह अन्तर दर	बचत	सेवा कर (**06.02.11** से **08.06.11** तक **10.3**: और **09.06.13** से **08.06.14** तक **12.36%**)	कुल
			से	तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(6 - 7)	(3 * 8)		(9 + 10)
1	रिलाइन्स	3000	06-02-2011	28-02-2011	2208	1200	1008	2700000	278100	2978100
		3000	01-03-2011	31-03-2011	2208	1200	1008	3024000	311472	3335472
		3000	01-04-2011	30-04-2011	2208	1200	1008	3024000	311472	3335472
		3000	01-05-2011	10-05-2011	2208	1200	1008	975484	100475	1075959
		3000	11-05-2011	31-05-2011	1480	1200	280	569032	58610	627643
		3000	01-06-2011	08-06-2011	1480	1200	280	224000	23072	247072
2	टाटा टेलीकम्यूनिकेशन	4500	06-02-2011	28-02-2011	2208	1200	1008	3726000	383778	4109778
		4500	01-03-2011	31-03-2011	2208	1200	1008	4536000	467208	5003208
		4500	01-04-2011	30-04-2011	2208	1200	1008	4536000	467208	5003208
		4500	01-05-2011	09-05-2011	2208	1200	1008	1316903	135641	1452544
		4500	10-05-2011	31-05-2011	1480	1200	280	894194	92102	986295
		4500	01-06-2011	08-06-2011	1480	1200	280	336000	34608	370608
		वर्ष 2009 के लिये निविदा विस्तार पर अतिरिक्त व्यय						25861613	2663746	28525359

3	रिलाइन्स	9000	09-06-2013	30-06-2013	1020	554	466	3075600	380144	3455744
		9000	01-07-2013	31-08-2013	1020	554	466	8388000	1036757	9424757
		9000	01-09-2013	30-11-2013	1020	554	466	12582000	1555135	14137135
		9000	01-12-2013	28-02-2014	1020	554	466	12582000	1555135	14137135
		2000	10-01-2014	31-01-2014	1020	554	466	661419	81751	743171
		2000	01-02-2014	28-02-2014	1020	554	466	932000	115195	1047195
		11000	01-03-2014	31-05-2014	1020	554	466	15378000	1900721	17278721
		11000	01-06-2014	08-06-2014	1020	554	466	1366933	168953	,;jVsy
4	एयरटेल	9000	09-06-2013	30-06-2013	1020	554	466	3075600	380144	3455744
		9000	01-07-2013	31-08-2013	1020	554	466	8388000	1036757	9424757
		9000	01-09-2013	30-11-2013	1020	554	466	12582000	1555135	14137135
		9000	01-12-2013	28-02-2014	1020	554	466	12582000	1555135	14137135
		1000	20-01-2014	31-01-2014	1020	554	466	180387	22296	202683
		1000	01-02-2014	28-02-2014	1020	554	466	466000	57598	523598
		10000	01-03-2014	31-05-2014	1020	554	466	13980000	1727928	15707928
		1000	28-04-2014	30-04-2014	1020	554	466	46600	5760	52360
		1000	01-05-2014	31-05-2014	1020	554	466	466000	57598	523598
		11000	01-06-2014	08-06-2014	1020	554	466	1366933	168953	1535886
		वर्ष **2011** के लिये निविदा विस्तार पर अतिरिक्त व्यय						**108099473**	**13361095**	**121460568**
कुल अतिरिक्त व्यय								**133961086**	**16024841**	**149985927**

अतः ₹ 12.10 करोड़

अनुलग्नक - XI

(पैराग्राफ 4.1.1.1 (म),

एस एम एस प्रभार पर किये गये परिहार्य व्यय के विस्तृत को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बिल अवधि	एस एम एस की कुल संख्या	टाटा को प्रति एस एम एस भुगतान राशि	भा सं नि लि द्वारा प्रति एस एम एस प्रस्तावित राशि	परिहार्य व्यय	सेवा कर	कुल परिहार्य व्यय
1	23-03-2011 से 22-04-2011	238119	0.07	0.17	-23332	-2403	-25735
2	23-04-2011 से 22-05-2011	372413	0.07	0.11	-13931	-1435	-15366
3	23-05-2011 से 22-06-2011	457623	0.07	0.09	-7966	-820	-8786
4	23-06-2011 से 22-07-2011	601154	0.07	0.048	13225	1362	14587
5	23-07-2011 से 22-08-2011	1643765	0.065	0.048	27944	2878	30822
6	23-08-2011 से 22-09-2011	1456592	0.065	0.048	24762	2550	27312
7	23-09-2011 से 22-10-2011	3305131	0.065	0.048	56187	5787	61974
8	23-10-2011 से 22-11-2011	2026177	0.065	0.048	34445	3548	37993
9	23-11-2011 से 22-12-2011	10974964	0.05	0.025	274374	28261	302635
10	23-12-2011 से 22-01-2012	5387232	0.065	0.035	161617	16647	178264
11	23-01-2012 से 22-02-2012	18790629	0.05	0.025	469766	48386	518152
12	23-02-2012 से 22-03-2012	15258551	0.05	0.025	381464	39291	420755
13	23-03-2012 से 22-04-2012	14990709	0.05	0.025	374768	38601	413369
14	01-05-2012 से 22-05-2012	12895649	0.069	0.025	567409	70132	637541
15	23-05-2012 से 22-06-2012	24700186	0.069	0.02	1210309	149594	1359903
16	23-06-2012 से 16-07-2012	18875280	0.069	0.025	830512	102651	933163
17	17-07-2012 से 16-08-2012	20855613	0.069	0.02	1021925	126310	1148235
18	17-08-2012 से 16-09-2012	27880796	0.069	0.02	1366159	168857	1535016
19	17-09-2012 से 16-10-2012	48809185	0.069	0.02	2391650	295608	2687258
20	17-10-2012 से 16-11-2012	42929499	0.069	0.02	2103545	259998	2363543
21	17-11-2012 से 16-12-2012	41560105	0.069	0.02	2036445	251705	2288150
22	17-12-2012 से 16-01-2013	40695945	0.069	0.02	1994101	246471	2240572
23	17-01-2013 से 16-02-2013	41346147	0.069	0.02	2025961	250409	2276370
24	17-02-2013 से 16-03-2013	41046392	0.069	0.02	2011273	248593	2259866
25	17-03-2013 से 16-04-2013	75746692	0.067	0.01	4317561	533651	4851212
26	17-04-2013 से 16-05-2013	163036105	0.063	0.01	8640914	1068017	9708931
27	17-05-2013 से 31-05-2013						
कुल					**32291087**	**3954649**	**36245736**

अतः ₹ 3.62 करोड़

अनुलग्नक - XII
(पैराग्राफ 4.2)
पाशान भवन परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

संशोधित परियोजना लागत		116.19
घटायाः वास्तिविक परियोजना लागत		49.80
परियोजना लागत में वृद्धि		66.39
घटाया :		
अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के कारण परियोजना लागत में वृद्धि	11.16	
निष्पादित मद की अतिरिक्त लागत	5.84	
वैधानिक और अन्य मद जिन पर आरंभिक प्राक्कलनों में विचार नहीं किया गया	9.61	
निविदाओं के कार्य क्षेत्र से छूटे हुऐ आन्तरिक कार्य	14.59	41.20
परियोजना लागत में कुल वृद्धि		25.19

स्रोतः डी ई आई टी वाई के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन और योजना आयोग मूल्याकंन नोट।

अनुलग्नक - XIII

(पैराग्राफ 4.2)

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक के दौरान सी–डैक पुणे के द्वारा किराये के परिसर पर किये जाने वाले /किये गये के किराये का व्यय दर्शाता विस्तृत विवरण

(राशि ₹ में)

किराये के परिसर का स्थान	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
एन एस जी आई टी पार्क	61051050	62407740	7697808	38191164	0	169347762
वेस्टइन्ड केन्द्र	0	0	0	64754679	101817576	166572255
पूणे विश्वविद्यालय भवन	3970800	6618000	6741600	6741600	6741600	30813600
कृषि कॉलेज भवन	242280	242280	242280	242280	242280	1211400
कुल	**65264130**	**69268020**	**14681688**	**109929723**	**108801456**	**367945017**

टिप्पणी:

1. किराये पर किये गये/ किये जाने वाले व्यय की गणना अनुबंध के नियम और शर्त्तों के आधार पर की गई है।
2. किराये पर व्यय में समय समय पर लागू सेवा कर शामिल है।
3. दिनांक 24.20.2009 से 31.3.2012 तक सेवाकर की दर– 10.30% (एस टी+ ई सी +एस एच ई सी)।
4. दिनांक 1.4.2012 के बाद सेवा कर की दर– 12.36% (एस टी+ ई सी + एस एच ई सी)।
5. जून–08 से सितम्बर–10 तक के दौरान एन एस जी आई टी पार्क में किराये पर लिया गया स्थान 57,474 वर्गफीट था और जून–08 से मई 2011 तक प्रतिमाह किराये पर ₹ 41,00,000 था और ₹ 47,15,000 सेवाकर के साथ में था। 10,200 वर्गफीट अतिरिक्त स्थान को अक्तूबर–12 से ₹ 9,50,000 सेवाकर के साथ से मासिक किराये पर लिया गया था।
6. एन एस जी आई टी पार्क के किराये पर लिये गये स्थान को सितम्बर 2013 तक खाली किया गया था।
7. वेस्टइन्ड केन्द्र के अन्तर्गत किराये पर लिये गये स्थान वर्गफीट में: 1–जून–13 – 29,190; 1–अगस्त–13– 32,438; 23–अगस्त–13– 78,393; 15 अक्तूबर–13– 80,374 और 1–दिसम्बर–13– 94,393;
8. वेस्टइन्ड केन्द्र के पट्टेदाता को देय किराया और रख रखाव प्रभार – ₹ 80 प्रति वर्गफीट एवं सेवाकर।
9. पुणे विश्वविद्यालय परिसर में किराये पर लिया हुआ स्थान – 18,626 वर्गफुट।
10. कृषि कॉलेज भवन कों किराये पर लिया हुआ स्थान–3,959 वर्गफुट और किराया प्रतिमाह ₹ 20,190/-।
11. किराये पर लिये गये भवन के लिये वर्तमान मासिक व्यय (मार्च 2015) ₹ 90.67 लाख है (वेस्टइन्ड केन्द्र –₹ 8484798; पुणे विश्वविद्यालय ₹561800; कृषि कॉलेज भवन–₹ 20,190) अथवा ₹ 3.02 लाख प्रतिदिन।

अनुलग्नक - XIV

(पैराग्राफ 4.3)

सी–डैक नोएडा का प्लाट बी–30, सेक्टर 60, नोएडा के लिए किऐ जाने वाले किश्त/ब्याज और वास्तव में किये गये भुगतान की तुलना को दर्शाता विवरण

लीज़ डीड के अनुसार शेष प्रीमियम भुगतान योजना					वास्तविक भुगतान		टिप्पणीयां
किश्तों की संख्या	देय तिथि	मूल धन (₹)	ब्याज @ 12% (₹)	किश्त की कुल राशि (₹)	भुगतान की तिथि	मूल धन राशि (₹)	
1	24.04.2001	825000	1485000	2310000	3.01.2002	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
2	24.10.2001	825000	1435500	2260500	3.01.2002	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
3	24.04.2002	825000	1386000	2211000	17.04.2002	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
4	24.10.2002	825000	1336500	2161500	22.10.2002	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
5	24.04.2003	825000	1287000	2112000	23.04.2003	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
6	24.10.2003	825000	1237500	2062500	10.10.2003	825000	मूल धन का भुगतान किया। ब्याज का भुगतान नहीं किया।
7	24.04.2004	825000	1188000	2013000	1.12.2003	19800000	शेष प्रीमियम के लिये एक मुश्त भुगतान
8	24.10.2004	825000	1138500	1963500	14.10.2011	20483150	ब्याज के लिये भुगतान
9	24.04.2005	825000	1089000	1914000	12.05.2014	7825550	ब्याज के लिये भुगतान
10	24.10.2005	825000	1039500	1864500	27.05.2014	3886790	शेष प्रीमियम के लिये पूर्ण और अन्तिम अदायगी भुगतान
11	24.04.2006	825000	990000	1815000	कुल	**56945490**	
12	24.10.2006	825000	940500	1765500			
13	24.04.2007	825000	891000	1716000			
14	24.10.2007	825000	841500	1666500			
15	24.04.2008	825000	792000	1617000			
16	24.10.2008	825000	742500	1567500			
17	24.04.2009	825000	693000	1518000			
18	24.10.2009	825000	643500	1468500			
19	24.04.2010	825000	594000	1419000			
20	24.10.2010	825000	544500	1369500			
21	24.04.2011	825000	495000	1320000			
22	24.10.2011	825000	445500	1270500			
23	24.04.2012	825000	396000	1221000			
24	24.10.2012	825000	346500	1171500			
25	24.04.2013	825000	297000	1122000			
26	24.10.2013	825000	247500	1072500			
27	24.04.2014	825000	198000	1023000			
28	24.10.2014	825000	148500	973500			
29	24.04.2015	825000	99000	924000			
30	24.10.2015	825000	49500	874500			
	कुल	**24750000**	**23017500**	**47767500**			

वास्तविक भुगतान	₹ 56945490
(–) भुगतान होना है	₹ 47767500
परिहार्य भुगतान	₹ 9177990

अनुलग्नक - XV
(पैराग्राफ 4.3)
ब्याज की हानि की गणना दर्शाता विवरण

01 दिसम्बर 2003 को सी–डैक द्वारा शेष प्रीमियम हेतु भुगतान की गई राशि (₹)	19800000
घटाएंरू दिनांक 01 दिसम्बर 2003 को सी–डैक द्वारा देय राशि (ब्याज और दण्डात्मक ब्याज के साथ) (₹)	10622916
सी–डैक द्वारा किया गया अधिक भुगतान (₹)	9177084

अवधि	एस बी आई के पी एल आर अनुसार ब्याज की दर (प्रतिशत में)	निधि राशि जिस पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता था' (₹)	ब्याज की राशि (₹)
24.10.2004 से 24.04.2005	10.75	9177084	493268
24.04.2005 से 24.10.2005	10.75	8352084	448925
24.10.2005 से 24.04.2006	10.75	7527084	404581
24.04.2006 से 24.10.2006	10.75	6702084	360237
24.10.2006 से 24.04.2007	11.00	5877084	323240
24.04.2007 से 24.10.2007	12.50	5052084	315755
24.10.2007 से 24.04.2008	12.50	4227084	264193
24.04.2008 से 24.10.2008	12.25	3402084	208378
24.10.2008 से 24.04.2009	13.00	2577084	167510
24.04.2009 से 24.10.2009	12.25	1752084	107315
24.10.2009 से 24.04.2010	11.75	927084	54466
24.04.2010 से 24.10.2010	11.75	102084	5997
		कुल	**3153865**

* मूल धन से कम की गई राशि अर्थात् प्रत्येक छः माह बाद ₹ 825000 जब अगली किश्त देय हो जाती है।

अनुलग्नक - XVI

(पैराग्राफ 4.4)

रियाती शुल्क दरों पर विधुत का लाभ न लेने के कारण सी–डैक पुणे द्वारा किये गये परिहार्य अतिरिक्त व्यय को दर्शाता विस्तृत विवरण– (पुणे विश्वविद्यालय भवन)

बिलिंग अवधि		उपयोग की गई इकाईयां	प्रति इकाई भुल्क दर भुगतान			प्रति इकाई देय औद्योगिक शुल्क दर			अन्तर प्रति इकाई	परिहार्य व्यय
से	तक		शुल्क दर	विद्युत शुल्क	कुल	शुल्क दर	विद्युत शुल्क	कुल		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (6-9)	11 (3x10)
										(राशि रूपये में)
25-मार्च-10	25-अगस्त-10	1080480	7.15	0	7.15	3.40	0	3.40	3.75	4051800
25-अगस्त-10	29-नवम्बर-10	698520	7.15	0	7.15	3.40	0	3.40	3.75	2619450
30-नवम्बर-10	08-अप्रैल-11	940560	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	2238533
09-अप्रैल-11	26-अगस्त-11	956400	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	2276232
27-अगस्त-11	21-नवम्बर-11	585840	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	1394299
22-नवम्बर-11	03-अप्रैल-12	965335	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	2297498
03-अप्रैल -12	21-मई-12	375655	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	894059
21-मई-12	21-जून -12	253015	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	602176
21-जून-12	20-जुलाई-12	239575	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	570189
21-जुलाई-12	20-अगस्त-12	223920	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	532930
21-अगस्त-12	20-सितम्बर-12	190800	7.65	0	7.65	5.27	0	5.27	2.38	454104
21-सितम्बर-12	20-अक्तूबर-12	208080	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	249696
21-अक्तूबर-12	20-फरवरी-13	730440	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	876528
21-फरवरी-13	01-मार्च-13	57600	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	69120
01-मार्च-13	01-अप्रैल-13	204240	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	245088
01-अप्रैल-13	01-मई-13	192480	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	230976

01-मई-13	01-जून-13	251880	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	302256
01-जून-13	01-जुलाई-13	197880	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	237456
01-जुलाई-13	01-अगस्त-13	210480	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	252576
01-अगस्त-13	01-सितम्बर-13	230280	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	276336
01-सितम्बर-13	01-अक्तूबर-13	238920	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	286704
01-अक्तूबर-13	01-नवम्बर-13	224280	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	269136
01-नवम्बर-13	01-दिसम्बर-13	205440	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	246528
01-दिसम्बर-13	01-जनवरी-14	189240	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	227088
01-जनवरी-14	01-फरवरी-14	212280	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	254736
01-फरवरी-14	01-मार्च-14	243480	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	292176
01-मार्च-14	01-अप्रैल-14	303120	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	363744
01-अप्रैल-14	01-मई-14	256800	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	308160
01-मई-14	01-जून -14	303000	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	363600
01-जून -14	01-जुलाई-14	327240	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	392688
01-जुलाई-14	01-अगस्त-14	326280	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	391536
01-अगस्त-14	01-सितम्बर-14	301680	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	362016
01-सितम्बर-14	01-अक्तूबर -14	283560	8.21	0	8.21	7.01	0	7.01	1.20	340272
पुणे विश्वविद्यालय भवन के संबंध में कुल अतिरिक्त परिहार्य व्यय										**24769686**

स्रोतः बिल/वाउचर जिसके माध्यम से सी–डैक द्वारा किराये के भवन के लिए पट्टेदाता को विधुत प्रभार का भुगतान किया गया था।

टिप्पणीः 1. रूढ़िवादी आधार पर औद्योगिक दरों पर देय शुल्क दर त्वरित फीडर/गैर– त्वरित फीडर लागू शुल्क दर से उच्चतर पर ली गई थी।

2. लागू विधुत कर के साथ औद्योगिक श्रेणी के अधीन भुगतान योग्य एवं शिक्षण संस्था श्रेणी (15–अगस्त–12 तक)/लोक सेवा श्रेणी (16–अगस्त–12) के अधीन भुगतान की गई शुल्क दर के मध्य अतंर पर परिहार्य व्यय की गणना की गई है।

3. सी–डैक द्वारा उपभोग की गई ईकाईयों की संख्या भू–स्वामियों द्वारा प्राप्त बिलों से तथा शुल्क दर भू–स्वामियों द्वारा प्राप्त किये गये एम एस ई डी सी एल बिलों से ली गई है।

अनुलग्नक - XVII

(पैराग्राफ 4.4)

रियायती विधुत शुल्क दरों का लाभ न लेने के कारण सी–डैक पुणे द्वारा किये गये परिहार्य अतिरिक्त व्यय को दर्शाता विस्तत विवरण

(एनएसजी आई टी उद्यान/वेस्टइन्ड केन्द)

बिलिंग अवधि		उपयोग की गई इकाईयां	प्रति इकाई शुल्क दर भुगतान			प्रति इकाई देय औद्योगिक शुल्क दर			अन्तर प्रति इकाई	परिहार्य व्यय	स्थान
से	तक		शुल्क दर	विद्युत शुल्क	कुल	शुल्क दर	विद्युत शुल्क	कुल			
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (6-9)	11 (3X10)	12
											(राशि रुपए में)
19/मार्च/10	17/अप्रैल/10	87761	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	436172	एन एस जी आई टी पार्क
17/अप्रैल/10	18/मई/10	100058	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	497288	एन एस जी आई टी पार्क
18/मई/10	17/जून/10	88271	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	438707	एन एस जी आई टी पार्क
17/जून/10	19/जुलाई/10	84111	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	418032	एन एस जी आई टी पार्क
19/जुलाई/10	20/अगस्त/10	80727	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	401213	एन एस जी आई टी पार्क
20/अगस्त/10	20/सितम्बर/10	76057	7.15	1.22	8.37	3.40	0	3.40	4.97	378003	एन एस जी आई टी पार्क
20/सितम्बर/10	20/अक्तूबर/10	89279	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	308013	एन एस जी आई टी पार्क
20/अक्तूबर/10	19/नवम्बर/10	76990	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	265616	एन एस जी आई टी पार्क
19/नवम्बर/10	21/दिसम्बर/10	82530	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	284729	एन एस जी आई टी पार्क
21/दिसम्बर/10	20/जनवरी/11	74736	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	257839	एन एस जी आई टी पार्क
20/जनवरी/11	18/फरवरी/11	72666	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	250698	एन एस जी आई टी पार्क
18/फरवरी/11	21/मार्च /11	87197	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	300830	एन एस जी आई टी पार्क
21/मार्च/11	20/अप्रैल/11	95741	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	330306	एन एस जी आई टी पार्क
20/अप्रैल/11	20/मई/11	99567	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	343506	एन एस जी आई टी पार्क
20/मई/11	19/जून/11	96408	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	332608	एन एस जी आई टी पार्क
19/जून/11	19/जुलाई/11	83082	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	286633	एन एस जी आई टी पार्क
19/जुलाई/11	20/अगस्त/11	85218	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	294002	एन एस जी आई टी पार्क
20/अगस्त/11	20/सितम्बर/11	81729	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	281965	एन एस जी आई टी पार्क
20/सितम्बर/11	18/अक्तूबर/11	83349	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	287554	एन एस जी आई टी पार्क
18/अक्तूबर/11	21/नवम्बर/11	92297	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	318425	एन एस जी आई टी पार्क
21/नवम्बर/11	21/दिसम्बर/11	94351	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	325511	एन एस जी आई टी पार्क
21/दिसम्बर/11	21/जनवरी/12	91102	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	314302	एन एस जी आई टी पार्क
21/जनवरी/12	20/फरवरी/12	74704	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	257729	एन एस जी आई टी पार्क
20/फरवरी/12	21/मार्च/12	88858	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	306560	एन एस जी आई टी पार्क
21/मार्च/12	20/अप्रैल/12	96358	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	332435	एन एस जी आई टी पार्क
20/अप्रैल/12	21/मई/12	96906	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	334326	एन एस जी आई टी पार्क

21/मई/12	31/मई/12	35408	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	122158	एन एस जी आई टी पार्क
31/मई/12	01/जुलाई/12	98918	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	341267	एन एस जी आई टी पार्क
01/जुलाई/12	01/अगस्त/12	86981	7.45	1.27	8.72	5.27	0	5.27	3.45	300084	एन एस जी आई टी पार्क
01/अगस्त/12	01/सितम्बर/12	69090	7.45	1.27	8.72	7.01	0	5.27	3.45	238361	एन एस जी आई टी पार्क
01/सितम्बर/12	01/अक्तूबर/12	86395	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	387914	एन एस जी आई टी पार्क
01/अक्तूबर/12	31/अक्तूबर/12	82675	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	371211	एन एस जी आई टी पार्क
31/अक्तूबर/12	30/नवम्बर/12	86149	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	386809	एन एस जी आई टी पार्क
30/नवम्बर/12	31/दिसम्बर/12	91038	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	408761	एन एस जी आई टी पार्क
31/दिसम्बर/12	31/जनवरी/13	88514	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	397428	एन एस जी आई टी पार्क
31/जनवरी/13	28/फरवरी/13	76677	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	344280	एन एस जी आई टी पार्क
28/फरवरी/13	31/मार्च /13	100871	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	452911	एन एस जी आई टी पार्क
31/मार्च/13	30/अप्रैल/13	103491	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	464675	एन एस जी आई टी पार्क
30/अप्रैल/13	31/मई/13	114485	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	514038	एन एस जी आई टी पार्क
31/मई/13	30/जनवरी/13	71373	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	320465	एन एस जी आई टी पार्क
30/जनवरी/13	31/जुलाई/13	64704	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	290521	एन एस जी आई टी पार्क
31/जुलाई/13	31/अगस्त/13	41724	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	187341	एन एस जी आई टी पार्क
31/अगस्त/13	31/जुलाई/13	54558	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	244965	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/जुलाई/13	31/अगस्त/13	67346	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	302384	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/अगस्त/13	30/सितम्बर/13	100847	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	452803	वेस्टइन्ड केन्द्र
30/सितम्बर/13	31/अक्तूबर/13	140573	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	631173	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/अक्तूबर/13	30/नवम्बर/13	129264	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	580395	वेस्टइन्ड केन्द्र
30/नवम्बर/13	31/दिसम्बर/13	132555	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	595172	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/दिसम्बर/13	01/फरवरी/14	132322	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	594126	वेस्टइन्ड केन्द्र
01/फरवरी/14	28/फरवरी/14	124535	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	559162	वेस्टइन्ड केन्द्र
28/फरवरी/14	31/मार्च /14	164614	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	739117	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/मार्च/14	30/अप्रैल/14	175800	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	789342	वेस्टइन्ड केन्द्र
30/अप्रैल/14	31/मई/14	186417	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	837012	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/मई/14	30/जून/14	164285	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	737640	वेस्टइन्ड केन्द्र
30/जून/14	31/जुलाई/14	135273	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	607376	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/जुलाई/14	31/अगस्त/14	123779	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	555768	वेस्टइन्ड केन्द्र
31/अगस्त/14	30/सितम्बर/14	146249	9.83	1.67	11.5	7.01	0	7.01	4.49	656658	वेस्टइन्ड केन्द्र
एन एस जी आई टी उद्यान/वेस्टइन्ड केन्द्र के संबंध में कुल अतिरिक्त परिहार्य व्यय										**22994319**	

स्रोतः बिल/वाउचर जिसके माध्यम से सी–डैक द्वारा किराये के भवन के लिए पट्टेदाता को विधुत प्रभार का भुगतान किया गया था।

टिप्पणीः 1. रूढ़िवादी आधार पर औद्योगिक दरों पर देय शुल्क दर त्वरित फीडर/गैर– त्वरित फीडर पर के रूप में लागू शुल्क दर से उच्चतर पर ली गई थी।

2. वाणिज्य शुल्क दर और औद्योगिक शुल्क दर के अन्तर से निकाला गया परिहार्य व्यय लागु विधुत प्रभारों के साथ ही भुगतान किया गया।

3. सी–डैक द्वारा उपभोग की गई ईकाईयों की संख्या भू–स्वामियों द्वारा प्राप्त बिलों से तथा शुल्क दर भू–स्वामियों द्वारा प्राप्त किये गये एम एस ई डी सी एल बिलों से ली गई है।

अनुलग्नक - XVIII
(पैराग्राफ 4.5)
सी–डैक पुणे के सभी कर्मचारियों को लीज्ड आवास सुविधा का विस्तार देने के कारण हुये अधिक भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल लीज़ किराया प्रभार का भुगतान	दो मुख्य कार्यकारियों के संबंध में देय लीज़ किराया प्रभार	अन्य कर्मचारियों का लीज़ किराया प्रभार वेतन+ ग्रेड पे का @ 40% भुगतान किया गया	वेतन + ग्रेड पे का @ 20% पर देय एच आर ए	अधिक भुगतान
1	2	3 (₹ 32000X2X12)	4 (2-3)	5 (4X50%)	6 (4-5)
2010-11	14015145	768000	13247145	6623573	6623572
2011-12	22575309	768000	21807309	10903655	10903654
2012-13	20251680	768000	19483680	9741840	9741840
2013-14	24505654	768000	23737654	11868827	11868827
2014-15	44375779	768000	43607779	21803890	21803889
कुल	**125723567**	**3840000**	**121883567**	**60941785**	**60941782**

स्रोतः सी–डैक पुणे के वार्षिक लेखे तथा सी–डैक के पत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं।

टिप्पणीः 1. दो मुख्य कार्यकारियों अर्थात् डी जी सी–डैक तथा ई डी सी–डैक के लिये लीज़ किराया प्रभार देय था क्योंकि पुणे इकाई ने महानिदेशक कार्यालय के लिए भी वेतन एवं भत्तों का आहरण किया था।

2. अधिक भुगतान की गणना लीज़ किराया प्रभार के आधे पर की गई है जो कि पुणे में 20 प्रतिशत एच आर ए की तुलना में मूल वेतन जमा ग्रेड पे का 40 प्रतिशत है।

अनुलग्नक - XIX

(पैराग्राफ 4.5)

सी–डैक पुणे द्वारा ग्रेच्युटी के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम सर्वश्री / श्रीमती	सेवा त्यागने की प्रकृति	ग्रहण करने की तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि तथा त्यागपत्र आदि	ग्रेच्युटी के लिए विचार की गई सेवा की अवधि वर्षों में	सेवा निवृत्ति आदि के समय मूल वेतन (छठे सी पी सी के अनुसार)	सेवा निवृत्ति आदि के समय ग्रेड वेतन	मंहगाई भत्ता	ग्रेच्युटी हेतु कुल वेतन	डी ए %	ग्रेच्युटी भुगतान	जी ओ आई ग्रेच्युटी नियम के अनुसार देय ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12	13	14 (12-13)
1	किशन अंबिका	अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति	15.09.1994	30.06.2013	19	13940	2800	13392	30132	80	302157	286254	15903
2	चन्द्रकांत शन्नाके	अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति	01.11.1995	30.06.2011	16	13660	4200	9109	26969	51	239714	215752	23962
3	एस.डी. केलकर	अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति	05.10.1999	31.10.2007	8	45670	8700	4893	59263	9	278049	237052	40997
4	जे.एस.आर.ए. प्रसाद	त्याग पत्र	23.05.2001	07.08.2006	5	18660	5400	481	24541	2	70791	0	70791
5	प्रेमलता के.	त्याग पत्र	15.01.2001	31.03.2006	5	20420	6600	0	27020	0	77942	0	77942
6	उदय आर. टाडे	अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति	11.10.1988	23.03.2008	19	45230	8700	6472	60402	12	662099	573819	88280
7	सिदेश टी.वी.	त्याग पत्र	01.11.2000	20.06.2006	6	19810	6600	0	26410	0	91419	0	91419
8	अरूण एम गोकाक	त्याग पत्र	04.12.2000	02.02.2007	6	19990	6600	1595	28185	6	97564	0	97564
9	महेता एस.डी.	त्याग पत्र	11.01.2000	30.06.2006	6	21360	6600	0	27960	0	97719	0	97719
10	अनिता राव	त्याग पत्र	01.01.2001	30.04.2007	6	20610	6600	1633	28843	6	99841	0	99841

11	प्रशान्त ए. नायर	त्याग पत्र	01.11.2000	22.12.2006	6	22480	6600	582	29662	2	102676	0	102676
12	राकेश वेन्डे	त्याग पत्र	14.12.2006	17.05.2012	5	19030	6600	16660	42290	65	105725	0	105725
13	महेश वी.	त्याग पत्र	15.12.1999	05.06.2007	7	22480	6600	1745	30825	6	124486	0	124486
14	अन्नापूरना ए. फर्रनैन्डीस	त्याग पत्र	01.08.1994	01.05.2006	12	13580	4600	0	18180	0	125862	0	125862
15	पलेश कर्माकर	त्याग पत्र	08.06.2006	31.07.2011	5	21270	6600	16165	44035	58	127024	0	127024
16	आन्नदा डी.	त्याग पत्र	03.07.1998	18.08.2006	8	23100	6600	594	30294	2	139819	0	139819
17	नवनीता मिर्जाकर	त्याग पत्र	02.03.1994	22.03.2007	13	14650	4600	1155	20405	6	153037	0	153037
18	चेस्टर डोमिनिक रैबेरियो	त्याग पत्र	01.10.2000	12.05.2009	9	23870	7600	6923	38393	22	199348	0	199348
19	राघवेन्द्र गुप्ता	मृत्यु	01.12.2008	18.05.2010	1	9629	0	3370	12999	35	251558	25998	225560
20	महेन्द्र कुमार पाण्डये	त्याग पत्र	20.06.1997	03.06.2007	10	38790	8700	2849	50339	6	251695	0	251695
21	डा. वी.सुन्दरर. ाजन	मृत्यु	02.04.1994	16.05.2011	16	50820	8900	30457	90177	51	1282025	1000000	282025
22	टी. जे. शानमुगम	त्याग पत्र	08.11.1996	12.07.2007	11	38790	8700	4274	51764	9	328503	0	328503
23	एस. वेंक्टेश	त्याग पत्र	18.04.1994	30.03.2007	13	39950	8700	2919	51569	6	387597	0	387597
24	मोहन राम	त्याग पत्र	01.06.1989	06.03.2008	19	47970	8900	6824	63694	12	698195	0	698195
कुल													**3955970**

स्रोतः सी–डैक पुणे द्वारा प्रस्तुत विवरण।

टिप्पणीः जी ओ आई के नियमानुसार देय ग्रेच्युटी की गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 15 दिनों के वेतन पर की गई है।

अनुलग्नक - XX

(पैराग्राफ 4.5)

सी–डैक पुणे द्वारा कर्मचारियों के ₹ 5000/- प्रति वर्ष से अधिक किए गए मानदेय भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ में)

क्रम संख्या	नाम	मानदेय भुगतान					
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	अजय भोजक	0	0	1000	0	0	1000
2	अमोल करमपुरवाला	0	41800	0	0	0	41800
3	अंशूल भट्ट	0	0	19905	3250	0	23155
4	अर्पणा भुते	0	0	40900	0	0	40900
5	आशीष कुवेलकर	174512	351335	261685	295800	267125	1350457
6	अतिऊर खान	83418	0	0	0	0	83418
7	अत्रेय दाण्डे	0	0	0	0	98612	98612
8	अवंती जोशी	0	0	0	0	16715	16715
9	चिन्मय बाहुलकर	0	0	19893	15973	14030	49896
10	चिन्मई मोहारीर	0	0	0	4031	8118	12149
11	दीपक चौधरी	0	0	8017	0	18306	26323
12	दीपांकर दीक्षित	0	0	0	6900	11708	18608
13	ध्रुव देसाई	0	0	101024	135817	148657	385498
14	डा. देबश्रेरी चक्रबर्ती दुबे	0	0	0	0	39850	39850
15	डा. वी. वेंकटेश शिनॉए	0	0	2000	0	0	2000
16	गौर सुन्दर	37833	0	0	0	0	37833
17	गौरव पालीवाल	0	0	31565	17592	7844	57001
18	गीतांजली गाद्रे	0	0	20346	21550	8500	50396
19	आई. प्रभु	0	0	2750	0	6050	8800
20	जहान्वी बोड़ान्कर	0	0	0	0	675	675
21	जावेद शेख़	0	0	29130	8500	0	37630
22	जीतेन्द्र म्हात्रे	0	0	0	0	350	350
23	जीतेश बाफ्ना	0	108806	56702	79351	118978	363837
24	केदार कुलकर्णी	0	0	0	0	23663	23663
25	कृष्णन गोपाल गुप्ता	0	0	0	0	7920	7920
26	कृष्णानाजन भट्टाचार्याजी	0	36250	0	0	0	36250
27	कुमार संजीव	0	0	0	0	20453	20453
28	मनीष चुघ	0	104750	0	0	0	104750
29	मनीषा मांत्री	0	0	0	0	5100	5100
30	मनोज चव्हान	0	0	0	17	5720	5737
31	मुदित माँकड़	0	0	0	0	11800	11800
32	नागेश वैद्य	0	0	2063	0	16575	18638
33	पी. आर. रंजीत रमन	0	81075	0	0	0	81075

34	परिक्षित गोडबोले	91489	164250	102872	114250	108400	581261
35	पवन कुरारिया	0	0	0	52138	265787	317925
36	प्रफुल्ल कोल्टे	0	41025	127442	127301	58725	354493
37	प्रशान्त बेन्दाले	0	0	0	1000	35425	36425
38	प्रशान्त सिहं सिशोदिया	0	0	14075	0	0	14075
39	प्रवीन सिंह रधुवंशी	0	162250	0	0	0	162250
40	राविन्द्र पाणिग्रहय	0	0	0	0	9800	9800
41	राम मारूत वेदप्रकाश अनेजा	0	0	5119	0	0	5119
42	रंजन कुमार दास	0	0	0	0	9950	9950
43	सचिन नानावती	0	51333	2000	0	0	53333
44	सलिल मिश्रा	0	0	7000	0	0	7000
45	संदीप अग्रवाल	0	0	0	2875	0	2875
46	संदीप जोशी	0	54119	0	0	0	54119
47	संदीप श्रीवास्तव	0	0	1000	0	0	1000
48	सतीश परदेशी	0	0	0	0	3100	3100
49	सवनीर कौर	0	0	0	0	34921	34921
50	शीला इक्सामबेकर	0	0	55200	0	0	55200
51	शैलन्द्र सिंह नरवारिया	0	0	74946	0	3250	78196
52	सुचेता पवार	0	0	0	10056	0	10056
53	सुहाश जिन्गड़े	0	39867	0	0	0	39867
54	सुनील लौंधे	0	0	0	0	21510	21510
55	स्वपनिल अवघाड़े	0	0	0	0	5650	5650
56	स्वपनिल बेल्हे	0	0	23215	54416	46136	123767
57	टी. एस. मुरूगेश प्रभु	0	0	787	6142	15620	22549
58	तरूण दीप कोहली	0	0	16575	14912	22788	54275
59	वी शिवकुमार	0	0	0	200	18750	18950
60	वीनु जोशी के	0	0	0	0	8638	8638
61	विशाल माने	0	0	8025	0	0	8025
62	योगेन्द्र अभ्यँकर	60750	43450	18925	45625	49375	218125
कुल		**448002**	**1280310**	**1054161**	**1017696**	**1574574**	**5374743**

अनुलग्नक - XXI
(पैराग्राफ 4.5)

अप्रैल 2013 से अक्तूबर 2014 के दौरान पवन दुग्गल एसोसिएटस् को सी–डैक पुणे द्वारा दिये गये परामर्श प्रभार को दर्शाता विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	बिल संख्या	बिल तिथि	बिल राशि	टी डी एस @ 10%	पूर्ण भुगतान	प्रदान की गई सेवा की प्रकृति	घंटों की संख्या	फीस प्रति घंटा
1	बी/सी–डैक/आर1/13	15/04/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
2	बी/सी–डैक/एएच1/13	18/04/2013	125000	12500	112500	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	5	25000
3	बी/सी–डैक/एएच1/13	15/05/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बी/सी–डैक/एएच2/13	18/05/2013	100000	10000	90000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	6	16667
5	बी/सी–डैक/आरटी1/13	18/05/2013	150000	15000	135000	माह अप्रैल 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 9 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	9	16667
6	बी/सी–डैक/आर3/13	14/06/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
7	बी/सी–डैक/एमएम1/13	26/06/2013	116664	11666	104998	सी सी एस (सी सी ए) नियम के नियम 10 पर सलाह	7	16666
8	बी/सी–डैक/एमएम2/13	26/06/2013	133336	13334	120002	सी सी एस (सी सी ए) नियम के नियम 14 पर सलाह	8	16667
9	बी/सी–डैक/एमएम3/13	26/06/2013	300000	30000	270000	आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 पर सलाह	18	16667
10	बी/सी–डैक/आरटी2/13	18/06/2013	233330	23333	209997	माह मई 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 14 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	14	16666
11	बी/सी–डैक/एएच3/13	18/06/2013	191670	19167	172503	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	11.5	16667
12	बी/सी–डैक/एमएम4/13	07/04/2013	275000	27500	247500	आई ई कार्यावाहियों में प्रजेन्टिग अधिकारियों के लिए टेम्पलेट के मसौदे बनाने पर सलाह	16.5	16667
13	बी/सी–डैक/आर 4/13	15/07/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं

14	बी/सी–डैक/आरटी3/13	20/07/2013	175000	17500	157500	माह जून 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 10.5 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	10.5	16667
15	बी/सी–डैक/एएच4/13	20/07/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	12	16667
16	बी/सी–डैक/एमएम5/13	29/07/2013	200000	20000	180000	भारतीय कोपीराइट अधिनियम ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को सुरक्षा और परिरक्षण पर सलाह	12	16667
17	बी/सी–डैक/आरटी4/13	08/01/2013	250000	25000	225000	माह जुलाई 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 15 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	15	16667
18	बी/सी–डैक/एमएम6/13	08/05/2013	200000	20000	180000	डाटा और सूचना के इलेक्ट्रानिक रूप में उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अपनाये जाने पर सलाह	12	16667
19	बी/सी–डैक/आर5/13	16/08/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
20	बी/सी–डैक/एएच5/13	18/08/2013	175000	17500	157500	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	10.5	16667
21	बी/सी–डैक/आर6/13	16/09/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
22	बी/सी–डैक/आर7/13	15/10/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
23	बी/सी–डैक/एएच6/13	18/09/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	12	16667
24	बी/सी–डैक/एएच7/13	18/10/2013	258332	25833	232499	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	15.5	16667
25	बी/सी–डैक/आरटी5/13	09/10/2013	91668	9167	82501	माह अगस्त 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 5.5 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	5.5	16667
26	बी/सी–डैक/आरटी5/13	20/10/2013	150000	15000	135000	माह सितम्बर 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 9 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	9	16667
27	बी/सी–डैक/एएच8/13	18/11/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	12	16667

28	बी/सी–डैक/आर8/13	15/11/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	10.5	19048
29	बी/सी–डैक/आरटी7/13	11/12/2013	275000	27500	247500	माह अक्तूबर 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 16.5 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	16.5	16667
30	बी/सी–डैक/आर9/13	16/12/2013	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
31	बी/सी–डैक/आरटी8/13	18/12/2013	133331	13333	119998	माह नवम्बर 2013 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 8 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	8	16666
32	बी/सी–डैक/एएच9/13	18/12/2013	116669	11667	105002	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	7	16667
33	बी/सी–डैक/आर10/14	15/01/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
34	बी/सी–डैक/आर11/14	14/02/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
35	बी/सी–डैक/आर12/14	14/03/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
36	बी/सी–डैक/एमएम डब्ल्यू1/14	04/02/2014	275000	27500	247500	कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में कर्मचारी जागरूकता पर सलाह (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013)	16.5	16667
37	बी/सी–डैक/एमएम डब्ल्यू2/14	04/07/2014	250000	25000	225000	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक मध्यस्थ के रूप में सी–डैक की भूमिका पर सलाह	15	16667
38	बी/सी–डैक/एमएम डब्ल्यू3/14	04/10/2014	250000	25000	225000	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक मध्यस्थ के रूप में सी–डैक द्वारा उठाये जाने वाले यथोचित परिश्रमी कदम पर सलाह	15	16667
39	बी/सी–डैक/एमएम डब्ल्यू1/14	15/4/2014	183330	18333	164997	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	11	16666
40	बी/सी–डैक/आरटी डब्ल्यू1/14	15/4/2014	166670	16667	150003	माह अप्रैल 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 10 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	10	16667
41	बी/सी–डैक/आर1ए/14	16/4/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं

42	बी/सी–डैक/एमएम डब्ल्यू4/14	05/10/2014	250000	25000	225000	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सी–डैक द्वारा अपनाये जाने वाले मानकों पर सलाह	15	16667
43	बी/सी–डैक/आरए2/14	19/5/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
44	बी/सी–डैक/आरटी आईडब्ल्यू 2/14	28/5/2014	83335	8334	75001	माह मई 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 5 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	5	16667
45	बी/सी–डैक/एएच डब्ल्यू2/14	28/5/2014	116665	11667	104998	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	7	16666
46	बी/सी–डैक/आरटी आईडब्ल्यू 3/14	06/01/2014	100000	10000	90000	माह मई–जून 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 6 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	6	16667
47	बी/सी–डैक /एएच डब्ल्यू3/14	06/01/2014	200000	20000	180000	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	12	16667
48	बी/सी–डैक /आरए3/14	17/6/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
49	बी/सी–डैक /आरटी आईडब्ल्यू4/14	07/05/2014	200000	20000	180000	माह जुलाई 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 12 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	12	16667
50	बी/सी–डैक /एएच डब्ल्यू4/14	07/05/2014	250000	25000	225000	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	15	16667
51	बी/सी–डैक/आरए4/14	17/7/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
52	बी/सी–डैक /एएच डब्ल्यू5/14	1/8/2014	200000	20000	180000	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	12	16667
53	बी/सी–डैक /आरटी आईडब्ल्यू5/14	16/8/2014	200000	20000	180000	माह अगस्त 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 12 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	12	16667
54	बी/सी–डैक /आरए5/14	18/8/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
55	बी/सी–डैक /एएच डब्ल्यू6/14	14/9/2014	166670	16667	150003	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	10	16667

56	बी/सी–डैक /आरटी आईडब्ल्यू6/14	14/9/2014	133330	13333	119997	माह सितम्बर 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 8 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	8	16666
57	बी/सी–डैक /आरए6/14	17/9/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
58	बी/सी–डैक /एमएम डब्ल्यू5/14	15/10/2014	158330	15833	142497	कम्प्यूटर आउटपुट तथा अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में भारत में बदलते कानून पर उच्चतम न्यायलय के निर्णय और इनकी सी–डैक पर प्रयोज्यता पर सलाह	9.5	16666
59	बी/सी–डैक /एएच डब्ल्यू7/14	15/10/2014	141670	14167	127503	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	8.5	16667
60	बी/सी–डैक /आरए7/14	17/10/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
61	बी/सी–डैक /आरए8/14	17/11/2014	200000	20000	180000	सी–डैक को प्रभावित करने वाले विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दे हेतु परामर्श शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं
62	बी/सी–डैक /आरटी आईडब्ल्यू7/14	20/11/2014	100000	10000	90000	माह नवम्बर 2014 में आर टी आई प्रश्नों हेतु सलाह पर 6 घंटों के लिये (अपील एवं सुनवाई सहित)	6	16667
63	बी/सी–डैक /ए एच डब्ल्यू8/14	20/11/2014	100000	10000	90000	सी–डैक के साथ विधि सम्मेलन हेतु अतिरिक्त परामर्श शुल्क	6	16667
कुल			**11775000**					

अनुलग्नक - XXII
(पैराग्राफ 4.7)
सरकारी राजस्व को भारत की समेकित निधि में गैर प्रेषण के कारण देय दण्डात्मक ब्याज को दर्शाता विवरणं

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	वर्ष	भारत की समेकित निधि में सरकारी राजस्व के गैर प्रेषण पर ब्याज			कुल
		ई आ टी एल कोलकाता	ई टी डी सी बंगलौर	ई टी डी सी जयपुर	
1	जनवरी 09-मार्च 09	--	46141	5427.85	
2	2009-10	--	202241	12370.26	
1	2010-11	479440	146400	4922.95	
2	2011-12	291143	662807	161856.75	
3	2012-13	716629	491378	40113.08	
4	2013-14	1393099	586967	36322.46	
5	2014-15	1123926	283629	25034.14	
कुल		**4004237**	**2419563**	**286047.49**	**6709847.49**

अनुलग्नक - XXII

लीज्ड सर्किट ग्राहकों से तीन साल से अधिक बकाया राशि को दर्शाता विवरण

(पैराग्राफ 5.2)

(₹ करोड़ में)

परिमण्डल का नाम	मामलों की संख्या	अवधि	बकाया राशि	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली राशि	शेष राशि
महाराष्ट्र	128	2011-12 से 2014-15	204.61	111.23	93.38
चैन्नई	510	2010-11 से 2014-15	94.74	59.27	35.47
कर्नाटक	297	2006-07 से 2014-15	4.56	3.58	0.98
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	319	2001-02 से 2014-15	5.86	0.44	5.42
गुजरात	293	2012-13 से 2014-15	1.64	0.87	0.77
उड़ीसा	---	2005-06 से 2014-15	22.28	---	22.28
उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, दिल्ली	307	2008-09 से 2014-15	65.69	---	65.69
	1854		**399.38**	**175.39**	**223.99**

अनुलग्नक - XXIV
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली दर्शाता विवरण
(पैराग्राफ 5.7)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परिमण्डल का नाम	विषय	अवधि	वसूली जाने वाली राशि	वसूली / रद्द राशि	शेष वसूली जाने वाली राशि
1	तमिलनाडू दूरसंचार परिमण्डल	डक्ट प्रभार की गैर बिलिंग	मई 2002 से मार्च 2015	1.32	0.84	0.47
2	पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमण्डल	विस्तार परियोजनाओं आई एम पी सी एस की कीमतों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अतिरिक्त भुगतान	फरवरी 2007 से मई 2014	12.78	12.78	0.00
3	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	दोषपूर्ण बिजली संयंत्रों और बैटरी पर अपव्यय	2008 से जुलाई 2013	3.48	1.52	1.96
4	महाराष्ट्र परिमण्डल	यू एस ओ साइटों पर एम एस ई डी सी एल को ऊर्जा प्रभार से व्यय का गैर–समायोजन	2008 से 2014	2.76	0.90	1.86
कुल योग				**20.34**	**16.04**	**4.30**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 के लिए दूरसंचार विभागए सं मं व सू प्रौ के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी का संक्षिप्त स्थिति।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	ए टी एन देय	अभी तक अप्राप्त	पत्र–व्यवहार के अंतर्गत
भारत संचार निगम लिमिटेड				
1	2000 की 6	2	शून्य	2
2	2001 की 6	2	शून्य	2
3	2002 की 3	1	शून्य	1
4	2002 की 6	1	शून्य	1
5	2003 की 5	6	शून्य	6
6	2004 की 5	2	शून्य	2
7	2005 की 5	3	शून्य	3
8	2006 (पी ए) की 9	1	शून्य	1
9	2006 की 13	7	शून्य	7
10	2007 की 12	9	शून्य	9
11	2008 की पी ए 9	1	शून्य	1
12	2008 की सी ए 10	1	शून्य	1
13	2008 की सी ए 12	8	शून्य	8
14	2009-10 की सी ए 25	10	शून्य	10
15	2009-10 की पी ए 27	1	शून्य	1
16	2009-10 की 9	1	शून्य	1
17	2010-11 (पी ए) की 10	2	शून्य	2
18	2011-12 की 3	7	1	6
19	2012-13 की 8	3	शून्य	3
20	2014 की 17	5	1	4
21	2015 की 20	9	9	शून्य
	कुल	**82**	**11**	**71**

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	ए टी एन देय	अभी तक अप्राप्त	पत्र–व्यवहार के अंतर्गत
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड				
1	1999 की 3	1	शून्य	1
2	2003 की 5	1	शून्य	1
3	2004 की 5	2	1	1
4	2005 की 5	1	शून्य	1
5	2006 की 13	1	शून्य	1
6	2007 की 10	1	शून्य	1
7	2007 की 12	3	शून्य	3
8	2008 की सी ए 12	1	शून्य	1
9	2009-10 की सी ए 25	1	शून्य	1
10	2009-10 की 9	1	1	शून्य
11	2012-13 की 8	1	शून्य	1
	कुल	**14**	**2**	**12**
कुल योग		**96**	**13**	**83**

परिशिष्ट - II

सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं व सू प्रौ मं) के अन्तर्गत विभागों से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति

क्रण संण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	ए टी एन देय	अभी तक अप्राप्त	पत्र–व्यवहार के अंतर्गत
डाक विभाग				
1	2014 की 17	2	शून्य	2
2	2015 की 20	5	शून्य	5
	कुल	7	**शून्य**	7
दूरसंचार विभाग				
1	2004 की 2	2	शून्य	2
2	2006 (एन टी आर) की 9	1	शून्य	1
3	2014 की 17	3	शून्य	3
4	2015 की 20	8	4	4
	कुल	14	4	10
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
1	2006 की 12	1	शून्य	1
2	2014 की 17	1	शून्य	1
3	2015 की 20	1	1	शून्य
	कुल	**3**	**1**	**2**
कुल योग		**24**	**5**	**19**

शब्दावली

बी डब्ल्यू ए	ब्राडबैंड बेतार पहुंच ऐसी प्रौद्योगिकी है जो लोगों को व्यापक क्षेत्र में उच्च गति बेतार इंटरनेट पहुंच अथवा कम्प्यूटर नेटवर्किंग पहुंच उपलब्ध कराती है।
सी–डैक	एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग के विकास का केन्द्र
सी–मैट	इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी के लिये सामग्री का केन्द्र
डी पी ई	सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी पी एस ई के लिये नोडल एंजेंसी का कार्य करता है और अर्थव्यवस्था में पी एस ई की भूमिका से संबंधित नीति–निर्माण में सहायता करती है जो कि निष्पादन सुधार व मूल्यांकन, वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबन्धन व संबंधित क्षेत्रों में दिशानिर्देश–निति का निर्धारण भी करती है। यह एकत्र करती है, मूल्यांकन करती है तथा पी एस ई के संबंध में कई क्षेत्रों में सूचना रखती है। डी पी ई प्रशासकीय मंत्रालयों व पी एस ई के मध्य इंटरफेस भी उपलब्ध कराती है।
ई जी ओ एम	सशक्त मंत्री समूह
ई आर एन ई टी	ई आर एन ई टी इंडिया राष्ट्रीय अनुसंधान व शिक्षा नेटवर्क है जो कि देश में अनुसंधान व शिक्षा समुदाय की आवश्यकतायों को सर्मथन करने हेतु समर्पित है। यह इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है तथा 1998 में स्थापित की गई थी।
जी एस एम	मोबाइल कम्यूनिकेशन के लिये ग्लोबल सिस्टम एक डिजिटल मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम हे जिसका व्यापक उपयोग यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में किया जाता है।
आई ओ बी ए एस	इंटर ऑपरेटर बिलिंग व लेखा प्रणाली
एम जी उल अरी ई जी एस	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कि एम जी एन आर ई जी अधिनियम 2005 के तहत शुरू हुई थी जोकि जीवन–यापन सुरक्षा बढ़ाने, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर को जिसके स्वैच्छिक वयस्क सदस्य को दक्षता रहित हस्तचालित कार्य करने हेतु कम से कम 100 दिन का रोजगार भत्ता देना है।
एन आर एस ए	हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेन्जी स्पेस स्पान्सर्ड संगठन विभाग है जो रिमोट सेनसिंग डेटा के अधिग्रहण, संसाधन व के लिये समर्पित है। प्राथमिक रूप से डेटा भारत की अपनी आई आर 1-ए एस आई व 1बी द्वारा तथा अन्य देशों जैसे यू एस ए के लैंडसैट से संबंधित सैटेलाइट द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।
खण्ड 25 कम्पनी	सैक्शन 25 भारत में अलाभकारी संगठन के लोकप्रिय फार्म में से एक है। सैक्शन 25 कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन है जो वाणिज्य, कला, धर्म, दान व कोई अन्य उपयोगी वस्तु को बढ़ावा देने के लिये निर्मित हे।
वाई मैक्स	माईक्रोवेव एसेस के लिये विश्वव्यापी इंटरोपेराबिलिटी बेतार संचार का एक परिवार हे जिसे 30 से 40 मैगाबिट प्रति सैंकेन्ड दरों जिसको स्थिर स्टेशनों के लिये 1 गीगा बिट तक 2011 अद्यतन करके उपलब्ध कराया गया था, के साथ प्रारम्भिक डिज़ाइन तैयार किया गया है।
डब्ल्यू एल एल	वायरलेस इन लोकल लूप

© भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in